हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

07 मार्च, 2017 (प्रथम बैठक)

खण्ड–1, अंक–8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 07 मार्च 2017 (प्रथम बैठक)

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	3
हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण का अभिनन्दन	5
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	6
हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव का अभिनन्दन	23
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	36
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	39
विभिन्न मामले उठाना	42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
डिजिटल इंडिया अभियान से संबंधित	66
वक्तव्य–	
मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित	67
वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	69
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन	84
वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	84
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन	107
वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	107

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 07 मार्च, 2017 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कवंर पाल) ने अध्यक्षता की।

———

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन जन–स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल के भाई श्री राम अवतार जी के कल 6 मार्च, 2017 को हुये आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

यह सदन दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक श्री संतोष तिवारी के कल पी.जी.आई. में हुये आकस्मिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं तथा उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । मैं शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । मैं इस सदन की भावनायें शोक–संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा ।

अब मैं सदन से विनती करूंगा कि इन महान् आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है ।

Construction of Bus Stand in Ambala City

***1710. Shri Assem Goel. :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the Bus Stand of Ambala City is functioning under the temporary sheds for the last so many years; if so, the time by which new Bus Stand of Ambala City is likely to be constructed togetherwith the details thereof ?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, हाँ। सरकार द्वारा अम्बाला शहर में नया बस अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के आधार पर बनाने का निर्णय किया गया है जिसके लिए निविदाएं मांगी गई हैं जिनकी अन्तिम तिथि 28.03.2017 हैं। नए बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि अम्बाला शहर की चिरलम्बित मांग को स्वीकृत किया है । अम्बाला जिला हरियाणा का सबसे पुराना जिला है और सबसे पुराना रोडवेज डीपो होने के बावजूद पूरे देश के 600 से 650 जिलों में से अकेला ऐसा जिला था जिसका अपना बस–अड्डा नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इसकी प्रि–बिड की तारीख निकल चुकी है तो क्या किसी कम्पनी की तरफ से इसके लिए बिड आई है? दूसरी बात यह है कि आपने इसको बनाने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय की है क्या ये केवल बस–अड्डे के निर्माण का समय है या पूरे कम्पलैक्स का निर्माण समय है?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला शहर में नया बस–अड्डा पी.पी.पी. मोड में बनाया जायेगा । उसके लिए हमने टैंडर मांग लिये हैं और उसकी अंतिम तिथि 28.3.2017 है । हमने इसके निर्माण की समय सीमा 2 वर्ष रखी है तथा इस पर लगभग 204 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने रिवाड़ी का पुराना बस स्टैंड जो जीर्ण अवस्था में है उसको दूसरी जगह स्थानान्तरण करने के लिये और उसकी बिल्डिंग बनाने के लिये सदन में आश्वासन दिया था । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस बस स्टैंड के बारे में आज का क्या स्टेटस है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल अलग है फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि माननीय साथी ने पहले भी यह सवाल सदन में उठाया था और हमने इनको आश्वासन दिया था कि रिवाड़ी का जो बस स्टैंड है वह शहर के बीच में है । उसके स्थानान्तरण के लिये प्रपोजल अण्डर कंसीडेरेशन है और हम उसका सुधारीकरण करेंगे ।

श्री विक्रम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोसली में रोड़वेज का सब डिपो बनाने की घोषणा की थी । क्या वहां सब डिपो बनाना सरकार के विचाराधीन है ? अगर है तो उस पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाएगा ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणा में था और हमने उसकी ऐक्सरसाईज करवाई थी जिसमें उसकी नॉन फिजिबिलिटी पाई गई थी । इसलिये फिलहाल कोसली में सब डिपो बनाना विचाराधीन नहीं है ।

श्री विक्रम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में कोसली में सब डिपो बनाने की बात थी लेकिन रिवाड़ी के अन्दर कोई भी सब डिपो नहीं है । जबकि कोसली रेवाड़ी से 30 किलामीटर की दूरी पर पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : विक्रम जी, वैसे तो यह बिल्कुल अलग प्रश्न है फिर भी आपने जितना पूछा है उतना मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री विक्रम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि अलग प्रश्न है लेकिन वह तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है इसलिए उसके बारे में हमें यह तो पता चले कि वह सब–डिपो वहां पर बन रहा है या नहीं बन रहा है ।

श्री अध्यक्ष : विक्रम जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आपका प्रश्न बिल्कुल अलग है । अगर आप इसका प्रश्न लगाते तो तभी मंत्री जी इसका पूरा जवाब दे पाते । यह तो आपने वैसे ही थोड़ा सा पूछ लिया उतना ही मंत्री जी ने आपको बता दिया है क्योंकि सप्लीमैंट्री में तो इतना ही जवाब दिया जाता है ।

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री रण सिंह मान, भूतपूर्व सदस्य श्री भागीराम, श्री रामफल कुण्डू और श्री नफे सिंह राठी जी सदन की कार्यवाही देखने के लिये वी.आई.पीज. दीर्घा में बैठे हैं । हम सदन की तरफ से उन सबका स्वागत करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, मुझे याद है एक बार तो भागी राम जी ने हमें भी शपथ दिलवाई थी ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पेहवा का जो बस स्टैंड है वह बिल्कुल शहर के अन्दर आ गया है और नैशनल हाई–वे नम्बर 65 बनना भी शुरू हो चुका है जो पेहवा के पूर्व की तरफ से बन रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने वहां पर नये बस स्टैंड के लिये किसी जगह का चयन किया है ? अगर जगह का चयन किया है तो वहां पर कब तक वह बस स्टैंड बन जाएगा ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जितने भी बस स्टैंड शहर के बीच में आ गये हैं उनके लिये जैसे जैसे जगह उपलब्ध हो रही हैं हम उनको शहर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं । जैसे झज्जर में हमने 36 एकड़ जमीन में बस स्टैंड बनाया है और 268 करोड़ रूपये की लागत से हम करनाल के बस स्टैंड को बाहर जी.टी.रोड़ पर लेकर आए हैं । इस प्रकार से हमें जैसे–जैसे जमीनें उपलब्ध हो जायेंगी हम जो बस स्टैंड कंजस्टिड एरिया में हैं उनको शहर से बाहर निकालने का काम करेंगे ।

.....

Construction Of Under Pass

***1806. Sh. Pirthi Singh Namberdar. :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an under-pass in village Dhakal in Narwana Assembly Constituency on the main road of Hisar-Chandigarh; if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी; इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

श्री पिरथी सिंह नम्बरदार : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी 18 दिसम्बर को नरवाना में गये थे । बरौदा खुर्द और ढ़ाकल गांवों के लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम यहां अण्डर पास बनवा

देंगे । लेकिन आज तक उन आश्वासनों का कोई समाधान नहीं हुआ । ढ़ाकल गांव नरवाना के बिल्कुल नजदीक है । वहां के मजदूर और वहां की महिलाएं पीने का पानी नहर से लाती हैं जिनको आने–जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । इसी तरह बरौदा गांव में जब किसान अपने खेतों में जाते हैं तो उनका जैसे बिछपड़ा रोड़, बिखेवाला रोड़ और कलौदा रोड़ इन रोड़ज से बहुत आना–जाना भी है । वहां से लोगों का आवागमन बहुत ही ज्यादा है । इसलिये वहां अण्डर पास बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को जान माल की हानि से बचाया जा सके । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर अण्डर पास जल्दी बनवाया जाए नहीं तो वहां के लोग धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए हैं जिनको हमने भी वहां जाकर समझाया है लेकिन वह लोग वहां पर अण्डर पास न बनने तक धरने से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं । इसलिये जब तक वहां अण्डर पास नहीं बनेगा तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : पिरथी सिंह जी, मैंने आपकी बात का समर्थन कर दिया है ।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ढ़ाकल गांव नैशनल हाइवे नं0 65 पर पड़ता है और वहां पर फोर लेनिंग बनी हुई है । इसलिये क्रोस रोड़ की जितनी ट्रैफिक हैं उसका वोल्यूम बहुत कम है । लेकिन फिर भी यदि वहां अण्डर पास बनाना बहुत जरूरी है तो हम उसके लिये सरकार की तरफ से नैशनल हाई–वे मिनिस्टर को लिख सकते हैं ।

.....

To Fill Up The Vacant Posts in the Hospitals

***1793.Shri. Jasbir Deswal.:** Will the Health Minister be pleased to state -

(a) the steps taken by the Government to fill up the vacant posts in the district Hospitals;

(b) the steps taken by the Government to improve the immunity of the children; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the vaccination programme in each district of the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) चिकित्सा अधिकारियों के 662 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया षुरू कर दी गई है तथा पैरामैडिकल स्टाफ के 2828 पदों के लिए मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है।

(ख) टीकाकरण नियमित आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) हां , श्रीमान जी।

श्री जसबीर देसवालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न के (क) भाग कि जिला अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए है तथा (ख) भाग कि बच्चों की रोधक्षमता सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए है, के उत्तर से तो मैं सहमत हूँ लेकिन मेरे प्रश्न के (ग) भाग कि क्या राज्य के प्रत्येक जिले में टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाये?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, टीकाकरण एक नियमित कार्यक्रम है। 10 वैक्सीन प्रिवेंटेबेल डीजिज अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, डिपथेरिया, परटूशिश, टैटनस, हैपेटाईटिस–बी, हेमोफिलस इन्फलुएंजा टाईप–बी, पोलियो, मिजल, जापानीज एंजेफलिटिस, रोटा वॉयरस व डायरिया की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन करके सतत प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, रोटा वॉयरस वैक्सीन की मार्किट कॉस्ट 2200 रूपये है जबकि पूरे प्रदेश में इस वैक्सीन को सरकार की तरफ से बच्चों को फ्री में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त देशवाल जी के प्रश्न के (ग) भाग के संबंध में इतना ही बताना चाहूँगा कि सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष के इस वर्ष में अटल जीवन रक्षक नामक एक टीकाकरण योजना बनाई है, जिसके तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को न्यूमोनिया का वैक्सीन लगाया जायेगा क्योंकि न्यूमोनिया को इंफेंट मोरटेलिटी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रिस्पॉंसिबल माना जाता है।

.....

To Shift The Pipli Bus Stand

***1839. Shri Pawan Saini. :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Pipli Bus Stand; if so, the time by which the building of the said Bus Stand is likely to be constructed ?

Transport Minister (Shri Krishan Lal Panwar) : No, Sir.

डॉ पवन सैनीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिपली में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी। पटियाला, पेहवा की साईड से जब उत्तर प्रदेश को जाते हैं तो बीच में पिपली आता है जोकि एक बहुत बड़ा जंक्शन है। पिपली में इस समय एक छोटा सा छोटा सा बस अड्डा बना हुआ है। जी.टी.रोड़ पर उपरगामी पुल बनाये जाने की वजह से कोई भी वह बस जो दिल्ली से आती है, को पिपली बस स्टैंड पर आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया है बल्कि बस को पहले 7–8 किलोमीटर चंडीगढ़ की तरफ आना पड़ता है उसके बाद यू टर्न लेकर पिपली बस स्टैंड में एंट्री होती है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो बसिज लाडवा, यमुनानगर, सहारनपुर तथा हरिद्वार को जाती हैं, उन बसिज को पकड़ने के लिए भी सवारियां लाड़वा रोड़ पर खड़ी रहती हैं, तो इस परिपेक्ष्य में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और चूंकि पिपली में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अंतर्राज्यीय बस अड्डे बनाने संबंधी घोषणा भी है, को ध्यान में रखते हुए पिपली में एक बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाये तो निःसंदेह इससे मेरे इलाके के लोगों को बहुत राहत होगी और जहां तक वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से बस अड्डे के लिए जमीन एक्सचेंज करने संबंधी प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि वेयरहाउसिंग भी सरकार का ही एक अंग है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि यह अंतर्राज्यीय बस अड्डा पिपली में बन जाता है तो मंत्री जी यह मेरे क्षेत्र की जनता पर बड़ा उपकार होगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया है कि इनकी चिंता वाजिब है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरगामी पुल का निर्माण होने के पश्चात

दिल्ली की ओर से जो बसिज आती हैं, वह पिपली बस स्टैंड नहीं जा पाती है। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि पिपली में अंतर्राज्यीय बस अड्डे संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिपली बस स्टैंड के साथ वेयरहाउंसिग कारपोरेशन के गोडाउन की जमीन लगती है। अभी थोड़े दिन पहले वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की 75 फुट चौड़ी जमीन जिसका खसरा न. 454, 459 तथा 460 है और जो कुल मिलाकर 4400 गज जमीन बनती है, को लेने के लिए एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। वर्ष 2016 से राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। जैसे ही स्वीकृति मिल जायेगी तो 75 फीट की स्लीप रोड़ बनाकर लाडवा के मेन रोड़ की तरफ से पिपली बस स्टैंड में इंट्रैंस चालू करवा दिया जायेगा।

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग का वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के साथ पत्राचार वाली बात को तो लगभग 7–8 महीने हो गए हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा?

श्री अध्यक्षः पवन जी , मेरा ख्याल है कि मंत्री जी ने अपना उत्तर दे दिया है। सप्लीमैंटरी प्रश्न का मतलब यह होता है कि यदि कोई चीज क्लीयर नहीं हो रही है तो उस अवस्था में सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछा जा सकता है?

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि पत्राचार वगैरह में ज्यादा समय लग जायेगा। लोगों की असुविधा को देखते हुए मंत्री जी द्वारा मामले में गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर, इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

श्री नरेश कौशिक : अध्यक्ष जी, मेरे हलके के बहादुरगढ़ शहर का बस अड्डा इतना नीचा है कि झील की तरह हो चुका है । इसके अतिरिक्त वहां पर आये दिन जाम भी लगा रहता है । बहादुरगढ़ के सैक्टर–9 में बस अड्डा बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी कर रखी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बस अड्डा कब तक बन जाएगा ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह अनुपूरक प्रश्न बिल्कुल अलग है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ के बस अड्डे को बनाने की फाइल प्रोसैस में है और जल्द ही इस प्रयोजन पर कार्य शुरू हो जायेगा ।

.....

To Open Government Veterinary Dispensary / Hospital

***1972.Shri Om Parkash Yadav. :** Will Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Government Veterinary Dispensary/Government Veterinary Hospital in village Rasoolpur, Nangal and Dhana of Ateli Assembly Constituency?

कृषि मन्त्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : जी हां श्रीमान।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती संतोष यादव के विधान सभा क्षेत्र के तीन गांवों से संबंधित है । मैं माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश यादव को सदन में आश्वस्त करता हूं कि हम इन तीनों गांवों में पशु औषघालय खोल देंगे ।

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का यह आश्वासन देने के लिए धन्यवाद करता हूं । माननीय मंत्री जी ने हर साल एक गांव में पशु औषघालय खोलने की बात कही थी । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गांव मढ़वाला और ढ़ाणी बाढ़ोठा में पशु औषघालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । अगर हां, तो पशु औषघालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के विषय से पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदया के विधान सभा क्षेत्र अटेली के बारे में प्रश्न पूछा है । अतः जो व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है हमें भी उसके भले में ही सोचना पड़ता है । अगर ये दोनों गांव पशु औषघालय के नॉर्म्स पूरा करते हैं तो हम वहां पर पशु औषघालय अवश्य खोल देंगे ।

.....

To Replace Obsolete Conductors of Electricity.

***1899. Shri Naseem Ahmed. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity conductors from the Malab, Dehana, Devla, Jaisingpura, Mevali, Ghasera, Shakras, Biva, Pathkori, Doha, Omra, Rithad, Bhadas, Nagina, Ghaghas, Jalalpur villages in Mewat area of Nuh District; if so, the time by which these conductors are likely to be replaced?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पंवार) : श्रीमान जी, नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में तारों को आवश्यकतानुसार समय–समय पर बदला जाता है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नूंह जिले के मेवात क्षेत्र के गांवों मेलाब, देहाना, देवला, जयसिंहपुरा, मेवली, घसेरा, शाकरास, बीवा, पथकौड़ी, दोहा, ओमरा, रिथाड़, भादस, नगीना, घाघस, जलालपुर में बिजली की तारों की हालत बहुत ही खराब है । इस वजह से वहां कई बार हादसे भी हो जाते हैं । कुछ दिन पहले गांव खेड़ा में बिजली की लाइन से टच होने के कारण 8 महिलाओं की मौत हो गई थी । वहां इस तरह के और भी कई हादसे हुए हैं । वहां पर बिजली की तारें बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं । कई जगह से तो ये तारें इतनी कमजोर हैं कि थोड़ा–सा प्रैशर पड़ने से ही टूट जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तारों को कब तक बदल दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कई जगहों पर अभी तक जो लोहे के पोल लगे हुए हैं उन्हें कब तक बदल दिया जाएगा ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्र के 16 गांवों मेलाब, देहाना, देवला, जयसिंहपुरा, मेवली, घसेरा, शाकरास, बीवा, पथकौड़ी, दोहा, ओमरा, रिथाड़, भादस, नगीना, घाघस, जलालपुर में कंडक्टर बदले जाने थे । अध्यक्ष जी, हमने पिछले दो सालों में 196.20 किलोमीटर कंडक्टर एक्सचेंज किये हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 16 गांवों में अभी तक 24 किलोमीटर क्षेत्र में पुरानी बिजली के संचालकों को

हमने बदला है और नूहं जिले में 185 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली के संचालकों को बदलने की प्रपोज़ल है उसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंजूरी लेकर दो वर्ष यानी वर्ष 2017 और 2018 में बदल देंगे।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, नूंह विधान सभा क्षेत्र के गांव मेलाब, देहाना, देवला, जयसिंह पुरा, मेवली, घसेरा आदि गांवों के बारे में जो जवाब माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर दिया है वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में बिजली के संचालकों को कहीं पर भी नहीं बदला गया है। चाहे माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवा लें। इनमें से देहाना और देवला आदि गांवों की बिजली के संचालकों को बदलने की प्रपोज़ल तो आई हुई है लेकिन उसकी मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, आज भी इन गांवों में बिजली के संचालक इतने नीचे हैं कि हवा के तेज प्रवाह से आपस में टकरा जाते हैं जिसके कारण बिजली की सप्लाई ठप्प हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, कई–कई दिन ये गांव अंधेर में डूबे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि फिरोजपुर झिरका और नूंह के गांवों में कब तक बिजली के संचालकों को बदला जायेगा?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि इन गांवों में बिजली के संचालक नहीं बदले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि गांव पाटखोरी की 2 किलोमीटर एल.टी. लाइन को एल.टी. केबल के रूप में बदल दी गई है। ओमरा गांव की 4 किलोमीटर मुख्य 11 के.वी.ए. लाइन बदल दी गई है। अध्यक्ष महोदय, नगीना में 18 किलोमीटर की 11 के.वी.ए. लाइन के कंडक्टर बदल दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त 16 गांवों में से 24 किलोमीटर के कंडक्टर बदले जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यू.एच.बी.वी.एन. लि0 के एम.डी. श्री एस.एस.कपूर ने नूंह जिले के सभी माननीय सदस्यों के साथ एक मीटिंग करके सुझाव भी मांगे थे। अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित तौर पर संचालकों को बदलेंगे। अध्यक्ष महोदय, नूंह जिले के लगभग 163261 घरों में 76502 घरों में बिजली के कनैक्शन हैं और लगभग 86759 घरों ने बिजली के कनैक्शन नहीं ले रखें हैं। इस तरह से नूंह जिला का लाइन लॉसिज 58 प्रतिशत है और लगभग 120 करोड़ रूपये की डिफाल्टिंग राशि बकाया है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, नूंह जिले के सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि वो इस रिकवरी को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी की बात सही है। इसमें माननीय सदस्यों को सहयोग करना चाहिए।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पाटखोरी, ओमरा आदि में बिजली के संचालक बदले हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ काम हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है कि नगीना में 18 किलोमीटर 11 के.वी.ए. लाइन के कंडक्टर बदले गए हैं, अध्यक्ष महोदय, यह काम तो सिर्फ शुरू हुआ है न कि कंडक्टर बदले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि बिजली चोरी के डिफाल्टर नूंह जिले में ही है या पूरे हरियाणा में भी है। उसका भी ब्यौरा माननीय मंत्री जी सदन में दे दें।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, नूंह जिला में चाहे कोई क्राईम की बात हो या बिजली चोरी की बात हो, यह बात केवल सोची समझी साजिश के तहत ही कही जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं रिकॉर्ड के मुताबिक ही सदन में कह रहा हूँ कि न ही हम क्राईम के मामले में सबसे आगे हैं बल्कि हमारा नम्बर तो कई जिलों के बाद आता है। बिजली के बारे में मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ केवल तीन या चार 33 के.वी.ए. सब–स्टेशन हैं इस तरह से कितनी बिजली की चोरी होती होगी? इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जितनी बात तोड़–मरोड़ कर सदन में पेश की जाती है। (विघ्न)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, बिजली चोरी का क्राईम तो पिछली सरकार में हुआ करता था। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात की ताईद न करते हुए अपने विषय पर ही बात करूंगा। यह बात सही है कि यू.एच.बी.वी.एन. के एम. डी. श्री एस.एस.कपूर ने नूंह जिले के सभी माननीय सदस्यों के साथ मीटिंग की थी। अध्यक्ष महोदय, पिछले लगभग दो वर्षों से हम बिजली विभाग को सहयोग देते आ रहे हैं और लोगों को बिजली के बिलों को भरने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। लेकिन बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करने की बजाय श्री एस.एस. कपूर के साथ जो गुरूग्राम में मीटिंग हुई थी उसका हवाल सदन को देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, गांव मेलाब, देहाना, देवला, जयसिंह पुरा, मेवली, घसेरा आदि गांवों में एक किलोमीटर

भी बिजली के कंडक्टर नहीं बदले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या जब बहुत बड़ी घटना घट जायेगी तब जाकर इन गांवों में बिजली के कंडक्टर बदले जायेंगे? माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन गांवों में जल्दी से जल्दी बिजली के कंडक्टर बदलने की कृपा करें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने स्वयं कहा है कि 185 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली के संचालकों को बदलने की प्रपोज़ल है। इससे बिजली की कमी की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि फीडर्ज की संख्या कम होने के कारण लोड ज्यादा होता है। माननीय सदस्य के इलाके में अब तक 36 घरेलू फीडर्ज हैं इसलिए निगम ने 20 और फीडर्ज एकसटैंड करने की प्रोपोजल बनाई है इसमें नये 8 फीडर्ज के बनाने का कार्य चल रहा है और 12 फीडर्ज की एल.एन.के. वी. लाईन की एप्रूवल हो चुकी है। उसके बाद फीडर्ज की संख्या बढकर कुल 56 हो जाएगी जिसके कारण बिजली की सप्लाई में लोगों को आपको काफी राहत मिलेगी। अब तक 20 फीडर्ज को बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और 8 फीडर्ज का काम फिलहाल चल रहा है।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं उन 6 स्पेसिफिक गांवों के बारे में पूछना चाहता हूं। उन पर मंत्री जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 185 किलोमीटर लम्बी बिजली की लाईन की प्रोपोजल अंडर कंसीड्रेशन हैं जिनका कार्य लगभग 2 वर्ष के अन्दर पूरा हो जाएगा।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 गांवों में फीडर्ज बनाने की मंजूरी दी गई है वर्तमान में इस संबंध में बिजली विभाग क्या कर रहा है ? अध्यक्ष जी, पिछले साल 6 जून को तुफान आया जिससे हमारा ओमराह फीडर क्षतिग्रस्त हो गया था परन्तु बावजूद इसके विगत 6 महीने में डिपार्टमैंट ने इस फीडर को ठीक नहीं किया है जिसके कारण वहां पर कम से कम 50 गांवों की लाईन ठप्प पड़ी हैं, इसलिए मैं मंत्री जी ने निवेदन करता हूं कि इनके ठीक करने का कार्य जल्दी करवाएं ताकि कोई हादसा न हो।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, आपके सवाल का जबाव माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं यह कार्य जल्दी ही पूरा करवा दिया जाएगा।

.....

Land Limit for Affordable Houses

***1845.Sh. Umesh Aggarwal. :**Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the limit of 300 acreage land have been fixed in the master plan 2031 for the affordable houses in Gurugram; if so, whether there is any proposal to extend the limit up to 500 acreage?

वित्त मंत्री (श्री कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, 300 एकड़ के क्षेत्र की सीमा गुरूग्राम–मानेसर शहरी काम्पलैक्स– 2031 की विकास योजना में नियत नहीं है बल्कि किफायती मकान पालिसी 2013 में नियत है। क्षेत्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव जांच के अधीन है। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने सवाल पूछा है कि क्या गुरूग्राम में किफायती मकानों के लिए मास्टर प्लान 2031 में 300 एकड़ भूमि की सीमा नियत की गई है, यदि ऐसा है तो क्या यह सीमा 500 एकड़ तक बढाने का कोई प्रस्ताव है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि गुरूग्राम मानेसर शहरी कम्पलैक्स संबंधी मास्टर प्लान 2031 में 300 एकड़ भूमि की सीमा नियत नहीं की गई है बल्कि इसे किफायती मकान पालिसी 2013 में निहित किया गया है तथा भूमि की सीमा बढाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री उमेश अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि एफोरडेबल हाउस की स्कीम 300 एकड़ से बढाकर 500 एकड़ बढाने का प्रस्ताव है यह कब तक पूरा होगा, दूसरा सवाल यह है कि क्या यह मास्टर प्लान के अन्दर फिर से बदलाव नहीं हैं तथा तीसरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताएं कि पहले जो 300 एकड़ के एफोरडेबल मकान बनाने के लाईसेंस दिये गये हैं उनमें किस प्रकार की पालिसी बनायी गयी थी क्या वे लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिए गये थे और उनमें क्या अनियमितताएं थीं इसके बारे में भी मंत्री जी बताएं?

कैप्टन अभिमन्युः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो इसकी सीमा बढाने का प्रस्ताव विचाराधीन है अभी उसकी समय सीमा तो निर्धारित नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि इस एफोरडेबल हाउसिज की पॉलिसी को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए। कई जगह इस प्रस्ताव की उसकी निर्धारित सीमा से भी अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये पालिसी बड़ी एट्रैक्टिव है जिसके माध्यम से 5 एकड़ से 10 एकड़ तक की यह विशेष रूप से एफोरडेबल हाउसिज की कालोनी के लिए ये लाईसेंस दिये जा रहे हैं। इसमें जो कारपेट एरिया है वह 28 स्कवेयर से 60 स्कवेयर मीटर का कुल बनता है तथा इसके प्रावधान भी बड़े सख्त रखे गये हैं। यह पॉलिसी वर्ष 2013 में बनायी गयी थी इसमें कहा गया था कि 4 साल के अन्दर जब बिल्डिंग प्लान ड्राफट एप्रूव हो जाए या इ.सी. मिल जाए तो वह कालोनियां बनानी पड़ेगीं। जैसा कि मैंने पहले बताया हैं अगर मैं माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है वह गुरूग्राम मानेसर अर्बन कैंपलैक्स में 213.1357 एकड़ के एल. ओ.आई हैं वह अंडर रूल 10 हैं वह दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लाईसेंस एप्लीकेशन रूल 66.71 के अंडर कंसीड्रेशन है जो 300 एकड़ की सीमा के अन्दर हैं। उसके अलावा 72.7975 एकड़ की एप्लीकेशंज भी और आयी हुई हैं जो इस 300 एकड़ की सीमा से बाहर हैं अगर यह 300 एकड़ की सीमा बढायी जाती है तो इन एप्लिकेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो दूसरे प्रश्न पूछे हैं कि क्या मास्टर प्लान में कोई बदलाव किया गया है? विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मास्टर प्लॉन में जो रेजीडैंशिएल जॉन की जो मर्यादा है या सीमा है उसकी के अन्तर्गत ही उसमें एफोरडेबल हाऊसिज का कम्पोनैंट बढाने का प्रस्ताव पॉलिसी में ही है। रेजीडैंशिएल जोन का कम्पोनैंट उससे अलग से बढता नहीं है। इसलिए मास्टर प्लॉन में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अगला प्रश्न है कि ये लाइसेंसिज देने में किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं या किस प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस दिए गए हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक इस प्रकार की लाइसेंस देने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जानकारी में नहीं आई है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन्ज एक प्राथमिकता के आधार पर जो तयशुदा प्रक्रिया है उसके तहत ही ये लाइसेंस दिए गए हैं।

श्री उमेश अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि यह मास्टर प्लान में बदलाव नहीं है। यह ठीक है कि आर जॉन के अंदर ही ये एफॉर्डेबल हाउसिज के लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन रेजीडैंशिएल सैक्टर की जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस सैक्टर की डेनसिटी के अनुसार ही उसमें सीवर और पानी की फैसलिटीज दी जाती हैं। जब उस सैक्टर में एफॉर्डेबल हाउसिज की स्कीम उसके अंदर आती है तो उस सैक्टर की डैंसिटी बदल जाती है। इस तरह से यह एक मास्टर प्लान के अंदर बदलाव है जिसको मंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरी मैंने अनियमितता की बात की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 213 एकड़ के जो लाइसेंस दिए गए हैं, इनके अंदर कुछ कम्पनियां ऐसी थीं कि जब वर्ष 2013 में जब यह पॉलिसी बनी तो उन्होने पॉलिसी बनने से पहले ही अपने ड्राफ्ट बनवा लिये थे और जब यह पॉलिसी बनने से पहले ड्राफ्ट बने तो उनमें से कुछ लाइसेंस तो पिछली सरकार ने दे दिए थे। जब हमारी सरकार के पास यह बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा की इन लोगों को पॉलिसी का पहले कैसे पता लगा और इन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाद में 2 साल के बाद उन 8 कम्पनियां को भी सरकार द्वरा लाइसेंस जारी कर दिए गए। जब उन कम्पनियों ने पॉलिसी आने से पहले ही ड्राफ्ट बनवा लिए थे तो इसका मतलब है कि उन कम्पनियों को पॉलिसी के बारे में पहले से ही जानकारी थी और वे लोग संभवतः सरकार से मिले हुए थे। उनके ऊपर हमें जांच करानी थी, लेकिन दो साल तक उन कम्पनियों का केस पेंडिंग रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या घटना हुई कि उन लोगों को लाइसेंस जारी कर दिए गए, न तो उनकी जांच की गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। इन कम्पनियों के केस के बारे में क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में कृपया मंत्री जी सदन को जानकारी दें।

कैप्टन अभिमन्यु : आदणीय अध्यक्ष जी, जहां तक मास्टर प्लान की बात है तो माननीय विधायक जी को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चाहे वह रेसिडेंसियल कॉलोनी में डेंसिटी का परिवर्तन की बात हो या उसमें अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, ये सब सरकार के स्तर पर निर्णय किए जा सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलअप भी किया जा सकता है तो इस तरह से यह मास्टर प्लान में बदलाव तो नहीं है। उनकी बात सही है कि डैंसिटी बढ़ेगी तो इफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सरकार अपने स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकती है, लेकिन जो

दूसरा उन्होंने सवाल किया है कि 2013 में पॉलिसी आने से पहले अगर कुछ एप्लीकेंट्स ने ड्राफ्ट एडवांस में बनाकर रखे थे तो निश्चित तौर पर इससे यह आभास मिलता है कि कुछ लोग ऐसे थे, जिनको जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी और उसी की तैयारी में उन्होंने वह एप्लीकेशन और वह ड्राफ्ट बनाकर रखे थे। यह बहुत ही गंभीर सवाल है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसके अलावा माननीय विधायक जी ने आपके माध्यम से सदन को जो जानकारी दी है कि ऐसे कोई 9–10 एप्लीकेंट्स और हैं जिन्हें दो साल के बाद भी आज उनको लाइसेंस दिए गए हैं। अब यह देखने और जांचने का विषय है कि इस दो साल के अंतराल में अगर उन्होंने उनकी एप्लीकेशन में कोई सुधार किया है या उस एप्लीकेशन की प्रक्रिया में अभाव के बावजूद उन्होंने उसे प्रोसेस की है, अगर ऐसी किसी प्रकार की कोई अनियमितता सामने आती है या माननीय विधायक जी उसको प्रकाश में लाते हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : उमेश जी, मंत्री जी ने आपकी बात का स्पष्ट उत्त दे दिया है और किन्हीं अनियमित्ता की अवस्था में जांच करवाने का भी आश्वासन दिया है अतः आप अब बैठिए?

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ। तभी जाकर मेरी बात क्लियर होगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आब्जेक्शन लगते हैं, वह सी.टी.पी पर लगते हैं और सी.टी.पी से फाइल क्लियर हो जाती है और उसके बाद डायरेक्टर से फाईल निकल जाती है, उसके बाद तो कोई आब्जेक्शन की बात बाकी रहती नहीं है। जो वह फाइलें थीं, वह डायरेक्टर से निकलने के बाद 2 साल पेंडिंग रहीं, जबकि हम कहते हैं कि हमारे यहां फाइलें पेंडिंग नहीं रहती हैं या कोई अनियमितता नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री जी के लैवल पर दो साल फाईल पैंडिंग रही है । इसकी पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका हूं उसके बाद भी लाईसैंस जारी कर दिए गये और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फाईल की पैंडैंसी बारे सवाल किया है यह स्पेसिफिक फाईल के बारे में सैपरेट क्वैश्चन है इसलिए इसका अभी जवाब देना संभव नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यदि किसी बिल्डर को लाईसैंस दिया गया है और उसकी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो वह जांच के योग्य है । हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करवायेंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मास्टर प्लान बनाया जाता है उसकी समय सीमा निश्चित की जाती है कि वह उस टाईम तक चेंज नहीं होगा । लेकिन मौजूदा सरकार ने गुड़गांव के सैक्टर 75 ए जो इन्स्टीच्यूशनल था उसका मिक्स लैंड यूज में दे दिया गया और 350 प्रतिशत एफ.ए.आर. दे दिया गया है । इस तरह से यह तो पूरी तरह से मास्टर प्लान को गोलमोल करके बदल दिया गया है । फिर मास्टर प्लान का क्या मतलब रह गया है ? मंत्री जी कृपा इस बारे में बतायें ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह स्प्रेट क्वैश्चन किया है। इसका मूल क्वैश्चन से कोई संबंध नहीं है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यही जानकारी दे दें कि मास्टर प्लान जितने समय के लिए बनाया जाता है उससे पहले उसमें बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट क्वैश्चन है इसलिए इसका जवाब देना संभव नहीं है ।

.....

To set up a Unani Medical College

*** 1810. Shri Zakir Hussain. :** Will the Health Minister be pleased to State -

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Unani Medical College at district Nuh; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

Health Minister (Shri Anil Vij) :

a) Yes, Sir.

b) 2-3 years after receipt of approval from the Govt. of India.

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने नूंह में यूनानी मैडीकल कालेज बनाने की बात स्वीकार की है और कहा है कि भारत सरकार से एप्रूवल मिलने के बाद दो–तीन साल में यह मैडीकल कालेज बना दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष लाना चाहता हूं कि इस यूनानी मैडीकल कालेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयूष, भारत सरकार से भी वित्तीय सहायता मिलेगी । इसमें 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता मिनिस्ट्री ऑफ आयूष, भारत सरकार और 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार देगी । इस पर टोटल खर्चा 10.50 करोड़ रुपये होगा । इसमें हरियाणा सरकार 4.20 करोड़ रुपये प्लस रैकरिंग चार्जिज देगी । मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि अभी इस कालेज की प्रपोजल की फाईल भारत सरकार के पास एप्रूवल के लिए पैंडिंग है । उनका यह जवाब सही नहीं है । अभी इस कालेज की प्रपोजल हरियाणा सरकार के पास ही पैंडिंग है । अभी चीफ आर्किटैक्ट के आफिस में नक्शा बनने के लिए फाईल पैंडिंग है । उसके बाद यह फाईल लोक निर्माण विभाग के पास एस्टीमेट बनने के लिए जायेगी । एस्टीमेट बनने के बाद वित्त विभाग इसकी अप्रूवल देगा और उसके बाद सारी फार्मलटीज पूरी होने के बाद प्रपोजल अप्रूवल के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयूष विभाग के पास भेजी जायेगी । उसके बाद भारत सरकार से इसको बनाने के लिए पैसे मिलेंगे । यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हरियाणा केडर का आई.ए.एस. अधिकारी श्री अजीत मोहन शरण आयूष विभाग में सक्रेटरी हैं । इसलिए वहां पर इसकी एप्रूवल में देरी नहीं लगेगी । मंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि जो मैंने जानकारी दी है क्या वह सही है और वे कब तक इस कालेज की फाईल को सारी फार्मलटीज पूरी करके भारत सरकार को भिजवा देंगे ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस कालेज के लिए जो जानकारी दी है, वह बिलकुल सही है । माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 4.4.2016

को मेवात डिवैल्पमैंट एजैंसी की मीटिंग हुई थी । उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन ले लिया था कि इस यूनानी मैडीकल कालेज को बनाया जायेगा । उसके अतिरिक्त जब मैं मेवात में गया था तो वहां के लोगों ने मुझे भी इसके लिए रिप्रजैंट किया था और आकेड़ा गांव की पंचायत ने इसके लिए 6 एकड़ जमीन देने की बात भी कही थी । उस गांव की जमीन पर यह यूनानी मेडीकल कालेज बनाने के लिए सारी प्रपोजल बनाकर वित्त विभाग के पास भेजी हुई है और जैसे ही हमें फाईनैंस डिपार्टमैंट से इस मामले में क्लीरैंस मिलेगी वैसे ही हम इस केस को फर्दर अप्रूवल के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। वहां पर जो आई.ए.एस. अधिकारी शरण जी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। इस पूरे प्रोजैक्ट की लागत 10.50 करोड़ रूपये बनती है जिसको केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60:40 के रेशों में खर्च किया जाना है। हम स्वयं भी चाहते हैं कि यह यूनानी कालेज अवश्य बने। हरियाणा सरकार प्रदेश में जिला अस्पताल में आयुष सैंटर खोलना चाहती है और आयुष के अंतर्गत आर्युवेदा, योगा और यूनानी सबको रखना चाहते हैं। इस समय हमारी समस्या यही है कि वर्तमान में हमारे पास यूनानी चिकित्सा के क्वॉलिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं। आज की तारीख में हमारे पास पूरे प्रदेश में केवल 19 यूनानी डॉक्टर्स हैं जिनसे हम अपना काम चला रहे हैं। इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। हम इसको पूरे प्रदेश में पॉपूलर करना चाहते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यह काम जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ जायेगा। जल्दी ही हम इसकी फाईनैंस डिपार्टमैंट से क्लीयरैंस करवाकर इसके नक्शे इत्यादि बनवाकर केन्द्र को भेजेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, इसमें एक बार फिर बात आई कि यह 04.04.2016 की मीटिंग में मंजूर नहीं हुआ था बल्कि 04.04.2016 को तो मैंने एम.डी.बी. की मीटिंग में इसकी मांग की थी। उसके बाद 14.12.2016 को गुरूग्राव में हुई मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी थी। माननीय मंत्री जी नूंह गये थे। पता नहीं जिला मेवात से इनको इतना परहेज क्यों है क्योंकि ये मंत्री बने थे अक्तूबर, 2014 में और मेवात में गये अक्तूबर, 2015 में और वह भी मेवात के बाहर–बाहर से आ गये मेवात के मैडीकल कालेज में फिर भी तशरीफ लेकर नहीं गये। इस प्रकार से मेवात में ये आज तक भी नहीं गये। पता नहीं ये ऐसे कर रहे हैं जैसे यू.पी. के चीफ मिनिस्टर कभी नोएड़ा नहीं जाते। इसके लिए जमीन का प्रस्ताव पहले आया हुआ है। मंत्री जी ने मेरे जवाब को फिर स्किप किया है। इस समय मंत्री जी के पाले में गेंद है इसलिए माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने की

कृपा करें कि 10 दिन में या एक महीने के अंदर कब तक ये अपनी तरफ से केस तैयार करके भारत सरकार को भेज देंगे। जिस प्रकार से इन्होंने अभी केन्द्र सरकार का जिक्र किया है मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत सरकार तो अभी पिक्चर में ही नहीं है। ये मुझे यह बतायें कि ये अपने यहां से केस को पूरी तरह से तैयार करके कब तक भारत सरकार के पास भिजवा देंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे विभाग ने अपने स्तर की सारी की सारी कार्यवाही करके वित्त विभाग को केस भेज दिया है जैसे ही वित्त विभाग से यह केस क्लीयर होता है वैसे ही हम इसको केन्द्र को भेज देंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मेरे सवाल का यह कोई संतोषजनक जवाब नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस केस को कब तक भारत सरकार को भिजवा देंगे?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं अपने विभाग के सम्बन्ध में समय सीमा बता सकता हूं लेकिन वित्त विभाग से तो मैं केवल रिकवैस्ट ही कर सकता हूं कि वहां से हमें जल्दी क्लीरैंस मिल जाये। मैं फिर से यह बात दोहराना चाहूंगा कि हम इस केस को जल्दी से जल्दी भारत सरकार को भिजवा देंगे।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव का अभिनंदन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज वी. आई. पीज. गैलरी में श्री सुल्तान सिंह जांडौला, भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार सदन की कार्यवाही देखने के लिए विराजमान है। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Repair of Roads

***1801.Shri Sri Krishan Hooda . :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) whether the road from Chirana to Shamri Via Bajana upto Ganaur Road Mundlana to Khanpur PGI, Shamri to Khanpur PGI and Banwasa to Gharwal have been damaged; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, सड़क अनुसार विवरण निम्न प्रकार हैः–

(क) चिड़ाना से शामड़ी वाया बजाना गन्नौर तक सड़क के लिए–

हां, श्रीमान् जी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क की मरम्मत 31.05.2017 तक किए जाने की संभावना है।

(ख) अन्य सड़कों की मरम्मत, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आगामी वित्त वर्ष में किए जाने की सम्भावना है।

श्री श्रीकृष्ण हुड्डा : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हूं और इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या : 1908

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Rehabilitation Of People

***1850. Sh. Gian Chand Gupta. :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) whether it is fact that about 50,000 people are forced to leave in the hellish conditions without basic amenities in the colonies/Slum Basties of Panchkula; if so, the steps taken by Government to provide basic amenities in these colonies/basties; and (b) the steps taken by the Government, for rehabilitation; of the people living in above said colonies/basties ?

वित्त मंत्री (श्री केप्टन अभिमन्यू) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

(क) लगभग 40,000 लोग पंचकूला में विभिन्न अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं। चूँकि पीने का पानी 'आवष्यक सेवाओं' की श्रेणी में आता है, इसलिए हुडा द्वारा राजीव कॉलोनी व इंदिरा कॉलोनी के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए स्टैंड पोस्ट लगाई गई है। नगर निगम पंचकूला द्वारा राजीव कॉलोनी व इंदिरा कॉलोनी में सफाई, जैसे कि सड़क/गली की सफाई, नाले/नालियों की सफाई, कूड़ा–कर्कट उठाने की व्यवस्था की गई है।

(ख) हुडा द्वारा सैक्टर–20, 26 (पॉकेट क और ख), 28 और औद्योगिक क्षेत्र फेस–1 पंचकूला में पहले ही 2072 आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित लागत 64.78 करोड़ रूपये है। इन में से 1971 आवासीय इकाईयों को आबंटित किया जा चुका है और इनमें आजाद भारत कॉलोनी, मातु राम कॉलोनी, बाबू राम कॉलोनी के झुग्गीवासी रह रहे हैं। इसके बाद राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए पंचकूला में 512 आवासीय इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव था। बाद में यह पाया गया है कि 512 आवासीय इकाईयाँ इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, माता मनसा देवी कॉलोनी ओर मद्रासी कॉलोनी पंचकूला में रहने वाले झुग्गीवासियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यदि इन झुग्गीवासियों को चरणों में पुर्नवासित करते हैं तो

परियोजना को पूरा करने में करीब 20 साल लगेगें। झुग्गीवासियों की अधिकतम संख्या को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को संषोधित किया गया है ताकि नई योजना के अनुसार लगभग 7,000 आवासीय इकाईयों का पी0पी0पी0 मोड पर पंचकूला में निर्माण किया जा सके। लेनदेन–एवं–कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए आमंत्रित की गई निविदा अब स्वीकृति की प्रक्रिया में है। काम शीघ्र ही एजेंसी को आबंटित होने की उम्मीद है। आवासीय इकाईयों को उनके निर्माण की षुरूआत की तारीख से तीन सालों के भीतर पात्र व्यक्तियों को आबंटित किये जाने की संभावना है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये झुग्गी–झोपड़ियां बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गये। उन झोपड़ी वाले लोगों से एक बार 2500/– – 2500/– रूपये और दूसरी बार 8500/– – 8500/– रूपये यह कह कर ले लिये गये कि उनको फ्लैट्स दिये जायेंगे या मकान दिये जायेंगे लेकिन अभी तक न तो उस पैसे का ही पता है कि वह कहां पर गया और न ही उन लोगों को फ्लैट्स या मकान दिये गये। जो लोग 25–30 साल से उन झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको इस समय कोई भी बेसिक एमिनिटीज़ उपलब्ध नहीं हैं। जबकि माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि "Municipal Corporation, Panchkula is looking after the sanitation work, that is, road/gali sweeping, cleaning of drains/nalies, lifting of garbage in Rajiv Colony and Indira Colony." वहां पर इस प्रकार की कोई सुविधा न रोड और न ही गली के लिए उपलब्ध है। क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज के लिए और गलियों की सफाई के लिए एक रूपया भी यहां पर न तो नगर निगम की तरफ से खर्च किया जाता है और न ही हुड्डा की तरफ से खर्च किया जाता है। इसके विपरीत वहां पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वहां पर कोई भी पैसा नगर निगम या हुड्डा की तरफ से खर्च नहीं किया जायेगा। इस कारण आज के दिन उन सभी कालोनियों की हालत बहुत ही खस्ता है। वहां पर लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मज़बूर हैं। इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि वहां पर उन कॉलोनियों को जो इल्लीगल कहकर प्रतिबंध लगाया हुआ है उसको हटाया जाये क्योंकि ये झुग्गी–झोपड़ियां हैं न कि इल्लीगल कालोनीज़। यह सभी जानते हैं कि इल्लीगल कॉलोनीज़ की डैफिनेशन कुछ अलग

होती है। इसलिए मैं बार–बार मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इन झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो यह प्रतिबंध लगा हुआ है कि वहां पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा सकता इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाये और वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधायें चाहे वह गली हो और चाहे वह छोटी–छोटी सड़कें हों वे जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जायें। मेरी माननीय मंत्री जी से केवल इतनी ही प्रार्थना है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार जो 7 हजार रिहायशी फ्लैट पी.पी. पी. मोड पर बनाने जा रही है उनके निर्माण के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये हैं तथा प्रस्तावित ऐजेंसीज को यह काम कब तक अलॉट कर दिया जायेगा?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी ने पंचकुला की इन स्लम बस्तियों को लेकर पिछले 2 साल में कई बार इस महान सदन में प्रश्न भी उठाये हैं तथा कई बार इन्होंने सरकार के स्तर पर भी और व्यक्तिगत चर्चा में भी इस विषय को उठाया है । उनके कल्याण के लिए इनकी संजीदगी और गम्भीरता के बारे में हम सभी जानते हैं । यह बात सही है तथा इस बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर भी रखा हुआ है । सबसे पहले वर्ष 1996 में और उसके बाद वर्ष 2010 में लगभग 3959 एप्लीकेशन्ज प्राप्त हुई हैं जिससे 13497100/– रुपये आवेदन फीस के रुप में प्राप्त हुये हैं । माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि उस पैसे का कोई पता नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस पैसे की पूरी जानकारी सरकार के पास है । जहां तक उनकी डिवैल्पमैंट की बात है तो इस बारे में एक प्रोपोजल तैयार की गई है और पी.पी.पी. मोड पर 7 हजार रिहायशी यूनिट्स बनाई जायेंगी । जिसके तहत एक ट्रांजैक्शन–कम–प्रोग्राम मैनेजमैंट कंसल्टैंट की एप्लीकेशन मांगी गई थी, वे आ गई हैं और अब वह अप्रूवल की स्टेज पर है । यह तय किया गया है कि जब भी इन फ्लैट्स का निर्माण शुरू होगा उसके 3 साल के अन्दर–अन्दर उनको फ्लैट अलॉट कर दिये जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो दूसरा सवाल है वह यह है कि स्लम बस्तियों में बेसिक अमैनिटीज उपलब्ध करवाई जायें । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर बेसिक अमेनिटीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं । वहां पर पीने का पानी दिया जा रहा है तथा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के माध्यम से कुछ साफ–सफाई का काम भी किया जा रहा है । हो सकता है वह माननीय सदस्य की अपेक्षा के अनुरूप न हो जैसी कि माननीय सदस्य उस क्षेत्र में सुविधा देना चाहते

हैं । इनका सुझाव है कि ऐसी स्लम बस्तियों के विकास पर जो बैन लगा हुआ है उसको हटाया जाना चाहिए । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उस पर सरकार द्वारा अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 20 साल पहले 1996 में पैसा जमा करवाया था आज तक उनको फ्लैट नहीं मिले हैं तो क्या सरकार उस पैसे पर उनको ब्याज देगी क्योंकि 20 वर्ष पहले अगर किसी ने 5 हजार रुपये भी जमा करवाये हैं तो 20–30 हजार रुपये तो उसके वैसे ही हो जाते हैं । उनको फ्लैट की अलॉटमैंट भी नहीं हुई है तो क्या उनको उनके जमा पैसे पर ब्याज मिलेगा?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है कि 1996 में एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी और 21 साल बाद आज तक उनको फ्लैट भी उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं तो वाकई यह अजीबोगरीब स्थिति है। उसके बाद 2010 में जो एप्लीकेशन्ज मांगी गई थी उन पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया । जहां तक उनके द्वारा जमा राशि पर ब्याज लगा कर उनको देने की बात है तो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । दूसरी बात यह है कि उस समय जो निर्माण लागत थी उसके हिसाब से वह पैसा ठीक था लेकिन आज 20 साल बाद निर्माण की लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है । फिर भी माननीय सदस्य की तरफ से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा और वह विचार करने योग्य होगा तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है ।

.....

Central University Status To Kurukshetra University

***1841. Sh. Subhash sudha. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give status of Central University to Kurukshetra University; if so, the time by which it is likely to be given?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): नहीं, श्रीमान्। इसलिए, प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी ने

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की चिन्ता व्यक्त की है । यह हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है । कुरूक्षेत्र अपने आप में एक भारत की कल्चरल कैपिटल होने के नाते से इस विश्वविद्यालय को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुरूक्षेत्र सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही गुरू गुरूजम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनी, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी बनी, चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी बनी और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जीन्द बनी । पिछले 6 वर्षों में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 42 से अधिक शोध पत्र लिखे । यह कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी 150 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सैमीनारों का आयोजन कर चुकी है । कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने खेल के जगत में भी 12 अर्जुन पुरस्कार, 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक मेजर ध्यान चन्द पुरस्कार के साथ–साथ अनेकों पुरस्कार लिये हैं । अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिये 325 करोड़ रूपये का बजट पास किया गया है और हमारी सरकार इसके लिये 75 करोड़ रूपये की ग्रांट देती है । वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है अगर मंत्री जी इस केस को भारत सरकार को भेज दें तो स्टेट का 75 करोड़ रूपये बचेगा और वह पैसा दूसरी यूनिवर्सिटीज के काम आ जाएगा । इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में दोबारा से विचार किया जाए । जिसमें आपका बहुत बड़ा उपकार होगा ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को मैं उनकी जो चिन्ता है उस संबंध में कहना चाहता हूं कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय का रूतबा है और यूनिवर्सिटी का ग्रेडेशन है वह सैंट्रल यूनिवर्सिटी के रूतबे से कहीं ज्यादा अच्छा है। जहां तक सुधा जी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की आर्थिक रूप की चिन्ता कर रहे हैं उस संबंध में मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार कर रही है । इसके साथ ही कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को प्रदेश सरकार की तरफ से जो ग्रांट दी जाती है उसको बढ़ाने पर भी हम विचार कर रहे हैं । भारत सरकार भी कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के रूतबे के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले सत्र में मेरे एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने हाउस को यह आश्वस्त किया था कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो कॉलेजिज हैं जैसे टैक्नीकल कॉलेजिज, बी.एड. कॉलेजिज वे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को स्थानांतरण कर दिये गये थे क्या वे दोबारा से इसी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अण्डर लाए जाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पीछे जो वायदा किया था अभी तक तो वह वायदा पूरा नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसके बारे में सदन को बताएं कि वे कॉलेजिज कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अण्डर वापिस कब तक आ जाएंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू ने पिछली बार भी यह प्रश्न किया था क्योंकि उनका जो चुनाव क्षेत्र है वह कुरूक्षेत्र जिले में आता है और इन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की परिधि में जो टैक्नीकल कॉलेज हैं, जो बी.एड. कॉलेज हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वह दूसरे किसी विश्वविद्यालय में खास कर बी.एड. कॉलेज जीन्द में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में शिफ्ट किये गये थे उनको वापिस कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लाया जाए ? परन्तु उसके बाद सदन के बहुत से लोगों ने और खुद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी यह कहा था कि जीन्द यूनिवर्सिटी के पास इन्फ्रास्ट्रैक्चर नहीं है । उस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर उस पर अच्छी तरह से चिन्तन कर लिया है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई बी.एड. कॉलेज, कोई टैक्नीकल कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कॉलेजिज कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कब तक वापिस आएंगे क्योंकि अभी तक तो वह वापिस आए नहीं हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम अपने साथी जसविन्द्र सिंह संधू को इसी सत्र के चलते उनके वापिस आने की चिट्ठी दे देंगे ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रोहतक यूनिवर्सिटी का भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन उसका प्रोसीजर भी सारा शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसके बारे में

वह क्या कहना चाहते हैं ? मंत्री जी ने यहीं सदन में आश्वासन दिया था लेकिन वह इम्प्लीमैंट न हो कर के उल्टा जो करने की कोशिश की जा रही थी वही कर दिया ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी मंत्री जी के विभाग से ही संबंधित है इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे तिगांव विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नीमका गांव में वर्ष 2012 में साढ़े 18 एकड़ जमीन पॉलिटैक्निक कॉलेज बनने के लिये दी गई थी और वह पॉलिटैक्निक कॉलेज बनकर तैयार हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है क्योंकि मूल प्रश्न यूनिवर्सिटी का था । अगर आपका भी कोई यूनिवर्सिटी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह चौटाला जी का तारांकित प्रश्न संख्या 1908 आज के लिए मंजूर है। अभय सिंह चौटाला जी, अभी सदन में मौजूद नहीं है तो मुझे इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दी जाये?

श्री अध्यक्षः संधू जी, देखिये जब तारांकित प्रश्न संख्या 1908 की बारी आई थी तो मैंने बाकायदा अनाउंस किया था, लेकिन उस समय अभय सिंह चौटाला जी उपस्थित नहीं थे और अब तो इस प्रश्न को अनाउंस हुए काफी लंबा समय हो चुका है, यदि आप अनांउसमैंट के समय ही बता देते कि आप अभय सिंह चौटाला जी का प्रश्न पूछेंगे तो आपको समय जरूर दिया जाता है। अतः आप अब प्लीज बैठिए?

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी सुभाष सुधा जी ने पूछा है, उसी प्रश्न के संदर्भ में मैं भी एक चीज माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मान लो सैंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाती है तो बताया जाये कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट एक्ट के तहत बनी यूनिवर्सिटी में सुविधाओं में क्या अंतर होता है?

डॉ पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और जब माननीय मंत्री जी दलाल साहब के प्रश्न का उत्तर दें तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। रामबिलास शर्मा जी हमारे बहुत ही यशस्वी मंत्री हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और इस बात को सुभाष सुधा

तथा जसविन्द्र सिंह संधू जी ने भी उठाया है कि चूंकि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक मदर यूनिवर्सिटी है, बावजूद इसके कई बी.एड. कालेजिज का इस यूनिवर्सिटी के साथ लिंक खत्म कर दिया गया है जिसकी वजह से आज लोगों में बहुत रोष है। मैं माननीय मंत्री जी का निवेदन के साथ धन्यवाद भी करूंगा यदि वे कोई ऐसा आश्वासन दें कि जिन बी.एड. कॉलेजिज का लिंक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से काट दिया गया था, उन कॉलेजिज का दोबारा से कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी के साथ लिंक कायम किया जायेगा ताकि जब हम अपने विधान सभा क्षेत्र में जाये तो कह सके कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बी.एड. कॉलेजिज का लिंक यथावत रहेगा।

श्री अध्यक्षः पवन जी, माननीय मंत्री जी ने आज कहा तो है कि हाउस के चलते–चलते बी.एड. कालेजिज को दोबारा से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लिंक करने वाली चिट्ठी निकल जायेगी?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पवन सैनी जी तो धन्यवाद करने लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां तक श्री करण सिंह दलाल ने बात पूछी है कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी की सुविधाओं में क्या अंतर होता है, उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि सुभाष सुधा जी के मूल प्रश्न का आश्य यह नहीं था कि करूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाये। सुभाष सुधा जी अपने प्रश्न के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है इसलिए इसके आर्थिक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये और सुभाष सुधा जी की इस चिंता का बाकायदा तौर पर समाधान भी कर दिया गया है। श्री आनन्द सिंह दांगी जी ने एम.डी यूनिवर्सिटी, रोहतक के बी. एड़ बारे में पूछा है। पिछले सदन में हरियाणा के बी.एड. कालेजिज को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद में शिफ्ट करने संबंधी एक चिंता प्रकट की गई थी और उस बाबत जैसाकि मैंने अभी जसविन्द्र सिंह संधू जी को बताया है, इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वह निर्णय इसी सत्र में बताया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एम.डी. यूनिवर्सिटी से संबंधित बात को क्लीयर नहीं किया है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि रोहतक एम.डी यूनिवर्सिटी का कोई भी बी.एड कॉलेज चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद के साथ लिंक नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, जो बी.एड. कालेजिज आलेरेडी शिफ्ट हो चुके हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, किसी भी बी.एड. कॉलेज का कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी तथा एम.डी. यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं टूटेगा, इस बाबत अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है जिसकी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि कई बच्चों द्वारा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद में फीस जमा करवा दी गई है। नोटिफिकेशन न होने की अवस्था में प्रदेश के स्टूडेंट्स में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, अगर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद के क्षेत्राधिकार से बी.एड. कॉलेजिज निकाल दिए गए तो इसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, अब मुझे मामले की तह में जाना पड़ेगा और वास्तविकता को बताना पड़ेगा कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी पिछली सरकार में कुछ लोगों को राजी करने के लिए ही बनाई गई थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, कविता जी हर बात के बीच में बोल पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि इनको बोलने का ज्यादा ही शौक है तो इनको अध्यक्ष की चेयर पर बैठा दो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, दांगी जी की टोन हमेशा धमकाने वाली रहती है। कविता जैन जी हमारे कैबिनट मंत्री हैं। दांगी साहब को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछा है और सवाल पूछते हुए बीच में व्यवधान डालना ठीक बात नहीं है और राम बिलास शर्मा जी बहुत ही सीनियर मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी अपने आपको सीनियर मानते हो लेकिन वास्तव में शर्मा जी सबसे ज्यादा सीनियर मंत्री हैं और जहां तक मेरे द्वारा

धमकाकर बोलने वाली बात है तो मैं समझता हूँ कि यह घमकाना नहीं है, रोब से बोलना दिखाता है कि बंदे में हिम्मत है?

11:00 बजे

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, चौधरी आनन्द सिंह दांगी जब बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह बहुत गुस्से में बोल रहे हैं?

श्री आनन्द सिंद दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि यह दमखम की बात है गुस्से करने वाली बात नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन कविता जैन जी कैबिनेट मंत्री है और उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये सवाल का सही जवाब दिया है । (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी घुमा–फिराकर बात कर रही हैं । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष जी, हमें माननीय सदस्यों की तसल्ली के लिए डिटेल में जवाब देना पड़ता है ।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या – 1859

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थी ।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या – 1854

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सदन में उपस्थित नहीं थे ।

.....

Posting Of Doctors And Nurses

*1887.Shri Kehar Singh. : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to post Doctors, Nurses and Pharmacist and to

provide, X-Ray Machine, Ultra-Sound Machine, Blood Testing Machine in the PHC, Nangal Jat, CHC, Hathin and PHC Mandkola of Hathin Constituency ?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Sir, Doctors, Nurses and Pharmacists are posted in various Health Institutions against sanctioned posts keeping in view actual availability. Machines & equipments are provided as per norms prescribed for different level of institutions.

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम नांगल जाट है । दुःख की बात है कि वहां पर न तो डॉक्टर है, न नर्स है और न ही फार्मासिस्ट है । आप सोच सकते हैं कि ऐसे अस्पताल की कितनी दयनीय हालत होगी ? हमारा अस्पताल पिछले 10 साल से अच्छे ढंग से चल रहा था । पहले वहां पर हर महीने हजारों मरीज आते थे । वहां के लोग गरीब हैं । उस अस्पताल की हालत दयनीय होने की वजह से वहां के लोगों को दूसरे अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं । इसी तरह हथीन की सी.एच.सी. में न तो एक्स–रे मशीन है, न अल्ट्रा साउण्ड मशीन है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वहां पर ये सुविधाएं कब तक दे दी जाएंगी ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गांव नांगल जाट की पी.एच.सी. में मैडिकल ऑफिसर की दो पोस्ट्स हैं इनमें एक पोस्ट खाली है और एक पोस्ट भरी हुई है । वहां पर फार्मासिस्ट की एक पोस्ट खाली है । इसके अतिरिक्त वहां पर स्टाफ नर्स की एक सैंक्संड पोस्ट है जोकि भरी हुई है । जहां तक उसमें एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें देने की बात है तो पी.एच.सी. में ये मशीनें नहीं दी जाती है । (विघ्न) जहां तक हथीन सी.एच.सी. की बात है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां की स्थिति बहुत खराब है । वहां पर 8 डॉक्टर्स के स्थान पर केवल एक डॉक्टर नियुक्त है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जब हम डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे तो सबसे पहले हथीन सी.एच.सी. पर डॉक्टर्स की अप्वॉयंटमैंट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Issue of Arms Licenses issued in State

*** 1892. Sh. Naresh Kaushik. :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) the number of Arms Licenses issued in the Haryana State during the tenure of previous Government together with the number of Arms Licenses issued after the formation of present Government.

(b) the purpose and recommendations on which the above said Arms Licenses have been issued; and

(c) the name of the authority whose recommendation is mandatory for issuing the Arms Licenses ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) दिनांक 26.10.2009 से 25.10.2014 और 25.10.2014 से 31.01.2017 तक जारी किए गए शस्त्र लाइसैंस क्रमशः संख्या 14215 व 4138 हैं।

(ख) आत्म–सुरक्षा, सम्पति सुरक्षा, निशानेबाजी खेल और ऐसी नौकरी जिसमें शस्त्र आवश्यक हो, के उद्देश्य के लिए शस्त्र लाईसैंस जारी किए गए हैं।

(ग) प्राधिकारी जिसकी सिफारिश अनिवार्य है :–

अनुज्ञापन अधिकारी	सिफारिश प्राधिकारी
जिलाधीश	––
राज्य सरकार	जिलाधीश
केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय	जिलाधीश/राज्य सरकार

.....

Upgradation of Schools

***1922 Smt. Latika Sharma. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools of Block Morni of Kalka Constituency by giving relaxation in the policy/Norms; if so, the time by which the proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान, कालका विधानसभा क्षेत्र के खण्ड मोरनी में राजकीय विद्यालयों की स्तरोन्नति व नए विद्यालय खोलने के लिए नरम मानदंड दिनांक 20–02–2017 को जारी कर दिए गए हैं।

.....

Problem of Drinking Water

***1947. SH. Ranbir Gangwa. :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of drinking water in Gorchhi, Gawar, Sirsana, Haricot and Nalwa villages of Nalwa Constituency; if so, the step taken by the Government to solve the said problem; and

(b) whether it is also a fact that the water supply pipe line of village Gangwa is obsolete and leaking; if so, the steps taken by the Government to lay down the new pipe line togetherwith the details thereof?

राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रश्न के भाग क0 तथा ख0 का उत्तर नहीं में दिया जाता है।

.....

Use of Ponds for Irrigation Purpose

***1904 Shri Bishanbher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to use the water accumulated in the old ponds of villages for irrigations; if so, the number of such ponds of District Bhiwani the water of which is likely to be utilized for the irrigation purposes in Bawani Kehra Constituency together with the village wise details to these ponds?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) जी हॉ श्रीमान जी।

(ख) गावों के बह निकले हुए तालाबों के अतिरिक्त पानी को सिंचाई में प्रयोग करने के लिए एक योजना अवधारित की है जिस के लिए इस तरह के तालाबों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। शुरूआती चरण में प्रस्तावित है कि ऐसे बह निकले हुए 50 तालाबों की पहचान की जाएगी जहां एक पायलट परियोजना के अंतर्गत ऐसे तालाबों पर सौर उर्जा संचालित सूक्षम सिंचाई प्रणाली द्वारा कृषि योग्य भूमि को सिंचित किया जा सके।

.....

To Open A Government College For Girls

***2002. Sh Rajdeep Phogat. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government college for Girls in the village Achina of Dadri Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान्; इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

.....

अतांराकित प्रश्न एवं उत्तर

To Upgrade as Sub-Tehsil

452. Sh. Rajdeep Phogat. : Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to upgrade the village Chhapar and Achina of Dadri assembly constituency as Sub-Tehsil; if so, the time by which the said villages are likely to be upgraded as Sub-Tehsil?

वित्त मंत्री (श्री कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी। इसलिये इस हिस्से का प्रश्न ही नहीं उठता।

.....

Free Travelling in the Roadways Buses

419. Sh. Karan Singh Dalal. : Will the Transport Minister be pleased to State:-

(a) Whether the Transport Department has issued Identity Cards of Transport Department to the employees of Secretariat including Staff of Chief Minister, Finance Minister and Transport Minister for free travel in the Roadways Buses during the year 2015-16, 2016-17 and till to date.

(b) If so , the details of such employees who have been issued Identity Cards for free travel in Roadway Buses by the Transport Department ; and

(c) The rules/policy under which Identity Cards of Transport Department have been issued to Secretariat Staff other than Transport Department?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्णलाल पंवार) : श्रीमानजी, इस संबंध में विवरणी निम्न प्रकार है:–

(क) जी हां, केवल 31.12.2016 तक। वर्ष 2017 मे (जनवरी, 2017 से अब तक) सचिवालय स्टाफ के कर्मचारियों को अभी तक कोई पहचान पत्र जारी नही किया गया है।

(ख)वर्ष 2015 मे सचिवालय स्टाफ के कर्मचारियों को परिवहन विभाग के 557 पहचान पत्र तथा वर्ष 2016 मे 628 पहचान पत्र जारी किये गये थे। इस वर्ष 2017 में (आज तक) सिविल सचिवालय के कर्मचारियों को परिवहन विभाग का कोई पहचान पत्र जारी नही किया गया है। प्रतिवर्ष कर्मचारियो की संख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**सिफारिश कर्ता**	**जारी पहचान पत्रो की संख्या (2015)**	**जारी पहचान पत्रो की संख्या (2016)**
1.	राजनितिक सलाहाकार मुख्यमंत्री	3	10
2.	मुख्यमंत्री आवास	106	127
3.	ओएसडी मुख्यंमत्री	55	73
4.	वित्त मंत्री	22	24
5.	मिडिया सलाहाकार मुख्यमंत्री	9	14
6.	मुख्यमंत्री कार्यालय	158	160
7.	वित्त विभाग	27	85
8.	परिवहन मंत्री	59	43
9.	मुख्य सचिव	43	36
10.	अन्य (विजिलैन्स तथा अन्य)	22	20
11.	परिवहन शाखा तथा अतिरिक्त मुख्यसचिव परिवहन स्टाफ	53	36
	कुल	**557**	**628**

(ग) परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिवालय स्टाफ को परिवहन विभाग द्वारा पहचान पत्र जारी करने के कोई नियम/नीति नही है। फिर भी यह पूर्व प्रथा के अनुसार सिविल सचिवालय के शाखा अधिकारी/प्रभारी की सिफारिश परमाननीय मुख्यमन्त्री जी के पूर्व अनुमोदन अनुसार जारी किये जाते हैं।

.....

To Set Up a Power Sub-station

453. Shri Rajdeep Phogat. : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up the Power Sub-station in village Nimly of Dadri Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, नहीं। इसलिए प्रश्न का अन्य भाग उठता ही नहीं है।

.....

Construction of Road

454. Sh. Rajdeep Phogat. : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the road from village Chhapar to Narsinghwas is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

विभिन्न मामले उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारी बेटी साक्षी मलिक ने हरियाणा प्रदेश और हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है । परसों उनकी माता ने अपनी बेटी साक्षी मलिक और हरियाणा सरकार के बारे एक बयान दिया है । इस बयान को सुनकर हरियाणा के लोग बड़ी शर्मिन्दगी महसूस कर रहे हैं कि ये कैसी ***** सरकार है जो खिलाड़ियों के लिए अनाउंसमैंट तो करती है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है । अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सदन को

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

बताना चाहता हूं कि हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद फर्स्ट क्लास जैसी महंगी सीट से हवाई यात्रा करके ओलम्पिक खेलों को देखने गए थे । माननीय मंत्री जी ने वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था । वहां पर हमारी बेटी ने मैडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया और हमें गौरवान्वित किया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा की सरकार के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वह अपनी कही हुई बात को पूरा करे और हरियाणा प्रदेश के लोगों के मान–सम्मान का ध्यान रखें । अध्यक्ष महोदय, ***सरकार हरियाणा में बनी है जिसके कारण जनता खून के आंसू रो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री करण सिंह दलाल जी ने ***शब्द कहें हैं। वे रिकार्ड न किए जांए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी का जवाब देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, अपने सीनियर के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हों जो सदन की कार्यवाही से निकालने पड़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने खेलों के पैसों की सिर्फ घोषणा की थी, लेकिन पैसे नहीं दिए थे। वो पैस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सरकार खेलों के पैसे नहीं दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब मीडिया में भी दे दिया और सदन में भी देने जा रहे हैं इसलिए आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन रियो ओलंपिक में कुमारी साक्षी मलिक ने मैडल जीत कर देश की धरती पर कदम रखा था, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

महोदय ने नियमानुसार अढ़ाई करोड़ रूपये की राशि का चेक भेंट कर दिया था। (**इस समय मेजें थपथपाई गई**) पिछली ***सरकार में क्या होता था, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को भी रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में एशियाड की और पिछले तीन वर्षों से खिलाड़ियों के ईनाम की जो राशि थी, वो ईनाम की राशि हमारी सरकार ने दी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, हमारी खेल नीति के अनुसार सरकारी नौकरी का भी प्रावधान है। मगर साक्षी मलिक ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे मेरे शहर में ही मेरे पद के अनुसार नौकरी दी जाये। शहर में केवल महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय ही था और उसमें उसके पद के अनुसार कोई भी पद नहीं था। अध्यक्ष महोदय, उस विश्वविद्यालय में खेल निदेशक का स्पेशल पद क्रीएट करने की सारी स्वीकृति दे दी गई है। अध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक 11 मार्च को होनी वाली है, उसी दिन साक्षी मलिक को नौकरी मिल जायेगी। (**इस समय मेजें थपथपाई गई**) अध्यक्ष महोदय, फिर उसने कहा कि जहाँ मैं अभ्यास करती हूँ उसे वातानुकूलित बनाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमने कुमारी साक्षी मलिक की वो बात भी मानी ली। अध्यक्ष महोदय, हमने 75 लाख रूपये की मंजूर करके उपायुक्त रोहतक को भेज दिया और कहा कि जिस हॉल में साक्षी मलिक अभ्यास करती है उस हॉल को बढ़िया बनाकर वातानुकूलित बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कोच की बात आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, उसे प्लॉट देने की बात थी। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, कोच को ईनाम देने के बारे में वैसे तो हमारी खेल नीति में कोई योजना नहीं है। लेकिन कुमारी साक्षी मलिक ने कहा है कि मेरे कोचिज को भी इनाम की राशि दी जाये। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि हम साक्षी मलिक के एक कोच को ईनाम की राशि दे देते हैं। साक्षी मलिक ने पहले अपने एक ऐफिडेविट में दो कोचिज के नाम दिए थे लेकिन फिर दूसरे ऐफिडेविट में उसने तीन कोचिज के नाम दिए। इसके बाद फिर साक्षी मलिक ने कहा कि मेरे एक कोच को प्रमोट कर दो। अध्यक्ष महोदय, एक कोच ने दरखास्त दी कि साक्षी मलिक का असली कोच मैं हूँ इसलिए इनाम की राशि मुझे दी जाये। अध्यक्ष महोदय, 5–6 कोचिज को इनाम की राशि सरकार नहीं दे सकती है इसलिए हमने साक्षी मलिक से कहा कि आप एक कोच के नाम का फैसला करके सरकार के पास भेज दें ताकि उसे ईनाम की राशि दी जा सके। (विघ्न) आप लोगों को ए.बी.सी.डी. का भी पता नहीं है, इसलिए खानपुर का टीका लगाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, प्लॉट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि प्लॉट देने का प्रावधान पॉलिसी में है। इसमें हमने कुछ नया नहीं देना है। साक्षी मलिक को हुडा विभाग में प्लॉट के लिए आवेदन करना चाहिए। लेकिन साक्षी मलिक ने हुडा विभाग में आज तक प्लॉट के लिए एप्लाई नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह सरासर बेईमानी है। सरकार अपने वचन से पीछे हट रही है। माननीय मंत्री जी की सारी की सारी बातें झूठी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। अतः आप दलाल साहब को बिठायें। (विघ्न) इनको ए.बी.सी.डी. पढने तक का ज्ञान नहीं है। इनको यह तक नहीं पता की मूली पेड़ों पर लगती है या जमीन में लगायी जाती है।

श्री अध्यक्षः करण जी, माननीय मंत्री जी आपके सवाल का जबाव दे रहे हैं और सवाल के जबाव से पता चल गया होगा कि मंत्री जी सही जबाव दे रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि साक्षी मलिक को एक प्लाट दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः करण जी, आपने पहला सवाल किया पैसे के बारे में तो मंत्री जी ने उसका जबाव दे दिया हैं और दूसरा प्रश्न कोच को इनाम देने के बारे में कहा था उसके बारे में मंत्री जी ने बता दिया है तीसरा प्रश्न प्लाट के बारे में था तो उसके बारे में बताया गया कि साक्षी मलिक द्वारा हुडा को एप्लाई करने के बाद विचार किया जाएगा और जहाँ तक नौकरी से संबंधित चौथा प्रश्न है, उसके बारे में मंत्री जी ने बता दिया है कि प्रौसेस चल रहा है, अतः दलाल साहब अब आप बैठिये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने खेल पॉलिसी के हिसाब से ही कार्य किया है। यह लो उल्टी ऐनक लगाकर अखबार पढ़ते हैं इसलिए इनको बात समझ नहीं आती है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, ...(विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, आपके सभी सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है। अतः आप प्लीज बैठिये और हाउस को चलाने में सहयोग दें।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, इनको बिठाईये।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जबाव दिया है और यदि आप ध्यान से देखें तो इस जवाब पर किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शंका तक जाहिर नहीं की गई है। आप बेवजह सदन की कार्यवाही को बाधित न करें।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष जी, एक और काले कोट वाला खड़ा हो गया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, करनाल में एक दलित परिवार की कुछ दबंगों ने पिटाई की हैं। दबंगों द्वारा दलित परिवार के लड़के को घुड़चढ़ी नहीं होने दिया गया। जिनके भय से वे दलित परिवार पलायन को मजूबर हो गये हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अब जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने सभी दलित परिवार धरने पर बैठे हैं। इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी अपना

वक्तव्य नहीं दिया है। स्पीकर सर, इसमें हंसने वाली बात नहीं है क्या इस प्रदेश में दलितों को घुड़चढी निकालने का अधिकार नहीं है? दलित गांव छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं और सरकार/प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, मैं इसलिए हंसा था कि आप लोग बात करते हैं दलित के हितों की और वहीं अपनी पार्टी के दलित अध्यक्ष की पिटाई कर देते हो? (विघ्न)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गरीब व दलित के हक की लड़ाई की बात इस माननीय सदन में कर रहे हैं मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की देश की राजधानी दिल्ली में पिटाई कर दी क्योंकि वह एक दलित का बेटा था। ये लोग हमारे ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इनको ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज:अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पाटी के सदस्यों ने अपनी पार्टी के दलित समुदाय से संबंध रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी थी। इनके ऊपर एस. सी./एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः विज साहब, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक तंवर के बारे में बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेरी हंसी इसी बात पर छूट गयी थी कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य दलित समुदाय के हितों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी के दलित समुदाय से संबंध रखने वाले प्रदेशाध्यक्ष की पिटाई करते हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई की थी जो कि एक दलित हैं जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है।(शोर एवं व्यवधान) इन लोगों को पहले मुकदमें का निपटारा करवाना चाहिए?

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, मंत्री जी जबाव दे रहे हैं आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, मेरे द्वारा उठाये गए मामले को हल्के में न लिया जाये क्योंकि इस मामले में दलित गरीब समुदाय के लोगों को गांव छोड़कर जाने

के लिए मजबूर किया गया है। वे पलायन कर गये हैं। सरकार के पास कोई जबाव नहीं है। सरकार उनको न्याय दिलाने की बजाय चूप–चाप बैठी है और अपनी बात दबाने के लिए मंत्री जी को रामलीला के विभिषण की तरह खड़ा कर दिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस मामले में रामलीला के विभिषण की भूमिका निभा रहे हैं। (शोर एवं व्यधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है वे अपने दलित अध्यक्ष की डंडों से मारकर पिटाई कर रहे हैं और कुछ दिन पहले इन्होंने कुमारी शैलजा की इन्सलट की थी। (शोर एवं व्यधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा उठाया गया मामला गरीबों को पीटकर गांव से बाहर निकालने का है। यह बहुत ही गंम्भीर मामला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः बहन जी, बैठिये मुझे अपनी बात पूरी करने दें (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, ये अपनी सी.एल.पी. लीडर को बैठने के लिए कह रहे हैं यह पहली बार किया जा रहा है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को पीटते हैं यह कैसी पार्टी है ? (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने दलित अध्यक्ष की पिटाई की थी जिसके कारण मुकदमा दर्ज हो गया है। यह लोग स्वयं की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं और सदन में काले कपड़े डालकर विरोध जताने का ढोंग करके सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूं कि वे पार्टी अध्यक्ष को पीट रहे हैं और अपनी सी.एल.पी की लीडर को बैठने के लिए कह रहे हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी अध्यक्ष को पीट दिया और इनके ऊपर एस.सी/एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।(शोर

एव व्यवधान) यह दलित विरोधी पाटी है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ अत्याचार करती है, इन्हीं के समय में मिर्चपुर कांड हुआ, हमेशा दलितों का विरोध करने वाली पार्टी है। गोहाना कांड हुआ और करनाल में दलितों के साथ भी इन्हीं की पार्टी की शरारत हो सकती है। (शोर एव व्यवधान) जवाब तो सबको देने पड़ेंगे। जवाब पूरा देना पड़ेगा। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जब स्पीकर था तो इनको *** बाहर निकालता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, किसी भी तरह से सदन के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाने वाली ऐसी भाषा का और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह ठीक नहीं है। इस प्रकार के शब्द वापस लेने चाहिए, जो इन्होंने माननीय मंत्री जी को कहा है।

श्री अध्यक्ष : जो श्री कुलदीप शर्मा जी ने शब्द कहे हैं, वे शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। (शोर एव व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बारे में जो कल से मुझे जानकारी मिली है उसके बारे में आपको बता देता हूं। यह ठीक है कि गांव में दो वर्गों में यह विवाद बना और वो घुड़–चढ़ी को लेकर बना है। अब एक तथ्य तो यह आ रहा है, क्योंकि गांव में अपनी एक पंचायत होती है और गांव काा एक अपना अलग से सिस्टम होता है इसलिए गांव की पंचायत कुछ बातें तय करती है और पंचायत द्वारा लिए गये फैसले पर सब लोग चलने का प्रयत्न करते हैं चाहे वह डीजे की बात हो और चाहे घुड़ चढ़ी की बात आती हो। इसके अलावा कई दूसरी तरह की बातें होती हैं जिनके बारे में पंचायत फैसला करती है। ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि उस गांव की पंचायत ने यह फैसला किया था कि घुड़–चढ़ी की प्रथा को हम गांव में नहीं किया करेंगे। उसका क्या कारण रहा होगा क्या नहीं रहा होगा मालूम नहीं। लेकिन जो वर्तमान घटनाक्रम हुआ तो उसमें वाल्मीकी समाज के लोगों ने कहा की हम तो घुड़–चढ़ी करेंगे। इस प्रकार उन्होंने घुड़–चढ़ी की रस्म गांव में शुरू कर दी, ऐसा करने से थोड़ा विवाद बढ़ते देख कर

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस ने कहा कि चूंकि गांव में घुड़–चढ़ी करने या न करने का कोई निश्चित विधान नहीं हैं इसलिए जो समाज घुड़–चढ़ी की रस्म करना चाहता है वह करे, इसको ध्यान में रखते हुए तथा सुरक्षा पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए घुड़–चढ़ी की रस्म को पूरा करवाया गया। इस पर दूसरे समाज के लोगों ने उसका विरोध किया और कुछ स्वर्ण जाति के नौजवानों ने घुड़–चढ़ी के दौरान पथराव भी किया जिससे और पुलिस के लोगों को चोट भी आई। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। एक मुकदमा तो पुलिस की ओर से दर्ज किया गया और दूसरा मुकदमा संबंधित पक्ष वाल्मीकी समाज के लोगों ने भी एस.सी/एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में फिर दोनों पक्षों में समझौते की भी कुछ बातचीत चली और जब समझौते की बात चली तो जिस वर्ग ने घुड़–चढ़ी का विरोध किया था, उन्होंने माफी भी मांग ली और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम अपनी पगड़ी उतारकर आपके पैरों में रखते हैं, कृपा करके आप इस विवाद को आगे न बढ़ाइए। अब घुड़–चढ़ी हो गई है, इसलिए इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमें इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब कोई ऐसा मुद्दा खड़ा होता है खासकर करके दलित और दलित विरोध का विषय आता है तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं। केवल हमारे हरियाणा के अंदर के ही नहीं कुछ दिल्ली के लोग, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग बीच–बीच में कूद गए और कूदने के बाद वे लोग गांव छोड़कर के करनाल की तरफ यानी शहर की तरफ जब आना जब शुरू किया तो उनको लोगों ने कहा कि ऐसा मत कीजिए विषय को विवाद को समाप्त करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानी गई जैसा मैंने बताया की कुछ लोगों ने उसको उकसाया और उकसा करके जब करनाल आ गए तो कल शाम को डी.सी ने सब पक्षों को बुलाकर के 21 या 31 मैम्बर्ज की एक कमेटी बनाई और वह कमेटी बैठकर के कहा की ठीक है हम वापस चले जाते हैं और इस विषय को यहां समाप्त करते हैं । कमेटी बनी बाहर आये, बाहर आने के बाद तो फिर आपस में उन लोगों में जिन लोगों ने गांव छोड़ गए थे 100–125 लोग के आस पास हैं जो करनाल में बैठे हैं। उनका फिर आपस में विवाद हुआ और दो–तीन वर्ग बन गये । उनमें से एक ग्रुप के लोग कहते हैं कि गांव वापिस जाना चाहिए और दूसरा ग्रुप कहता है कि एफ.आई.आर. पर एक्शन होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और उस पर एक्शन भी होगा लेकिन यदि

बगैर कार्यवाही आपस में समझौता होकर यह विषय समाप्त किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी । यदि समझौता नहीं होता है तो एफ.आई.आर. के मुताबिक कार्यवाही होगी । अभी समझौते की बात चल रही है । हमने हमारे मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी और श्री भगवान दास जी को वहां समझौता करवाने के लिए भेजा है । वे वहां पर सभी लोगों से बात–चीत करेंगे और समझौता हो जाता है तो यह विषय समाप्त हो जायेगा अन्यथा एफ.आई.आर. के मुताबिक कार्यवाही होगी ।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी ने हमारे वरिष्ठ मंत्री जी को कहा है कि जब कुलदीप शर्मा जी स्पीकर होते थे उस समय वे उनको *** निकालते थे और यहां तक कहा है कि आगे वे स्पीकर बने तो निकालेंगे । यह उनकी बहुत गलत बात है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए उनके खिलाफ कोई न कोई निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से सदन नहीं चलना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, पूर्व स्पीकर ने जो बात कही है वह रिकार्ड

पर ली जाये । अपनी इस बात के लिए वे सदन से माफी मांगे अन्यथा मेरा आपसे निवेदन है कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी द्वारा सदन में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि वे कान पकड़कर बाहर निकालते थे । (शोर एवं व्यवधान) इस तरह की बात करके ये लोग सदन में दादागिरी की बात कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथियों का इस तरह का व्यवहार हम यहां सहन नहीं करेंगे ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की मर्यादा का सवाल है । कुलदीप शर्मा जी ने जो बात कही है वह रिकार्ड पर लानी चाहिए । इन्होंने जिस तरह की बात आज की है इससे जाहिर होता है कि वे स्पीकर रहते हुए किस तरह

———————————————————————————

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

का व्यवहार विपक्ष के सदस्यों के साथ करते थे । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन की मर्यादा और चेयर की आस्था का सवाल है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी अपनी कही हुई बात के लिए सदन से माफी मांगे अन्यथा मेरा आपसे निवेदन है कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह की बात आज यहां कही है उससे जाहिर होता है कि उन्होंने स्पीकर होते हुए भी इस महान सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का काम किया था । आज भी इन्होंने बड़े ही असभ्य तरीके से हमारे वरिष्ठ मंत्री जी के खिलाफ धमकी भरे अंदाज में जैस्चर शब्दों का प्रयोग किया है । सदन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की मर्यादाओं को कायम करने के लिए माननीय सदस्य या तो पूरे सदन से माफी मांगे अन्यथा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी को ही कुलदीप शर्मा जी द्वारा कहे गये शब्दों से तकलीफ नहीं है तो सत्ता पक्ष के दूसरे साथियों को तकलीफ क्यों हो रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमें सदन की मर्यादा की तकलीफ है और हरियाणा की जनता की मर्यादा की तकलीफ है । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी इस तरह की धमकी देने की तकलीफ न करें । (शोर एवं व्यवधान) सदन की मर्यादा की तकलीफ सबको होनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुलदीप शर्मा से सदन से गलत ब्यानी के लिए माफी मांगे अन्यथा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों के कहने से बैठने वाला नहीं हूं, मुझे भी बोलने का अधिकार है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढ़ांडा : अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी संस्कृति होती है वह उसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है । इन लोगों की संस्कृति ही इस तरह की है । (शोर एवं व्यवधान) इनके पूर्व स्पीकर कहते हैं कि वे अपने समय में विपक्ष के साथियों

को *** बाहर निकलवाते थे और आगे भी वे स्पीकर बने तो ऐसा ही करेंगे । (शोर एवं व्यवधान) मैं उनको कहना चाहूंगा कि वे इस तरह के सपने संजोकर रखें क्योंकि सपना लेना अच्छी बात है । आज कांग्रेस की हालत पूरे देश में फटे जूते जैसी हो गई है । (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी सरकार कहीं भी आने वाली नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह की भाषा का

प्रयोग किया है उसके लिए वे सदन से माफी मांगे अन्यथा मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान) जिस समय हम नये–नये चुनकर आये थे उस समय ये बड़ी अच्छी–अच्छी बातें ओरिंटेशन प्रोग्राम में बताते थे लेकिन अब जिस तरह का व्यवहार ये लोग यहां पर करते हैं वह बहुत ही निंदनीय है । इन लोगों ने अपने दस साल के शासन में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुलदीप शर्मा जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन की मर्यादा और परम्परा बनाये रखने के लिए यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि भूतपूर्व स्पीकर भी हैं, उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनके लिए

प्रयोग किया है उसके लिए वे सदन से माफी मांगे अन्यथा मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान) जिस समय हम नये–नये चुनकर आये थे उस समय ये बड़ी अच्छी–अच्छी बातें ओरिंटेशन प्रोग्राम में बताते थे लेकिन अब जिस तरह का व्यवहार ये लोग यहां पर करते हैं वह बहुत ही निंदनीय है । इन लोगों ने अपने दस साल के शासन में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुलदीप शर्मा जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन की मर्यादा और परम्परा बनाये रखने के लिए यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

कुलदीप शर्मा जी, जो कि भूतपूर्व स्पीकर भी हैं, उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनके लिए आप एक बार उनको अवसर दें कि वे अपने द्वारा कहे गये आपत्तिजनक शब्दों के लिए पूरे सदन से माफी मांगे। अगर वे हमारी संतुष्टि तक माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हम उनमे खिलाफ निंदा प्रस्ताव इस सदन में पेश करना चाहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, जब मंत्री जी को ऐसी भाषा अच्छी लगती है और ये किसी माननीय सदस्य को यह कहते हैं कि इसको खानपुर के किसी मैंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इनको अच्छी भाष सिखाई जाये। जब मंत्री जी ये कहते हैं कि तुम कौन हो? मैं मंत्री हूं। अगर कोई इस प्रकार की बात करे तो ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ता है। यहां पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए इसको पहले माननीय मंत्री जी समझें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि किसी भी दृष्टि से आपत्तिजनक या संसदीय मर्यादा के खिलाफ हो। अगर माननीय सदस्य ने ऐसी कोई बात अपने–आप ही सुन ली है तो यह इनका कानों का कसूर है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनके कान आवाज करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं यह बात बार–बार कहना चाहूंगा कि इनके कान बजते हैं अर्थात आवाज करते हैं तभी तो ये इतना ज्यादा सुन लेते हैं जो कि किसी ने नहीं कहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैंने इस प्रकार के कोई शब्द नहीं कहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, इन्होंने पिछले सैशन या उससे भी पहले सैशन में इस प्रकार की बातें कही हैं। अगर आप जरूरी समझें तो रिकार्ड निकलवाकर चैक कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आज की बात कर रहा हूं। पहले तो मैंने इनको पता नहीं क्या–क्या कहा है लेकिन मैं यह फिर से कह रहा हूं कि आज मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं बार–बार यही कह रहा हूं कि पहले तो मैंने पता नहीं क्या–क्या कहा है लेकिन आज कुछ नहीं कहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मैं सभी सम्बंधित सदस्यों को अपने चैम्बर में बुलाकर इस बारे में बात करता हूं। अभी आप विषय पर बात न करें और हाउस की कार्यवाही को

नियमानुसार चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण, कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान) दांगी जी, आप बोलिये आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत परम्परा है कि कभी तो श्री करण सिंह दलाल खड़े होकर बात करके सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से बाधित करते हैं और कभी श्री कुलदीप शर्मा जी ऐसा करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से सदन को नहीं चलाया जा सकता। जिस प्रकार से कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक बहुत ही सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है। कांग्रेस के माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि उसके ऊपर चर्चा न हो और बजट की अच्छी बातें पूरे सदन और पूरे प्रदेश के सामने न आ पायें इसलिए अपने इस लक्ष्य को ध्यान रखकर कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इसी कारण से जो सरकार की उपलब्धियां आज यहां आने वाली थी वे यहां पर न आयें। ये नहीं चाहते कि बजट के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों की चर्चा यहां पर न हो इसीलिए ये सब खेल खेलकर सदन को भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि इन माननीय सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रशिक्षण शिविर चलाकर हमें ऐसे लोगों से प्रशिक्षण दिलवाया जिन्हें स्वयं बात नहीं करनी आती। हमने ऐसे लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है यह सोचकर हमें शर्म आ रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि या तो आप श्री कुलदीप शर्मा जी से उनके द्वारा यहां पर एक माननीय मंत्री के खिलाफ प्रयोग किये गये शब्दों के लिए माफी मंगवायें या फिर हम उनके खिलाफ यहां पर निंदा प्रस्ताव लेकर आयेंगे। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके ध्यान में पुनः यह बात लाना चाहूंगा कि श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने विधान सभा में जो अपना ऑफिस बनाया था उसके आगे इन्होंने राज्यमंत्री लिखवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने

की परमिशन नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ये आज भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री कुलदीप शर्मा जी को यह कहना चाहूंगा कि वे हमारे बारे में इस प्रकार की बात करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लिया करें। जो बात मैंने कही है मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूं। ये खुद और इनकी पार्टी के नेता स्वयं कानून की पालना नहीं करते लेकिन दूसरों को कानून की पालना की नसीहत देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण, कृपया शांति से बैठ जायें और दांगी जी को अपनी बात कहने दें। ये बहुत ही कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं इसलिए आप कृपया करके इनकी बात सुनें क्योंकि ये कोई न कोई अच्छी बात ही सुनायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) दांगी जी, आप बोलें।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनके कारण यहां पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और वह कंट्रोवर्सी इस हद तक चली जाती है कि यहां पर हम सभी का तमाशा हो जाता है। हम यहां पर सभी 90 लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम यहां पर लाखों लोगों को रिप्रैजेंट करते हैं। यहां पर अगर हम कोई ऐसी वैसी बात करते हैं और यहां पर जो हास्यस्पद वातावरण बनता हैं यहां पर जो पूरे हरियाणा प्रदेश से चारों तरफ से आये हुए लोग यहां पर बैठे हैं ये हमारा क्या इम्प्रैशन लेकर जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, शायद इन बिना वजह खड़े होकर बोलने वाले माननीय सदस्यों को एक बात सिखा रखी है कि विपक्ष की तरफ से चाहे कोई जायज बात बोले और चाहे नाजायज बात बोले आपको खड़े होकर हंगामा खड़ा करना है।

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, ये सभी माननीय सदस्य आपकी बात की ही स्पोर्ट कर रहे हैं। आप कंटीन्यू करें।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता के साथ कोई घटना घटती है और जनता में किसी भी प्रकार का रोष होता है उसको यहां पर रखा जाये और उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया जाये तो उसके समाधान के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है । यहां पर यह कहना कि पहले यह काम हुआ वह हुआ उसको कोई नहीं पूछता क्योंकि वह पीछे चला गया है । अध्यक्ष महोदय, मेरे सिर के बाल उड़ गये हैं अगर मैं चाहूं

तो भी वे वापिस नहीं आ सकते इसलिए कंट्रोवर्सी में पड़ने की बजाय जो प्रश्न पूछा जाता है उसका सही ढंग से जवाब दिया जाये ताकि हमारा सदन सौहार्दपूर्ण तरीके से चल सके । यहां पर विपक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि यहां पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर आती है । एक आदमी बोलता है और उसके पीछे 20–20 आदमी खड़े हो जाते हैं यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, श्री करण सिंह दलाल ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं वे केवल और केवल हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए कहे हैं । वे ऐसे अनजान और नये सदस्य नहीं हैं कि उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द अचानक निकल गये । मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल तैयार हो कर इस प्रकार के शब्द कहे हैं । उसके बाद उन्होंने वे शब्द दोबारा से कहे हैं । इतने सीनियर सदस्य अगर इस तरह की बात करेंगे तो वह ठीक नहीं है । दलाल साहब, हमने आपको ओरिएन्टेशन प्रोग्राम में नये विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था और अगर आप ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि इनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये । शब्दों को कार्यवाही से निकालना गलत नहीं है लेकिन आप जैसे सदस्य की बात को कार्यवाही से निकालना आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है कि एक 4–5 बार चुन कर आये हुये विधायक के शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलना पड़ा है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे द्वारा कहे गये शब्द असंसदीय हैं तो आप उनको कार्यवाही से निकाल दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, शब्द तो सदन की कार्यवाही से निकाल दिये लेकिन जब श्री करण सिंह दलाल बोल रहे हैं तो इस तरह का मैसेज जाना चाहिए कि करण सिंह दलाल जी बोल रहे हैं । आपकी जानकारी सभी सदस्यों से अधिक है इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई गलत बात न हो । श्री कुलदीप शर्मा जी तो स्पीकर भी रहे हैं इसलिए उनकी बात मर्यादापूर्ण होनी चाहिए। आप अब तक ठीक चल रहे थे लेकिन आज आप पुरानी फोर्म में आ गये हैं ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं लेकिन अगर मैं किसी हरिजन का, किसी गरीब आदमी का मुद्दा उठाता हूं और सत्ता पक्ष की तरफ से 15 आदमी खड़े होकर बोल रहे हैं तो यह गलत बात है । उनको मुद्दे के महत्व को समझना चाहिए । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया तो हम

संतुष्ट हो कर बैठ गये लेकिन जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उनके पीछे कई–कई मंत्री खड़े हो कर बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपको बात ठीक तरीके से करनी चाहिए थी । आपने बात को जिस तरह से रखा वह ठीक नहीं था, आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं । आप इस तरह से नहीं बोल रहे थे जैसे हाउस में बोलते हैं बल्कि इस तरह से बोल रहे थे जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर प्रदर्शन करते हैं । आप अपना प्रश्न रखते और कहते कि सरकार इस पर जवाब दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम के तहत ही अपनी बात रखी थी । अध्यक्ष महोदय, मैं किसी से भी बहस कर सकता हूं लेकिन आपके साथ बहस नहीं करूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से बड़ी कोई सरकार नहीं है और जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो पीछे से कई सदस्य क्यों बोल रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और सभी सदस्यों को इसका पालन करना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिए समय दीजिए । मुझे बहुत जरूरी बात करनी है । मैं 1999 का एक जनहित का मुद्दा उठाना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसलिए पहले मैं बोलूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के लोगों की बात करनी है ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप तो करती ही प्रदेश की लोगों की बात हैं । अपनी बात तो आप कभी करती ही नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) कोई बात नहीं महिलाओं की संख्या वैसे ही कम है, चलो इनकी बात मान लेते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछ रहा हूं कि ये डिप्टी स्पीकर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) इनको सदन की मर्यादाओं का अच्छी तरह से

ज्ञान है और यह चेयर को ही चैलेंज कर रही हैं । इनको ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कल महिला दिवस है इसलिये आज इनको थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि ये डिप्टी स्पीकर रही हैं । आप इनसे पूछिये कि क्या सदन का कोई सदस्य स्पीकर को चैलेंज कर सकता है ? लेकिन ये तो चैलेंज कर रही हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :चौटाला साहब, कोई नहीं महिला दिवस के अवसर पर इन्हें छूट दे देते हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं रिवेन्यू पटवारियों के विषय पर बात रखना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : किरण जी, आप पटवारियों की बात कर रही थी ? (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी बात रख लीजिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूं । इतनी देर के बाद अब ये सदन थोड़ा सा शांत हुआ है तो मैं यह जायज बात करने की कोशिश कर रही हूं । मैं प्रदेश के लोगों की बात कर रही हूं कि वर्ष 1999 के अन्दर रिवेन्यु पटवारियों को चयनित किया गया था । वह तब से लेकर अब तक ऐसे ही भटक रहे हैं जबकि उनका सही व लीगल तरीके से पूरा चयन हुआ था । हमारे मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी यहां बैठे हैं उन्होंने भी उनको यह आश्वासन दे रखा है कि उनको लिया जाएगा । मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं उनसे मेरी उन लोगों की तरफ से यह प्रार्थना है कि ये 1055 ऑफ दैम ऐसे ही बाहर चक्कर लगाते फिर रहे हैं । जबकि इनको सही प्रक्रिया से चुना गया है । मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार अब इनको दोबारा से नियुक्त करेगी या नहीं करेगी । बस मुझे इतना ही जानना है । इसमें कोई लम्बी चौड़ी कहानी नहीं है । इसके अलावा मैंने कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करनी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा कैंडीडेट नहीं हैं केवल 250 कैंडीडेट ही बचे हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो भी हैं जितने भी कैंडीडेट्स हैं 100 हैं 200 हैं 250 हैं आप उनको दोबारा से नियुक्त कर दीजिये । यह केवल 250 कैंडीडेट्स ही हैं आप उनको दोबारा से नियुक्त कर दीजिये । आप तो दिलदार मंत्री हैं । आप इस कार्य को कर दीजिये। इनमें से ज्यादातर कैंडीडेट्स तो आपके इलाके के ही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, **** की सरकार है ।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, अभी दलाल साहब फिर यह कह रहे हैं कि * की सरकार है। दलाल साहब को विज साहब ने जो थोड़ी देर पहले कहा था वह बिल्कुल सही कहा था ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, द्वारा कहे गये शब्द सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड न किए जाएं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपना वक्तव्य देना चाह रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको बोलने का मौका दिया जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई कह रहा है निन्दा प्रस्ताव लाओ और कोई कह रहा है कुछ लाओ । मैं यह कहता हूं कि शर्मा जी ने पिछली बार हमें सदन से बहुत बार बाहर निकाला था । आप भी बस इनको एक बार सदन से बाहर निकाल दो । (हंसी)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सी.एल.पी. लीडर आदरणीय बहन किरण चौधरी ने जो बात पटवारियों की कही है । वह कैंडीडेट्स हम सबको भी मिले हैं और इनका जो मुद्दा है वह विचाराधीन है । इसके बारे में जयप्रकाश जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वे लोग मिले हैं । उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं । एक बात साफ है कि स्पीकर सर आप इस महान सदन को बहुत ही शालीनता व बहुत ही बढ़िया ढंग से चला रहे है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

विज जी को तो पुराने दिन अभी तक याद हैं जब छोटी सी बात पर ही इनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। श्री आनन्द सिंह दांगी ने आज बिल्कुल ठीक बात कही थी कि सदन में जनता की मेहरबानी से कोई सत्ता पक्ष में आ जाता है तो कोई विपक्ष में। अध्यक्ष महोदय, मैं पांचवी बार इस महान सदन का सदस्य बनकर आया हूँ। मैने देखा है कि कुछ लोग जो कभी सत्ता पक्ष की सीटों पर आसीन होते थे आज वह विपक्ष की सीटों पर बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी तरह का भी कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए बल्कि इस महान सदन को सुचारू रूप से चलाने की हम सब सदस्यों की सांझी जिम्मेदारी है। पंडित कुलदीप शर्मा जी इस महान सदन के स्पीकर रहे और वह कई बार खुद भी कह जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो एक कोने में बैठा करते थे। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि हम अकेले–अकेले कोने में बैठते थे और हमें बड़ी मुश्किल से कोई बात कहने का मौका मिला करता था। आज जो पंडित कुलदीप शर्मा जी ने अनिल विज के बारे में कहा है उसे किसी भी सूरत में ठीक नहीं माना जा सकता है। उसके बाद भी अनिल विज जी ने उदारता दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस काल में यद्यपि हमें बिना बात के ही सदन से निकाल दिया जाता था लेकिन बावजूद उसके हमें कोई गिला नहीं है क्योंकि उस समय हमारी भूमिका ही ऐसी हुआ करती थी। आज हम हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता की कृपा से सत्ता पक्ष की सीटों पर बैठे है जो विपक्ष के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही कारण है कि पुरानी याददाश्त अभी इनके दिलो–दिमाग से निकल नहीं पाई है। कुलदीप शर्मा जी से जो एक बात निकल गई उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कुलदीप शर्मा जी कोई भी व्यक्ति छोटे बाप का नहीं होता है और अनिल विज के जी बारे में जो बात आपसे निकल गई है वह पुराने समय की याद करते हुए पुराने अंदाज में निकल गई जिसके लिए आपको महसूस करने की जरूरत है और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह चलने दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे एक बात कहनी बहुत जरूरी हो गई है और वह यह है कि वर्ष 1991 का भजन लाल जी का समय छोड़कर, दादा रामबिलास जी तो सदा ही सत्ता में रहे है, रूलिंग पार्टी में रहे हैं। जितनी मौज इन्होंने सत्ता की लूट रखी है उतनी किसी अन्य ने नहीं लूटी। (हंसी)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, इस विषय पर की सदन का समय जाया न किया जाये या फिर सदन में कोई ऐसी बेतुकी टिप्पणी न की जाये जिसकी वजह

से सदन में शोर–शराबा पड़े, न जाने कितनी ही दफा चर्चा हो चुकी है। आज प्रश्न काल 11 बजे खत्म हो गया। तब से लेकर अब तक 40 मिनट हो गए लेकिन इन 40 मिनट्स में सिवाय एक दूसरे पर छींटाकशी के कोई और चर्चा नहीं हो पाई है। सदन में यह बात भी कही जाती है कि आपके व्यवहार को पूरे प्रदेश के लोग देखते हैं, निःसंदेह प्रदेश के लोगों के साथ–साथ देश के लोग भी हमें देखते होंगे। इसके अतिरिक्त दूर–दूर से लोग यहां पर आकर पास बनवाकर सदन की कार्यवाही को देखते हैं। अगर इस तरह के अमर्यादित आचरण सदन में किए जायेंगे तो लोगों के बीच इसका क्या मैसेज जायेगा। पहले भी कई दफा इस सदन में कहा जा चुका है और आज भी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अमर्यादित टिप्पणी करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि अगर उनके प्रति यही नरम रवैया अपनाये रखा जायेगे तो फिर 100 फीसदी मानकर चलो कि यह लोग इसी तरह का अमर्यादित आचरण सदन में करेंगे क्योंकि इन लोगों की बराबर यही मंशा रहती है कि अखबार में इनके फोटों व खबर कैसे छपे और इसी वजह से यह लोग सदन का समय जाया करने में तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे। प्रश्न काल के बाद के 40 मिनट की सदन की कार्यवाही यदि आप देखें तो उसमें सिवाय छींटाकशी के कुछ नहीं मिलेगा अतः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिन जिन व्यक्तियों ने सदन में अमर्यादित आचरण किया है और जो सदन की मर्यादाओं के प्रतिकूल है, उन लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि सदन की मर्यादाओं को पैरों तले रोंदने वाले आज मर्यादित आचरण की बात करते हैं? इस तरह की बातें इनके मूंह को शोभा नहीं देती। इन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। यह लोग मां–बहन की गालियां तक देते थे। इन्हें अपनी काली करतूतों को याद रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई करोगे या इनको इसी तरह से बोलने की छूट दी जाएगी ? अगर आप इसी तरह से इन्हें बोलने की छूट देंगे तो हम सदन से चले जाएंगे । ये काली करतूतों की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि ये अपनी काली–करतूतों को याद करें । (विघ्न) इन्हें अपना दस साल का समय याद करना चाहिए । ये अपने दस साल का समय भूल गये हैं । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही निकालकर देखिये । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी को आपने बोलने का सर्टिफिकेट दे रखा है ? ये सारा दिन एक ही बात करते रहते हैं । इनको यह छूट भी आपकी वजह से ही है । आप इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आये थे । आपने जब इस सत्र में उसको पढ़ा तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि इन्होंने जो बात कही थी वह झूठ थी । इसके बाद भी प्रिविलेजजि कमेटी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है । इससे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है । अगर आप इन पर सख्त कार्रवाई करोगे तो सदन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सौ फीसदी नहीं किया जाएगा और हर सदस्य को बोलने से पहले सोचना होगा कि वह सदन में खड़ा होकर क्या बोल रहा है । ऐसे मुद्दों से केवल सदन का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का अपमान होता है । अतः आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि पहले माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को माफी मांगनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल द्वारा मेरे मना करने के बावजूद जो कुछ कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड न किया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं अगर आप उन पर बात करोगे तो आपको पिछले अढ़ाई वर्ष की कार्यवाही निकालनी पड़ेगी कि किसने क्या–क्या कहा है ? अगर ऐसा हुआ तो कई सदस्य सदन में नहीं रह सकेंगे जिनमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष पूरे विपक्ष का नेता होता है इसलिए इस पद पर आसीन व्यक्ति को सरकार को किसी विपक्ष के सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई के लिए डायरेक्शंज नहीं देनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय,मैं भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभय सिंह चौटाला जी को माफी मांगनी चाहिए । अगर ये माफी मांगते हैं तो हम भी माफी मांग लेंगे । (विघ्न) इन्होंने हरियाणा विधान सभा को बदनाम और मिसअप्रोप्रियेट किया है । इस बात को कौन नहीं जानता है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अगर सदन की कार्यवाही की बात की जाए तो मुझे नहीं मालूम कि यह सदन की कार्यवाही में आया है कि नहीं आया लेकिन सदन के सभी सदस्यों ने सुना है कि माननीय सदस्य कुलदीप शर्मा जी ने सदन में खड़े होकर मंत्री जी को यह कहा था कि मैं जब स्पीकर होता था तो मैं तेरे ***** बाहर निकालता था । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये तो विधायकों के हाथ–पैर तोड़ा करते थे । ये किस मुंह से ऐसी बातें कह रहे हैं । ये तो मंत्रियों को बंधक बनाकर हवाई जहाज में बिठाया करते थे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये बेचारा माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी गया था । इसके अलावा ये मेरे खिलाफ थाने में भी कम्पलेंट करके आया था । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित राम बिलास शर्मा के एक प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला इस डिस्कशन को बड़ी गम्भीरता से बड़े नैतिक स्तर पर लेकर गए हैं । मैं तो इस बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि –

उन मोमनों से मेरे इमान अच्छे
जिन मोमनों ने अपने इमान बेच डाले ।

अध्यक्ष महोदय, इसके माध्यम से मेरा कहना है कि जिन लोगों ने कभी सदन की मर्यादा की परवाह न की हो कम से कम वे तो जीसस क्राइस्ट न बनें । ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी मुझसे कभी यह न

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

कहें कि मैं कौन हूं । माननीय मंत्री जी मुझे यह बात दो बार कह चुके हैं । मैं बिल्कुल चुप बैठ गया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझ से कहा कि मैं मंत्री हूं, तू कौन है ? These are his words. यह रिकॉर्ड में है । (विघ्न)

श्री अनिल विजः शर्मा जी, मैंने पहले कोई ऐसी बात नहीं कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः विज साहब, आपने पहले ऐसी बात कही हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, पहले कुलदीप शर्मा जी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या करते थे। (शोर एवं व्यवधान) क्या वे बातें इन सभी माननीय सदस्यों को इनके बारे में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय विज साहब की बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी किस तरह से मार्शलों के साथ हाउस को चलाते थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं भी हरियाणा विधान सभा का अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय विज साहब किस तरह से सदन में व्यवहार करते थे, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने सदन को कलंकित किया था। (शोर एवं व्यवधान) इस बात को सारा हरियाणा जानता है कि प्रजातंत्र को किस तरह से आपने पैरा तले रौंदा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, सदन को कलंकित करने का काम विज साहब ने किया था। सारा हरियाणा जानता है कि विज साहब किस कलंक के प्रतीक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, सारा हरियाणा जानता है कि पहले शर्मा जी किस कदर सदन को कलंकित करने का काम करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, सारा हरियाणा जानता है कि विज साहब की मनोस्थिति कैसी रहती थी? (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं विज साहब की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, कुलदीप जी की मनोस्थिति ठीक नहीं है इसलिए इन्होंने अपना ईलाज करवाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, विज साहब को मेरे इस शब्द से तकलीफ है कि मैं इनको ** सदन से बाहर निकालता था। तो मैं *** अपना शब्द वापिस लेता हूँ लेकिन मैं इनको सदन से बाहर निकालता था तो इस बात को कैसे वापिस लूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

डिजिटल इंडिया अभियान से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 जोकि डिजिटल इण्डिया अभियान के बारे में है, प्राप्त हुई है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 पढ़ेंगे और उसके बाद संबंधित मंत्री उस पर वक्तव्य देंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हूँ कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल इण्डिया अभियान की शुरूआत दिनांक 1 जुलाई, 2015 को की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के सभी नागरिकों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधायें इलैक्ट्रॉनिक तरीके से दी जा रही है और इंटरनैट की कनैक्टिविटी तेजी से बढ़ी है और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा सरकार भी केन्द्र सरकार की तर्ज पर इस दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होगी एवं प्रदेश के नागरिकों को ई–संपर्क, ई–पेमेंट, ई–वॉलेट, एवं कैशलैस भुगतान की सुविधा दी जाएगी ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार की डिजिटल योजना के तहत

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

ई. गर्वनैंस के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए जा रहे है व इस क्षेत्र में अब तक राज्य सरकार का प्रर्दशन कैसा रहा? क्या प्रदेश में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास करके सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाए है। अतः उन्होनें निवेदन किया है कि इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक जो–जो कदम उठाए गए है उनके बारे में सरकार कृप्या सदन में वक्तव्य दे।

Shri Karan Singh Dalal: Speaker Sir, this is not a matter of recent occurrence. This is not a matter of urgent attention (intervention)

Smt. Kiran Choudhary: Speaker Sir, it is not relevant, it is not a matter of urgent attention. (intervention)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा दी गई विभिन्न ध्यानाकर्षण सूचनाओं को रिजैक्ट कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्हें किस नियम के आधार पर रिजैक्ट किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, अब यह मैटर समाप्त हो गया है। अगर आप कोई सप्लीमैंटरी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं लेकिन अभी सदन के नेता ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 के संदर्भ में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़े हैं इसलिए आप बैठ जायें और सदन के नेता को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने दें।

वक्तव्य–

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया है।

The three pillars of Digital India vision: Infrastructure as a service, e-Governance and services on demand and Empowerment of citizens have been entirely adopted and taken forward aggressively in the state of Haryana. Since 2014, Haryana has taken multiple steps for using technology to increase transparency, reduce delays, decrease corruption and create a progressive state digital economy.

The State has vigorously pursued strengthening of Digital Infrastructure and ensured rollout of National Optic Fibre Network to 4051 Gram Panchayats, connected 1277 offices to State Wide Area Network, provided wifi in 119 Gram Panchayats and connected all police stations with district and state headquarters through Crime and Criminal Tracking Network System.

With a vision to make all Government services accessible to the common man in his locality, through common service delivery outlets, and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to realise the basic needs of the common man, state has ushered in e-Kranti by providing more than 170 departmental services of 24 departments online to citizens through a network of more than 4000 Atal Seva Kendras in the villages and 125 e-Disha Kendras at district and block level. To reduce delays, increase transparency, redress public grievances and enhance office efficiency a number of e-Governance applications have been put in place viz. CM Window; e-auctions; e-procurement; e-registration; online transfers; e-payments; e-business portal; direct benefit transfer in Scholarships, pensions, etc.; various online approval systems for change of land use, Licences, permissions, buildings plans; and many more. To reduce delays in offices we have rolled out 'e-Office' application for electronic movement of files in ITI department and propose to introduce it in many more departments during the year.

To empower the citizens to bridge the digital divide, state has taken rapid strides in promoting digital literacy and information technology skills. State has trained 2.26 lakh candidates in Digital Literacy and 1.31 lakhs have earned digital literacy certificates. State has provided information technology skills to more than 50,000 persons during the year.

To promote various modes of cashless transactions, the state announced and transferred one-time welcome appreciation money of Rs. 5 in the bank account of the citizens who register under cashless modes and execute a successful transaction. Over 2 lakh transactions have been entered by citizens in the portal. We have organized Digi Dhan Melas in Gurugram, Sonipat, Panchkula and Faridabad to drive cashless payments under Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana. The Digi Dhan melas were followed by Basant Melas in February 2017, across the State, to promote cashless transactions. To promote e-payments nearly 800 Point of sale machines have been provided at e-Disha Kendras and department service counters for payment through credit/debit cards. Power utilities and Public Health have created facility for citizens to pay utility bills online. State has also introduced online purchase of e-Stamps.

To ensure that citizens, whether residing in urban or rural areas of Haryana, are able to receive government services in a timely manner we have notified 234 services of 25 Departments/Boards/Corporations under the Right to Service Act, 2014.

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू की जाती है। असीम गोयल जी, आप बजट पर अपनी बात रखें।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2017–18 के बजट अनुमानों पर बोलने के लिए समय दिया। मैं आपका आभारी हूं। स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर इस बजट में हरियाणा को स्वर्णिम राह पर ले जाने के लिए जो योजनाएं इस सरकार ने प्रस्तुत की हैं, उन योजनओं के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई)** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारा राज्य बेशक पंजाब से छोटा है। लेकिन इस बार हमारे हरियाणा राज्य ने पंजाब से भी बड़ा बजट पेश किया है। हमारा इस बार का जो

बजट है पहली बार 1 लाख करोड़ रूपये के आंकड़े को पार कर गया है। जिस प्रकार हरियाणा आगे बढ रहा है यह जो एक लाख करोड़ रूपये का आंकड़ा है यह बिना प्रिक्योरमैंट का आकंड़ा है जो खाद्यान के लिए प्रिक्योरमैंट के लिए पेमैंट की व्यवस्था सरकार करती है उसके अलावा 1 लाख करोड़ रूपये का जो बजट बनाया गया है ये सरकार की दूरगामी दृष्टि इस हरियाणा को आगे बढाने के लिए सरकार की जो सोच है, उसके ऊपर एक मोहर है। उपाध्यक्ष महोदया, पहली बार भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनायी और सरकार बनाते ही हरियाणा को एक अच्छा वित्तीय प्रबन्धन के साथ भारत वर्ष के अन्दर के सबसे अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा किया। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है चखकर तो देख। इस प्रकार की नीति सरकार का जो इस बार बजट पेश किया उसमें नीति है, नेता है और नीयत है इस बजट के अन्दर झलकता है। हरियाणा को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी बात जो हरियाणा के बजट के अन्दर लायी गयी है उसमें पहली बार हरियाणा को रैवन्यू डैफिसिट जीरो करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और आने वाले सालों में जो ग्रोथ हरियाणा की हो रही है उसमें पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसका रैवन्यू डैफिसिट पूरे भारत में जीरो हो जाएगा। पहले सारा बजट बनता था वह एक जाति, क्षेत्र तक सीमित रहता था। मुझे यह कहते हुए कोई हैरानी भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं

क्षमा के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पहले की जो *****(शोर एवं व्यवधान) सरकारें थी, जब वह बजट बनाती थी।(विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की शब्दावली का सदन में प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस तरह की शब्दावली को सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः श्री असीम गोयल ने जो आपतिजनक शब्द कहे हैं, उनको सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए।

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय दांगी साहब के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने क्षमा के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया है। वैसे

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

हमारे 4–5 बार सदन के सदस्य रहे सीनियर साथी अपने आचरण से हमें जो कुछ सिखाना चाहते हैं हम तो केवल वही सीख रहे हैं? ट्रेनिंग सैशन के दौरान हमारे माननीय सदस्यों ने अपने–अपने के वक्तव्य में जो हमें सिखाया, मैं तो केवल उसी आधार पर बात करना चाहता हूं। पहले जो बजट बनता था वह सिरसा, रोहतक, हिसार, भिवानी इन चारों जिलों के अलावा किसी दूसरे जिले का कोई बजट नहीं होता था। पहले जो सम्मानित मुख्य मंत्री रहे वे अपने जिलों तक ही बजट का फोकस रखते थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं यह हरियाणा की अढाई करोड़ जनता और जो उपेक्षित जिले हैं वे चीख–चीखकर इस बात की गवाही दे रहे हैं। पहली बार इस बजट में 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की झलक दिखाई देती है। वर्तमान सरकार का यह बजट हरियाणा की अढाई करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा की सरकार ने क्षेत्रवाद को पीछे रख कर यह बजट बनाया है इसके लिए सदन में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। इसी सूत्र को लेकर पहली बार हरियाणा के बजट को बनाया गया। पंचकूला से पलवल तक, कालका से होडल तक और होडल से नांगल चौधरी नांगल चौधरी से कालांवाली तक हरियाणा के सभी क्षेत्रों को इस बजट के अंदर टच किया गया है। सभी क्षेत्रों के विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया और पहली बार 9 ऐसे क्षेत्रों सरकार ने चुने जिनको इस बजट के अंदर 9वां ग्रह की उपाधि दी गई और ये 9 वां ग्रह इस प्रदेश के ढाई करोड़ सम्मानित जनता के सुख के लिए काम करें। इस बार बजट के अंदर कृषि के लिए 3206 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। ग्रामीण विकास के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 10,000 की आबादी के बड़े गांवों के लिए स्पेशल योजना लायी थी। इस बार 3,000 से लेकर 10,000 आबादी के जो गांव होंगे उनके लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना जो हमारी सरकार लेकर आई है, उसका प्रावधान भी पहली बार बजट में रखा गया है। शहरी विकास के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपये इस बजट में रखे गए। हमारी पार्टी के पहले सम्मानित आदरणीय स्वर्गीय श्री मंगल सैन जी जो उपमुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पर यह 'मंगल नगर विकास योजना' हमारी सरकार लाई है। इसी प्रकार

अवसंरचना के लिए सिंचाई, सड़कें, पेयजल, रेलवे, परिवहन लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। शिक्षा और आई.टी क्षेत्र के लिए लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा गया है कि किस प्रकार पहले हरियाणा के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो पहलू ऐसे हैं कि हरेक व्यक्ति को इनका लाभ पहुंचे, इस बार स्वास्थ्य के लिए भी लगभग 3,900 करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। युवा के विकास के लिए मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब केन्द्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो तत्कालीन सरकार ने पहली बार युवा विभाग बनाने का काम किया था। उसी को आज प्रतिपादित करते हुए हरियाणा के अंदर भी लगभग 336 करोड़ रुपये का बजट इस सरकार ने युवाओं के विकास के लिए रखा है। नौवीं बात मैं संस्कृति और पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं। टूरिज्म के नाते कृष्णा सर्किट बनाने की बात कही गई है। कुरूक्षेत्र को लेकर बहुत बातें हुईं, गीता को लेकर बहुत बात हुई, लेकिन इस गीता और कुरूक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पहली बार ठोस कदम इस सरकार में उठाये गए। चाहे बह्म सरोवर की बात हो, ज्योतिसर की बात हो, नरकातारी की बात हो, सनहित सरोवर की बात हो, इनके विकास के लिए पहली बार ठोस कदम इस बजट में उठाए गए हैं। रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, माधवपुर जो टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एक हेरिटेज सर्किट जो विकसित करना है, उसके लिए भी पहली बार ऐसे ठोस प्रयास हुए। चाहे राखी गढ़ी की बात हो जो हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति की बात हो, जो हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति जिसके बारे में कहा जाता है राखीगढ़ी और कुनाल के अंदर इसके अवशेष मिले हैं। उनको चाहे पूरे संसार के सामने रखने की बात हो और जो वामन भगवान हम कहते हैं कि भगवान विष्णु का पाचवां अवतार है। उनको अवतार मानते हैं और उनका जन्म हरियाणा में हुआ । पहली बार वामण भगवान का अवतार स्थल हमारी सरकार बनाने जा रही है । इसी तरह से शहीद स्मारक भी अम्बाला में हमारी सरकार बनाने जा रही है ताकि जो सैनिक सीमा पर तैनात रहकर हमारी रक्षा करते हैं ताकि देश में हम अमन–चैन से रह सकें । उनकी शोर गाथाओं के बारे में युवाओं को जानकारी देकर देशभक्ति की भावना पैदा की जा सके । हमारी सरकार शहीद स्मारक इसीलिए बनाने जा रही है ताकि हमारे वीर सैनिकों से हमारे प्रदेश के युवा

प्रेरणा ले सकें । यह शहीद स्मारक करोड़ों रुपये की लागत से बनेगा और बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान भी किया गया है । इसी तरह से हमारी सरकार ने सिख संग्राहलय बनाने का भी निर्णय लिया है जिसमें गुरू गोविंद सिंह जी से संबंधित सारी चीजें उसमें होंगी । गुरू गोविंद सिंह जी ने देश के लिए अपने वंस तक की कुर्बानी दे दी थी । जिनके बारे में कहा जाता है कि पिता वार्या, ते लाल चार वारे, हिंद तेरी शान बदरे । उनकी महानता को दर्शाने के लिए सिख संग्राहलय बनने जा रहा है जिसके लिए बजट में पैसे का भी प्रावधान रखा गया है । इसी तरह से हरियाणा को फिल्म निर्माण के अनुकूल बनाने के लिए फिल्म नीति बनाने की भी घोषणा की गई है । उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा की जी.डी.पी. 6 लाख करोड़ रुपये से उपर मानी जाती है । हमारी जो टी.आर.आर. रेशो थी वह 2014 में पिछली सरकार ने 9.3 प्रतिशत पर छोड़ी थी । उससे पहले यह रेशा 14 प्रतिशत तक बढ़ गई थी । पिछली सरकार के लोगों का तो खजाना बढ़ गया था लेकिन सरकार की हालत खराब हो गई थी और उस सरकार ने रिकवरी के उपर ध्यान नहीं दिया । पिछली सरकार ने प्रदेश के लोगों को ही गरीब करने का काम नहीं किया बल्कि पूरे प्रदेश को ही गरीब और कर्जदार करने का काम किया । लेकिन हमारी सरकार ने अपने अढ़ाई साल के कार्यकाल में हरियाणा को पटरी पर लाने का काम किया है और टी.आर.आर. रेशो दोबारा से 11.3 प्रतिशत पर आ गया है । यही वजह है कि हमारी सरकार ने बिजली कंपनियों को ब्याज दर में झूठ देकर घाटे से उभारा है जिसके कारण 20 सालों में पहली बार एफ.एस.ए. 37 पैसे कम हुआ है जो कि अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है । आज हमारा प्रदेश पूरे देश में पर कैपीटा इनकम में पहले नम्बर पर है और हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीबन 1,80,000 रुपये है जो कि पूरे देश में नम्बर एक है । यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाये तो हरियाणा भारत का 1.4 प्रतिशत है और जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा 2.9 प्रतिशत है । जबकि देश की जी.डी.पी. में हरियाणा 3.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों को संतुलित करने के लिए सबका साथ–सबका विकास की पॉलिसी लेकर आई है । मैं सर्व स्पर्शी, सर्वजन सुखमय और सर्व हितकारी, बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बजट में जो कल्याणकारी प्रावधान रखे गये हैं उनका अनुमोदन

करता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, अंत में एक श्लोक कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि–

यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
एक जनून को दिल में जगाना पड़ता है,
पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला,
बोली भरनी पड़ती है उड़ान व तिनका–तिनका उठाना पड़ता है ।

इसी नीति के साथ हमारी सरकार पूरे हरियाणा को आगे ले जाने का काम कर रही है । इसके लिए मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । धन्यवाद । जय हिंद, जय हरियाणा ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट भाषण पर होने वाली चर्चा में बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम तो आपका इसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का भी धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रात–दिन अथक परिश्रम करके और पता नहीं कहां–कहां से आंकड़े इक्ट्ठे करके बजट तैयार किया। इस बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार की हरियाणा प्रदेश की जनता से अढ़ाई साल के दौरान और उससे पहले किये गये वायदों की वायदाखिलाफी झलकती है। इस समय हरियाणा प्रदेश में धरातल पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश की जनता में सरकार और सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष व्यापत है। सरकार का यह बजट दिशाहीन है। इसी प्रकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी पूरी तरह से डांवाडोल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहूंगा कि उनका टाईटैनिक डूब रहा है और इतना ही नहीं उनका टाईटैनिक बहुत तेजी के साथ डूब रहा है। वे मेरी इस बात को नोट कर लें। यहां पर असीम गोयल जी ने बजट के बहुत कसीदे पढ़े और बजट की तरह–तरह से प्रशंसा करके बहुत से लड्डू बिखेरने की कोशिश की । ये लड्डू अखबारों में बिखेरे गये और विधान सभा में भी बिखेरे गये। यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं कि सत्तापक्ष के माननीय साथियों का यह दायित्व होता है कि वे अपनी सरकार के बजट की वाहावाही करें लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सत्तापक्ष के साथियों को बजट की कमियों की ओर भी सरकार

का ध्यान दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहां यह बात भी बड़े उत्साह की साथ कही गई कि कैप्टन अभिमन्यु जी पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं और उनकी फाईनैंशियल एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी है। हम भी यह चाहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में सार्थक पहल करने के उद्देश्य के लिए ये अपना बजट प्रस्तुत करते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि बजट से और कैग की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा प्रदेश एक गम्भीर वित्तीय संकट की ओर जा रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बात को नोट करें और इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श करें क्योंकि इससे हरियाणा प्रदेश का व्यापक हित जुड़ा हुआ है। प्रदेश इसलिए वित्तीय संकट की ओर जा रहा है क्योंकि हरियाणा प्रदेश का रेवेन्यू डैफिसिट वर्ष 2011–12 में 1451 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 11,679 करोड़ रूपये हो गया है। इस प्रकार से प्रदेश के रेवेन्यू डैफिसिट में इन चार सालों में 8 गुणा वृद्धि हुई है। यह किसी भी दृष्टि से कोई छोटी बात नहीं है। हमारे अधिकारी इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक ऐसी दयनीय स्थिति है जिसको जल्दी से जल्दी नोटिस करना चाहिए। इसी प्रकार से फिस्कल डैफिसिट अर्थात जो राजकोषीय घाटा होता है वह वर्ष 2011–12 में 3152 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 31,479 करोड़ रूपये हो गया है। जो कैग की रिपोर्ट आई है मैं उसके फैक्ट्स भी यहां पर बताऊंगा। मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनको उसका जवाब बजट प्रस्तुत करने से पहले देना चाहिए था लेकिन अगर वे बजट पर रिप्लाई के समय भी इसका जवाब देंगे तो भी ठीक है। जो राजकोषीय घाटा है वह बढ़ा है। इसके विपरीत असीम गोयल जी ने कहा कि राजस्व घाटे कम हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे यहां पर यह भी बताते कि कौन से घाटे कम हुए। जैसा कि मैंने यह बताया कि फिस्कल घाटा चार साल में बढ़कर 10 गुणा हो गया अर्थात जमद जपउमे पद विनत लमंतेण महोदया, यह कोई छोटी बात नहीं है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ. कादियान जी जिन चार साल का जिक्र कर रहे हैं उसमें दो साल उनकी गवर्नमैंट के भी है। इसलिए इस बात को भी नोट किया जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार के समय में तो यह घाटा 3,152 करोड़ रूपये था। वित्त मंत्री जी अपने जवाब में इस बारे

में स्थिति स्पष्ट कर दें । मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है और इसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। पूरा प्रदेश इस बजट की तरफ देख रहा है। जो बजटीय घाटे हैं वे निरंतर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महोदया, अब मैं फिस्कल लॉयबिलिटी के बारे में बात करना चाहूंगा कि फिस्कल लॉयबिलिटी जो डैट अर्थात् जो लोन की लॉयबिलिटी है उसकी दिशा और दशा क्या है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर पर भी 50000 रूपये का कर्ज होगा। इसी प्रकार से फिस्कल लॉयबिलिटी वर्ष 2011–12 में 54540/– करोड़ रुपये तथा वर्ष 2012–13 में 64818 करोड़ रुपये हो गई । इसी तरह से वर्ष 2013–14 में 76,000/– करोड़ रुपये तथा वर्ष 2014–15 में 88446/– हो गई । उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन आंकड़ों को नोट कर लें तथा जब वे अपना जवाब दें तो इन सारी बातों का जवाब दे दें । इसी प्रकार से वर्ष 2015–16 में 1,20,718/– करोड़ रुपये तथा वर्ष 2017–18 में बढ़ कर वही फिस्कल लायबिलिटी 1,41,854/– करोड़ रुपये हो गई । वाह रे वित्त मंत्री जी आपने कमाल कर दिया ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. कादियान से निवेदन करना चाहूंगा और उनकी इन्टरविन मेरे लिए और इस सदन के लिए बहुत जरूरी भी है लेकिन वे तय तो कर लें कि वे फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं या डैट की बात कर रहे हैं कर रहे हैं । मुझे लगता है कि इनको फिस्कल लायबिलिटी, डैट और फिस्कल डेफिसिट में कुछ कंफ्यूजन हो गया है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है । फिस्कल लायबिलिटी, डैट और लोनिंग तीनों एक ही चीज हैं । अगर तीनों में कोई अन्तर है तो वित्त मंत्री जी सदन को बता दें । इन तीनों में कोई फर्क नहीं है और अगर कोई अन्तर है तो वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बता दें ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो डॉ. कादियान से सीखना चाहता हूं । मैंने तो इनसे निवेदन किया था कि ये कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गये हैं । मैं अपने जवाब में एक–एक शब्द को नोट करके जवाब दूंगा । यह मेरी जिम्मेदारी है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी प्रोटक्शन चाहता हूं । मेरा समय बर्बाद हो रहा है इसलिए मंत्री जी इन सारी बातों का जवाब अपने जवाब में दे दें । फिस्कल लायबिलिटी, डैट और लोनिंग अगर अलग–अलग हों तो ये सदन को बता दें । उपाध्यक्ष महोदया, आज वर्ष 2017–18 की 1,41,854 /– करोड़ रुपये की फिस्कल लायबिलिटी है जो कि बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीसन है । यह ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे कोई निकम्मा आदमी शराब पी कर अपनी जमीन बेचता है, कर्ज ले लेता है यह उसी निकम्मेपन को दर्शाता है । इतना जबरदस्त लोनिंग सरकार के ऊपर खड़ी है । 2 साल पहले तक यह उतनी नहीं थी जितनी आपकी सरकार आने के बाद हो गई है ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. कादियान को कहना चाहता हूं कि वे अपने शब्दों को याद रखें । वे जिस निकम्मेपन की बात कर रहे हैं ये उस पर कायम रहें । मैं यह बात साबित करके दिखाऊंगा कि वह निकम्मापन किसका था और उस निकम्मेपन के लिए कौन–कौन जिम्मेदार था ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2007–08 में यह फिस्कल लायबिलिटी 29118 करोड़ रुपये थी यानि 30 हजार से नीचे। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था । हरियाणा के गठन में हरियाणा के लोगों ने अपने डिस्क्रिमनेशन के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था । जब अलग हरियाणा का गठन तो हिन्दुस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह बात कही थी कि क्या हरियाणा के पास इतने रिसोर्सिज हैं कि वह प्रदेश को चला सके । 1966 में स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी की कलम से हरियाणा बनने के बाद वर्ष 2008 तक हरियाणा की फिस्कल लायबिलिटी 42 साल में 30 हजार करोड़ रुपये से नीचे रही थी लेकिन उसके बाद वर्ष 2016–17 तक यह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उपाध्यक्ष महोदया, यह गजब की फिगर है। लेकिन यह एक ऐसे बजट को दर्शाता है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की नीयत और नीति पर भी मैं सवालिया निशान खड़ा कर रहा हूं । यह मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि वर्ष 2007–08 में लोनिंग पर जो इंट्रस्ट जाता था वह 2341 करोड़ रूपये की पेमेंट थी ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, इसमें मैं माननीय सदस्य को एक तथ्य ध्यान कराना चाहता हूं कि जब हरियाणा बना तो हरियाण बनने में उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था क्योंकि हरियाणा वर्ष 1966 में बना था । अगर

इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उसमें कोई रोल होता तो वह बहुत बाद में शुरू होता ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान :उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कलम से हरियाणा बना था । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है । हरियाणा जो बना है वह उन लोगों की वजह से बना है जिन्होंने जेलें काटी थी और जो हरियाणा के लिये संघर्ष कर रहे थे लेकिन कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे । हरियाणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कलम से नहीं बना । हरियाणा बना उन लोगों की वजह से जो लोग जेलों में जा रहे थे । (शोर एवं व्यवधान) उनके संघर्ष की वजह से हरियाणा बना है । यही माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य था ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी जो कह रहे हैं कि हरियाणा लोगों के संघर्ष से बना है वह सही है लेकिन उस समय प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही थी । उनके समय में ही यह सारा का सारा तय होकर हरियाणा को अलग बनाया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, सदन में इतनी बड़ी–बड़ी बातें कही जा रही हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में क्या कोई ऐसा सदस्य मौजूद है जिसने यह समय देखा हो ? बिना मतलब की बात नहीं करनी चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हरियाणा बना तब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और सैंट्रल कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया था तब हरियाणा बना था । हरियाणा श्रीमती इंदिरा गांधी की कलम से बना है । इसमें कोई दो राय नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्ष के साथी ने यह सवाल किया है कि यहां पर कोई स्वतंत्रता सेनानी है । मैंने इस महान सदन को पहले भी कहा है कि हरियाणा बनाने के संघर्ष में अनेकों लोग शामिल थे । वह बताएं कि वह कौन–कौन लोग शामिल थे । मेरे खुद के पूज्य पिता जी हरियाणा बनाने के आन्दोलन में वर्ष 1957 में सत्याग्रह आन्दोलन में चार महीना जेल में रहे । आप

हमसे पूछ रहें हैं कि हरियाणा बनाने में कौन–कौन शामिल थे । आप बताइये कि कौन शामिल थे, कौन जेलों में गये थे ? ये इंदिरा गांधी को श्रेय देना चाहते हैं कि उनकी एक कलम से हरियाणा प्रदेश बना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा बनाने के जितने भी दस्तावेज आए हैं । उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और उनकी कलम से हरियाणा बना । मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूं लेकिन जहां तक हरियाणा बनाने में जो रोल की बात आ रही है । उसमें हरियाणा के संघर्ष के समय जितने लोगों के नाम आए हैं वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बहुत पहले के आए हैं । सारे दस्तावेज हमने पढ़े हैं उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं है ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कलम से हरियाणा बना था । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आप एक मिनट में अपनी बात को कन्कलूड करें ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, आपने तो कमाल कर दिया । ऐसा है जी मेरे पास लैप है और जब मैं बोलता हूं तो उसको ऑन कर लेता हूं और जब मैं बैठता हूं तो उसको बन्द कर देता हूं । आप अपना रिकॉर्ड देख लें कि मैं कितनी मिनट बोला हूं । अगर आप इस सारे का रिकॉर्ड करो तो उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय वर्ष 2007–08 में लोनिंग पर 2341 करोड़ रूपये इंट्रस्ट जा रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आपने 12 बजकर 8 मिनट पर बोलना शुरू किया था ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब वह इंट्रस्ट 11257 करोड़ रूपये जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से वित मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वह किस दिशा में बजट को जीरो की तरफ ले जा रहे हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, हम तो इनकी सरकार के समय में लिये गये लोन का इंट्रस्ट चुका रहे हैं ।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश पर तीन साल में दुगुना कर्जा हो गया है। इस सरकार ने पूरे

प्रदेश को कर्जे के नीचे डुबो दिया है। आज हर आदमी ये हिसाब लगाता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, प्रदेश, देश कैसे चलेगा ? लेकिन मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि सरकार की जो नीति और नीयत है वह इसमें दर्शाती है कि सरकार प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहती है । इस संबंध में कैग ने भी बहुत सवाल उठाए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, समय डिवाईड किया हुआ है जितना ज्यादा समय आप लेंगे फिर आपके दूसरे साथियों को उतना ही कम समय मिलेगा ।

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, कैग ने भी हरियाणा प्रदेश के हर विभाग में बरती जा रही अनेक अनियमितताओं पर सवाल उठाये हैं और मैं समझता हूँ कि कैप्टन साहब को इन अनियमित्तताओं का जवाब जरूर देना चाहिए? कैग की रिपोर्ट बताती है कि एक साल से प्रदेश की 2865 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली अधर में लटकी हुई है और प्रदेश में स्थित कम्पनीज लगभग 2126 करोड़ रूपये के घाटे में चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यदि बजट को पढ़कर देखते है तो यह बात सामने निकलकर आती है कि बजट में हर क्षेत्र के लिए महज पांच से सात प्रतिशत बजट का ही प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, एग्रीकल्चर और इससे जुड़ी कई इकाईयां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हरियाणा प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है और खेती करके अपना जीवन यापन करती है। बजट में पॉवर और नॉन कंवैंशन एनर्जी का भी जिक्र किया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 में इस क्षेत्र के लिए 24 हजार 88 करोड़ का प्रावधान रखा गया था जबकि वित्त वर्ष 2017–18 में इसके लिए लिए महज 12 हजार 685 करोड़ रूपये का ही प्रावधान किया गया है। मतलब यह कि पॉवर और नॉन कंवैंशन एनर्जी के क्षेत्र में रखा गया बजट आधा ही रह गया है अर्थात पूर्ववर्ती बजट का लैस दैन फिफटी परसेंट इस क्षेत्र के लिए प्रावधान रखा गया है। इसी तरह इरीगेशन के लिए वित्त वर्ष 2015–16 में 2223 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया था जब कि वित्त वर्ष 2017–18 में इस क्षेत्र के लिए 2724 करोड़ रूपये की नोमिनल इंक्रीज की गई है। आज प्रदेश में कैनालज का बहुत बुरा हाल हो चुका है, कोई चैनल ठीक नहीं है, पानी की कमी बनी हुई है, सीपेज, परकोलेशन और वाटर, यूं कहें कि हर क्षेत्र में प्रदेश का सारा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी। कप्तान साहब, कहा गया आपका घोषणा पत्र? स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के

लिए धनखड़ साहब कुर्ता–कमीज पता नहीं क्या क्या पहनकर घूमते थे। धनखड़ साहब, कहा गई स्वामीनाथन रिपोर्ट?(शोर एवं व्यवधान) बराला साहब, कहां गया आपका घोषणा पत्र? कहां गई स्वामीनाथन रिपोर्ट? उपाध्यक्ष महोदया, बराला साहब भी लोगों के साथ कभी ट्रैक्टर तो कभी साईकल पर बैठकर घूमते थे और कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवायेंगे, कहां गई अब वह स्वामीनाथन रिपोर्ट?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनोष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूँगा कि ज्यादा नाटकबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, इन्होंने उस समय जो देखा था, उसे बता देना चाहिए, बस बात खत्म? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी के अढ़ाई साल के कार्यकाल में आज प्रदेश में किसान दुर्गती की कगार पर पहुंच गया है। आज प्रदेश की नहरों में पानी तक नहीं है। लोगों को सही समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है? जीरी का भाव बाजार में पिटा–पिटा घूम रहा है। बाजरे का भी भाव बाजार में पिटा हुआ है। यही नहीं जीरी के मामले में प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और यदि आने वाले समय में इसकी इंक्वॉयरी होगी तो जीरी का यह घोटाला सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा? उपाध्यक्ष महोदया, कपास के भाव भी बजार में पिटे–पिटे फिर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, विडम्बना देखिये जो गेहूं बाहर से आता था उस पर 25 प्रतिशत टैक्स लगा करता था लेकिन आज इस सरकार के समय में उस 25 प्रतिशत टैक्स को हटा दिया गया है जो एक तरह से किसानों के साथ अन्याय साबित होगा? उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहां–कहां की बात करूं, हर क्षेत्र में किसान की दुर्गति करने का काम किया जा रहा है। आज मैं दावे के साथ इस सदन में घोषणा करता हूँ कि आने वाले दो महीने के समय में हिंदुस्तान के किसान का गेहूं का रेट मंडियों में पिटा–पिटा फिरेगा? उपाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश के चुनावों के सिलसिले में मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण सुना था, वह कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो ..(शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी को इन ख्याली पुलावों को छोड़ देना चाहिए? कैप्टन साहब ने होप सस्टेस लाईफ वाली लाली पोप चूस रखी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का कतई सत्यानाश बिठा दिया है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मेरी बात आधी रह गई थी। उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भाषण के दौरान कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो किसानों के कर्जे माफ करूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, सब जानते हैं कि कितना कर्जा किसान का इन्होंने माफ किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख करोड़ रूपये का कर्जा देश के पूंजीपतियों और साहूकारों का ही माफ किया है। आम आदमी कर्जा लेता है तो उसके पीछे जीपें घूमती है, कर्जा लेने वाले के वारंट तक हो जाते हैं, उसकी धरती नीलाम कर दी जाती है, उसको अरेस्ट करने का काम किया जाता है, उसको हथकड़ियां लगाई जाती है लेकिन जिन लोगों के उपर 11 लाख करोड़ रूपये का कर्जा है, क्या उन लोगों पर सरकार ने कभी हाथ डाला? उपाध्यक्ष महोदया, किसी भी ऐसे बड़े कर्जदार के उपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हाथ नहीं डाला गया बल्कि ऐसे बड़े लोगों के दो लाख करोड़ रूपये माफ कर दिए गए। अकेले विजय माल्या के कर्ज के 12 हजार करोड़ रूपये माफ करके उसे सरकार की तरफ से लोली पोप देने का काम किया गया। यही नहीं अड़ानी, साहू, जैन, मोदी तथा सिंघानिया जैसे बड़े घरानों के भी कर्ज माफ किए गए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं वास्तव में सरकार ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इस तरह के आरोप बेबुनियादी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ज्ञान चंद गुप्ता जी से पूछना चाहूँगा कि जो यह इतना कूद–कूद कर बात कर रहे हैं, यह बतायें कि सरकार ने इनका कितना कर्जा माफ किया है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः उपाध्यक्ष महोदया, दांगी साहब बिना आपकी परमिशन के उठकर बोलने लग गए हैं। यह गलत बात है। आज यह किसान हितैषी होने का ढोंग कर

रहे हैं। इनकी सरकार में फसल ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था और किसानों को गुमराह करते थे कि 3 प्रतिशत ब्याज रिफंड हो जायेगा और 4 प्रतिशत ब्याज ही चार्ज किया जायेगा लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही फसल ऋण पर ब्याज दर को शून्य कर दिया है, अब यह स्वयं पता चल जाता है कि किसान हितैषी सरकार कांग्रेस की थी या भारतीय जनता पार्टी की? (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए अलाऊ किया हुआ है लेकिन पवन सैनी जी मुझे अपनी बात कहने से वंचित कर रहे हैं, जबकि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 97 (2) के तहत स्पीकर की परमिशन के बगैर कोई सदस्य सदन में नहीं बोल सकता । 8 नवम्बर को नोटबंदी हुई और 500 तथा 1000 रूपये के नोट बंद कर दिये गये और देश की लगभग 14 हजार करोड़ रूपये की करंसी को कागज का टुकड़ा बना दिया गया । इस निर्णय के लिए सरकार द्वारा यह दलील दी गई कि इससे देश का कालाधन बाहर आएगा, आतंकवादी गतिविधियों पर चोट लगेगी, नकली करंसी और ड्रग्स पर भी चोट लगेगी । ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 96 परसेंट ब्लैक मनी बड़े–बड़े सेठ–साहूकारों की रियल एस्टेट कम्पनीज में, ज्वैलरी में, शेयर्ज में, सोना–चांदी में लगी हुई थी । सौ परसेंट में से 96 परसेंट ब्लैक मनी रियल एस्टेट आदि में लगी हुई थी और सिर्फ 4 परसेंट ब्लैक मनी नोट की शेप में थी । सिर्फ 4 परसेंट ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी लागू कर दी गई और पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया । इस दौरान बैंकों की लाइन में खड़े होने से 131 आदमियों की मौत हो गई । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है । दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है, अतः आप प्लीज बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे बोलने के 5 मिनट कम कर दीजिए लेकिन माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह कादियान को अपनी बात पूरी करने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, आप माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए । आप मुझे बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दीजिए । ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, उस फैसले का हमें क्या फायदा हुआ ? न कालाधन आया, न आतंकवाद की गतिविधियों पर कोई असर पड़ा और न नकली नोटों पर कोई चोट पड़ी । ये तीनों मुद्दे ऐसे के ऐसे ही रहे । इस फैसले के वक्त कहा गया कि हिन्दुस्तान का काला धन हजार रूपये के नोटों के रूप में है । अगर हजार रूपये के नोट के रूप में कालाधन रखा हुआ था तो फिर 2 हजार रूपये का नोट क्यों शुरू किया गया ? मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है ? यह सरकार मोहम्मद तुगलकी फैसले करके देश को बर्बादी और तकलीफ के रास्ते पर ले जाना चाहती है । मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं । (विघ्न)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, श्री अशोक अरोड़ा भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा एवं पूर्व मंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, इण्डियन नैशनल लोकदल जो सदन की वी.आई.पी. दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं मैं सदन की तरफ से उन का अभिनन्दन करता हूँ ।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा(पुनरारम्भ)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर मैडम, केन्द्र सरकार की तरफ से एक फैसला आया और उसके आते ही जिस ढंग से देश को नुकसान हुआ उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है । इससे जितने छोटे कारोबारी थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, कर्मचारी थे उससे हर आदमी को तकलीफ झेलनी पड़ी है । डिप्टी स्पीकर मैडम, आप देखिये कि इससे हमारे प्रदेश के किस क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ है । नोटबंदी से जगाधरी और रिवाड़ी का मोर दैन 60 परसेंट मैटल उद्योग बंद हो गया, यमुनानगर का प्लाइवुड धंधा खत्म हो गया । यमुनानगर के बारे में स्पीकर साहब भी बता सकते हैं । इससे करनाल में चावल का धंधा, रोहतक में नट–बोल्ट का धंधा, सोनीपत में साइकिल का धंधा, फरीदाबाद और गुड़गांव में ऑटोमोबाइल का धंधा बंद हो गया । पानीपत में खादी का धंधा खत्म हो गया । (शोर एवं व्यवधान) महीपाल ढांडा जी, आप हाउस को आश्वस्त कीजिये कि पानीपत में खादी का कितना धंधा बंद हो गया । तकरीबन दो लाख लोग पेट के लिए प्रदेश से पलायन कर गये । उनके पास कैश नहीं था । मैं वित्त मंत्री कप्तान साहब को बताना चाहूंगा कि इससे जी.डी.पी. भी एक परसेंट नीचे आएगी और

प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो जायेगा । डिप्टी स्पीकर मैडम, आप विधान सभा के स्पीकर की चेयर पर बैठी हो, यहां सदन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ चुने हुए 2–2 लाख लोगों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, प्रैस गैलरी में मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स गैलरी में अधिकारीगण और दर्शक दीर्घा में विजिटर्स भी बैठे हैं, हमारे देश में 35 करोड़ परिवार हैं और तकरीबन 60 लाख परिवार हरियाणा में हैं, मैं इन सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप कोई एक परिवार ऐसा बता दो जिसकी आर्थिक शक्ति कम न हुई हो । मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट, चार एकड़ जमीन और एक घर था, अगर मेरी एक करोड़ की आर्थिक शक्ति थी तो नोटबंदी के बाद मेरी आर्थिक शक्ति घटकर 40–50 लाख रह गई है । नोटबंदी ने पूरे हिन्दुस्तान के हर परिवार और व्यक्ति की आर्थिक ताकत को तोड़कर रख दिया है । डिप्टी स्पीकर मैडम, इस देश को कहां लेकर जाया जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान) अगर कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर अपनी जायदाद बताए तो मैं बताऊंगा कि उसकी पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है । इस फैसले ने हर व्यक्तिगत आर्थिक ताकत को कम किया है । ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम, यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बहुत लोगों ने इस फैसले को कंडम किया है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2012 में वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत और विदेश में कालाधन से निपटने के उपायों के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था । उपाध्यक्ष महोदया, इस कमेटी ने साफ कहा था कि कालाधन जो अधिकतर बेईमानी संपत्ति जवैलरी के रूप में मौजूद है उससे निपटने के लिए विमुद्रीकरण का तरीका ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि विमुद्रीकरण के मामले में प्रधानमंत्री को सही सलाह नहीं दी गई। उपाध्यक्ष महोदया, जो सही फैक्ट्स हैं वे आपके माध्यम से सदन में लाना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, नोटबंदी से ध्यान हटाने के लिए इस बात का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कालाधन धारकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतना बड़ा फैसला ले लिया है। क्योंकि बिहार में चुनाव हार गए थे वैसी हालत आगे ना बने क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड आदि प्रदेशों में भी चुनाव के लिए जाना था और आगे गुजरात जैसे प्रदेशों में भी चुनाव होने हैं। you cannot make the fool of all the people for all the time पूरे देश को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। (विघ्न)

(Education Minister) Shri Ram Bilas Sharma: Madam Deputy Speaker, Hon'ble Dr. Raghuvir Singh Kadian is a Dr. from Agriculture University, Hisar. (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, फरीदाबाद, भिवानी और चण्डीगढ़ के नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। उपाध्यक्ष महोदया, हुड्डा साहब को मैंने वादा किया हुआ है कि इस बार होली के त्यौहार पर आपको भगवा रंग अच्छा लगेगा क्योंकि यू.पी. समेत पांच राज्यों में विधान सभा के नतीजे 11 मार्च, 2017 को आ रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, आज प्रदेश के लोग राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो कुल कालाधन सिर्फ 4 प्रतिशत करैंसी के रूप में 4–5 लाख करोड़ रूपया बनता था वह कितना जमा हुआ है? प्रदेश की जनता दूसरा सवाल यह पूछना चाहती है कि नोटबंदी के कारण यह कहा गया था कि आतंकवादी की गतिविधियों पर विराम लगेगा। क्या इससे आतंकवादी गतिविधियां कम हुई है? बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : कादियान जी, यह सवाल लोकसभा में जाकर पूछना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक जमींदार हूँ। मेरे पास 18 एकड़ की जमीन थी, जिसकी कीमत 9 करोड़ रूपये थी। विमुद्रीकरण के कारण मेरे 18 एकड़ की कीमत सिर्फ 1.80 करोड़ रूपये की आर्थिक शक्ति रह गई। विमुद्रीकरण ने मेरा 50 लाख एकड़ की जमीन को 10 लाख रूपये में बदल दिया।

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आपके बोलने का समय खत्म हो गया है। अगर आपकी कुछ बातें रह गई हों तो वे सदन के पटल पर रख दें। इसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना दिया जायेगा।

***डॉ. रघुवीर सिंह कादियान :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों का मेरी बात शांतिपूर्ण ढंग से सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) ठीक है, उपाध्यक्ष महोदया मैं सदन के पटल पर रख देता हूँ।

———————————————————————————————

* चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।

Beri

1. Round about (Four)
2. Polytechnic Women College
3. Bus Stand (out side near Mini Secretariat) on Beri-Jhajjar road
4. Sub-Depot of Haryana Roadways at Beri
5. Huda Sector
6. Bye Pass
7. Herbal Park in Chajjan Pana
8. Community Centre
9. Government College for Women

Dhubaldhan

1. Sub-Centre for Grain Market
2. Bye-Pass on North Side Dubaldhan, Kirman
3. Community Centre Dubaldhan,
    1. Kirman Pana,
    2. Ghikyan Pana
    3. Bidhayan Pana

Roads

Important Roads which may be constructed as soon as possible

1. Beri-Sheria road to Putlia Baba Ka Mandir
2. Chhara to Kultana
3. Chhara to Rewari Khera (Straight way along with Drain)
4. Beri-Dubaldhan road to Baba Tuta Ka Mandir
5. Bhadurgarh road to Mata Devi Ka Mandir (Chhara)
6. Manala Pond to Shiv Mandir (Chhara)
7. Beri- Dujana road to Nirachia Ka Mandir
8. From Matan Village to Chanderbhan Samadh (Freedom fighter)
9. From Matan village to Dada Hikamwala Mandir (2 K.M.)
10. Majra (D) PWD road to Piliawala Pond
11. Bye-Pass for Chhara village on South side
12. Bye-Pass for Dubaldhan on North side
13. Bye-Pass for Matan village on Bhadurgarh-Beri road
14. Bye-Pass for Beri town, Beri-Kalanor road to Beri-Jhajjar road

Irrigation

1. Extention of Rewari Khera Minor upto Kablana
2. Chhudani drain (Kharman, Chhudani to KCB drain
3. Bishan minor (Allocation of Time)
4. Bhambewa Minor (Allocation of time)
5. Drainage (Bhambewa, Dimana Chuliana) to KCB drain

6. Drain from Rohad to Kharhar
7. Drainage for 250 acres land at Dhaur
8. Drain for flood water village Dharana
9. Bridge over KCB Drain for Bhaproda village
10. Dighal Drainage for village flood water
11. Dabodha Sub-Minor abandoned time 10 years water supply restored.

Grants

1. Grants to each village
2. Grants to M.C., Beri
3. Grants of Chaupals
4. 100 yards plots to Harizans
5. Shortage of pipes in different village
6. Railway station Demand of Dujana & (Public Health) Bhambewa (Full-fill the criteria)
7. Road alongwith Railway line (West-side) from Dujana to Bhambewa
8. Bhambewa : Filling of low lying area Primary School
9. Sheria: Filling of low lying area of High School.

श्री महीपाल ढांडा: उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी के शासन काल में खादी ग्राम बोर्ड की बहुत हालत खस्ता हो गयी थी और आज वह किस स्टेज पर है। कादियान साहब ये भी बताएं कि इसमें घोटाला किसने किया है तथा इस पर किन–2 लोगों का कब्जा है ? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया: महीपाल जी, आप बैठिये, आपको बोलने के लिए बाद में समय दिया जाएगा।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): उपाध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का पहले मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल जब बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त मैं किसी अपने निजी काम की वजह से नहीं आ पाया था। लेकिन कल शाम को बजट पर वित्त मंत्री जी का जो भाषण था उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे कहीं–कहीं लग रहा था कि सरकार प्रदेश के बारे में गम्भीर है लेकिन जो पिछले वर्ष के आंकड़े थे और इस वर्ष के जो आंकड़े बजट में दर्शाये गये हैं उनसे साफ झलकता है कि सरकार प्रदेश में विकास की बजाय कहीं न कहीं लोगों को, आधा अधूरा वायदा रखकर कहीं न कहीं गोल–माल बात कर रही है लोगों को भ्रमित कर रही है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और जब प्रदेश की

सरकार का बजट आता है तो चार–पांच चीजों को सबसे अहम माना जाता है कि किन –किन चीजों को प्रदेश की सरकार की तरफ से बढावा दिया जा रहा है और बढावा देते समय जो टोटल बजट है उसमें से कितना प्रतिशत बजट किन–किन विभागों पर खर्च किया जाएगा। हमारे प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है। मुझ से पहले जो साथी बोल रहे थे उनमें से खासकर सत्ता पक्ष की तरफ यह बात कही गयी थी कि अबकी बार 3206 करोड़ रूपये का बजट कृषि के लिए रखा गया है। अगर पिछले वर्ष के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पिछले वर्ष 2016–17 में जो कृषि के लिए बजट रखा गया था वह 13.71 प्रतिशत था और अबकी बार उस बजट को बढाने की बजाय उसको घटा दिया है और 2017–18 के लिए है 12.49 प्रतिशत बजट रखा गया है। सरकार द्वारा कहा गया था कि हम किसान की मद के लिए नये–नये इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, कहीं बागवानी को बढावा देने की बात कहीं गयी, कहीं फूलों की फसल को बढावा देने के लिए बात कही गयी, कहीं फसलों को बढावा देने की बात कही गयी। इन सब चीजों को बढाने के लिए जो हमारे पास सबसे अहम सोर्स है, आज उसकी हालत भी सबसे ज्यादा खराब है। हमारा कृषि विज्ञान केन्द्र हिसार में है और कृषि विज्ञान केन्द्र में आज की तारीख में जितनी भी पोस्ट्स हैं वह चाहे टैक्निकल हैं या नान टैक्निकल पोस्ट्स हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो टैक्निकल पोस्ट्स हैं वह टोटल सैंक्शंड पोस्ट्स 1042 है और आज की तारीख में 583 पोस्ट्स वैकेंट हैं। मतलब लगभग 56 प्रतिशत पोस्टस आज भी वैकेन्ट हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे माननीय सदस्य वैकेंट पोस्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वह किस विश्वविद्यालय में वैकेंट हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह पोस्ट्स कृषि विश्वविद्यालय हिसार में खाली हैं जो मैं सदन में पहले ही बता चुका हूं। मुझे लगता है कि कादियान जी फर्जी डिग्री लेकर यहां आए हुए हैं। मुझे लगता है कि कादियान जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है अगर इनको इसके बारे में जानकारी होती तो ये इस प्रकार का सवाल न पूछते।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, अंधे को तो अंधेरा ही दिखता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, कादियान जी भी मेरे साथ कृषि विश्वविद्यालय हिसार में पढ़ते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह चौटाला जी का नकली सर्टिफिकेट देखना हो तो मेरे पास है।

श्री अभय सिंह चौटाला : कोई बात नहीं आप भी यहां पर प्रस्तुत कर दें। आपको तो किसी ने नहीं रोका है।

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आप करण जी को बैठाइए और मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये सदन का समय न बर्बाद करें। उपाध्यक्ष महोदया, आप इन्हें अलग से समय दे दें। (शोर एव व्यवधान) ये जो बातें कह रहे हैं ये सारी बातों को रिकॉर्ड से बाहर करवाइए।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, एक आई.सी.आर फैलोशिप की परीक्षा में मैंने पूरे हिन्दुस्तान में टॉप किया था, यह मैं रिकॉड की बात कर रहा हूं। (शोर एव व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, बात हो गई, आप बैठ जाइए। (शोर एव व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनके एक रिकॉर्ड की बात बता देता हूं मेरे पास इनके कई रिकॉर्ड हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी कादियान जी बात कर रहे थे कि मैंन यहां टॉप किया, वहां टॉप किया। ये जब स्पीकर पद से हटे थे तो इनके कोठी के अंदर जो एयरकंडीश्नर लगे हुए थे, ये उसे भी निकाल कर ले गए थे। मैं सच बोल रहा हूं इस बात की आप इनक्वायरी कराकर देखें। ये जब एम.एस.सी या पी.एच.डी कर रहे थे तो इनके खिलाफ पंखों की चोरी के आरोप भी लगे और इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। (शोर एव व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, शिक्षा मंत्री बैठे हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चौटाला जी के सर्टिफिकेट की जांच करवाइए और ये पता करवाइए कि अभय सिंह चौटाला जी का सर्टिफिकेट सही है या गलत, अगर मैं गलत हुआ तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करण जी रोज इस्तीफे की बात करते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से अभय जी को बताना चाहता हूं कि जब झज्जर में नेहरू कॉलेज बन रहा था तो उस समय लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए गए और मैंने अपने परदादी के नाम से 10 एकड़ जमीन नेहरू कॉलेज, झज्जर को दान कर रखी है। हमने एक कॉलेज अपने गांव में बनवाया और बनने के बाद उसे गवर्नमेंट को सौंप दिया। 60 एकड़ जमीन है वहां, पंचायत की भी है और कुछ दूसरे लोगों की भी है हमने जमीन तक दान कर दी, हम इन लोगों की तरह घड़ी चुराकर नहीं लाये थे। इनके दादा ने इनके पिताजी यहां तक कहा था कि ये मेरा लड़का ही नहीं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप मुझे एक कहोगे तो मै आपको दो सुनाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आप बैठो ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ये जो आरोप मैंने लगाये थे, जो बात मैंने कही थी, वह आरोप नहीं थे (शोर एव व्यवधान) वह कांग्रेस के राज के समय में, ये हमारी पार्टी में थे, कांग्रेस का ही राज था और कांग्रेस वालों ने ही मुकदमे दर्ज किए थे, हमने नहीं किए थे। जिस कांग्रेस की सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, मैंने उनका जिक्र भी किया था। ये कांग्रेस के राज का मामला है।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय सदस्य जी का यूनिवर्सिटी में एल. एल.बी के क्लासेज में नकली एडमिशन हुआ पड़ा है। शिक्षा मंत्री जी जांच करा लें, अगर ये बात झूठी निकली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह जी स्वयं बता दें कि इनके एल.एल.बी. के एडमिशन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है । मैं वही बात मान लूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को बैठायें । यदि ये नहीं बैठते हैं तो इन्हें सदन से बाहर निकाला जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी बात भी सुनी जाये । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज आप सभी बैठें । आप विपक्ष के नेता को अपनी बात पूरी करने दें । (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, आप भी प्लीज बैठें । (शोर एवं व्यवधान) मेरी परमिशन के बगैर कोई भी माननीय सदस्य न बोले । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है इनको स्प्रिंग लगे हुए हैं जिसके कारण ये बार–बार खड़े हो जाते हैं । (शोर एवं व्यवधान) अगर इनके पैर में कोई चोट लगी हुई है तो ये डाक्टर से इलाज करवायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, अभय सिंह जी स्वयं बता दें कि इनके एल.एल.बी. के एडमिशन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है । मैं वही बात मान लूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इनकी दस साल तक सरकार रही । उस समय इनको चैक करना चाहिए था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी भी बात सुनी जाये । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज आप सभी बैठें । कुलदीप जी आप तो स्पीकर रहे हैं । प्लीज आप परमिशन के बगैर न बोलें । विपक्ष के नेता को अपनी बात कन्टीन्यू करने दें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहा था कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्स्टीच्यूट है । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही फसल, सब्जियों, बागवानी आदि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रिसर्च करती है । यदि उसी यूनिवर्सिटी की हालत ठीक नहीं होगी तो जो बातें कृषि के बारे में बजट में दर्शाई गई हैं या जो बातें कृषि मंत्री जी कहते हैं, वे बातें केवल और केवल स्पीच तक सीमित रह जायेंगी । उससे आगे नहीं बढ़ सकती । आज उस यूनिवर्सिटी में हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट्स की टोटल 35 पोस्टें सैंक्शंड हैं जिनमें से 30 पोस्टें खाली पड़ी हैं । यदि हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट ही नहीं होंगे तो संबंधित डिपार्टमैंट के निर्णय कौन लेगा ? इसी तरह से इस यूनिवर्सिटी में डीन की पोस्ट भी खाली है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है । इस तरीके से कृषि बजट भी पिछले साल के मुकाबले कम रखा गया है। पिछले साल कृषि बजट 1371 करोड़ रुपये रखा गया था जो कि इस साल कम कर दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदया, किस तरह से किसान को कमजोर किया जाये और किस प्रकार से किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ा जाये, इस बारे में सरकार ने योजनाएं बनाई हैं । जबकि सरकार रोज कहती है कि कृषि और किसान को बढ़ावा देना चाहते हैं । केन्द्र सरकार ने भी कहा है कि वर्ष 2020 तक किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे और हरियाणा सरकार भी कह रही है कि किसान की आमदनी दोगुना करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है । लेकिन

आज प्रदेश में हालत इस तरह के हैं कि जो किसान धान पैदा करता है पिछले दो साल से नमी के नाम पर 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल काटे जा रहे हैं । हमने प्रदेश की मण्डियों में दौरा किया था । उस दौरान हम किसानों और आढ़तियों से मिले थे । सरकार द्वारा तीन–चार एजैंसियां धान खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन किसी भी मण्डी में किसी भी सरकारी एजैंसी द्वारा धान नहीं खरीदी जा रही। धान को खरीदने का काम मिलर्ज़ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि धान में अगर एक प्रतिशत नमी होगी तो उसके लिए पांच रूपये की कटौती की जायेगी लेकिन मिलर्ज द्वारा इस नमी के प्रतिशत को 5 प्रतिशत तक ले जाकर किसान से 75/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की गई। इतना ही नहीं किसाने से 150–200 और 250 रूपये तक की कटौती नमी के नाम पर की गई। जो जे–फार्म किसान को दिया गया वह तो 1560/– रूपये का ही दिया गया लेकिन उसको जो पेमैंट की गई वह 200 से 250 रूपये कम की गई। इसी प्रकार से हमारे यहां बाजरे का समर्थन मूल्य भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब की बार बाजरे का मूल्य 1330/– रूपये था। हरियाणा प्रदेश में 10 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी मात्रा में बाजरे की खेती होती है। इन 10 के 10 जिलों में बाजरे की खरीद सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी लेकिन सरकार द्वारा बाजरे की खरीद करने के बजाय यह कैप लगा दी गई कि अगर किसान का जो बाजरा बाजार में आयेगा तो सरकार उसमें से सिर्फ 4 क्विंटल ही खरीदेगी। इस बार प्रदेश में बाजरे की बम्पर फसल हुई है और किसानों को 40–40 मन प्रति एकड़ के हिसाब से बाजरे की फसल प्राप्त हुई है। अपने बाजरे को बेचने के लिए पहले पटवारी से और फिर गांव के सरपंच से इस प्रकार से किसान को 10 जगहों से लिखवाकर लाना पड़ा कि यह मेरा बाजरा है। इतना ही नहीं इसके बाद उसको फिर किसी तीसरे व्यक्ति को अपने साथ गवाही के लिए लेकर जाना पड़ा। उसने उसकी गवाही दी इसके बाद किसान का 4 क्विंटल बाजरा सरकार ने खरीदा। उसका बाकी का बाजरा 1100/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इतना ही नहीं उसको 230/– रुपये और कम मिले। अब मैं सब्जी लगाने वाले किसानों की बदतर हालत के बारे में बताना चाहूंगा। जो शहरों के साथ लगती हुई जमीने हैं जहां पर लोग आलू, प्याज, टमाटर और गोभी का उत्पादन करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में सफेदे और पॉपलर से सम्बंधित उद्योग लगे हुए हैं। जिस कारण हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो पपलर और

सफेदे की खेती करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार किसान के हितों के प्रति चिन्तित होती तो 100 का 100 प्रतिशत जिस प्रकार से आसाम की सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है वैसे ही हरियाणा प्रदेश के किसानों के आलू का भी समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती तो जिस प्रकार से आलू किसानों की बर्बादी हुई वह न होती। आज तो आलू उत्पादक किसान की इतनी बुरी हालत है कि उसके आलू की उसे मार्किट में 1/– रूपये से 2/– रूपये प्रति किलोग्राम की कीमत मिल रही है वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग द्वारा कोल्ड स्टोरेज में भी उसके आलू को रखने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी किसान ने यह कहा कि वह अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहता है तो कोल्ड स्टोर खाली होने के बावजूद भी उसको यही कहा गया कि कोल्ड स्टोर में जगह नहीं है क्योंकि ये कोल्ड स्टोर पहले से ही किराये पर चढ़े हुए हैं। इसके पीछे आलू व्यापारियों का यही षड्यन्त्र काम कर रहा था कि किसान का आलू कोल्ड स्टोर में न रखा जाये और उसे मज़बूरीवश अपना आलू 1/– रूपये से 2/– रूपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचना पड़े। आलू किसानों को लुटने से बचाने के लिए सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत केवल और केवल इसके लिए ही योजनायें बनाई गई कि किसानों को कैसे कमज़ोर बनाया जाये। यह उसी योजना का ही हिस्सा है कि वर्ष 2016–17 में जो बजट कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया था उसको वर्ष 2016–17 में और भी कम कर दिया। वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि किसान को कहीं न कहीं लाभ मिले और किसान के सिर पर जो कर्ज है वह कम पड़े। सरकार यह भी नहीं चाहती कि किसान अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पर पढ़ा सके। सरकार द्वारा किसान को पूरी तरह से कमजोर करने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है। मैं सिर्फ एक कृषि विकास केन्द्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो कृषि विकास केन्द्र हैं उसमें जो वैज्ञानिक हैं उनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसके साथ ही साथ जहां तक कृषि को बढ़ावा देने की बात है इसके लिए सरकार द्वारा ए.डी.ओ. लगाये जाते थे। वर्तमान में हमारे छात्र यूनिवर्सिटी में ऐग्रीकल्चर से सम्बंधित कोर्सिज में इसलिए एडमिशन नहीं लेते क्योंकि उनके लिए आने वाले समय में कहीं कोई जॉब का मौका उपलब्ध नहीं है। पहले जो बच्चे वहां पढ़ते थे उनकी सरकार द्वारा ए. डी.ओ. के पद पर नियुक्ति की जाती थी। उसकी जिम्मेदारी यह होती थी कि वह गांव–गांव में जाकर किसानों को प्रोत्साहित करें और किसानों को यह जानकारी दे

13:00 बजे

कि अच्छी फसल के लिए वह कौन सा बीज प्रयोग करे, कौन सी खाद प्रयोग करे और कौन सी स्प्रे करे ताकि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन हैरानी की बात है आज ए.डी.ओ. की ज्यादातर पोस्टें रिक्त पड़ी है। अगर कोई ए.डी.ओ. होगा भी तो वह भी 20–30 गांवों में कोई एक अधिकारी नियुक्त होगा जबकि हर गांव में एक ए.डी.ओ. होना चाहिए था ताकि जो कृषि करने वाले लोग थे उनको कृषि से सम्बंधित आवश्यक जानकारी मिल पाती। महोदया, कृषि की यह हालत मैंने आपके सामने रखी है। उसके साथ–साथ जो फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसके बहुत गुणगान हुये कि इस फसल बीमा योजना से किसान को बहुत फायदा होगा उसी फसल बीमा योजना के तहत जो पैसा किसान से लिया गया वह पैसा भी किसान को बिना बताये लिया गया । उसके लिए किसी किसान को यह नहीं बताया गया कि हम आपकी उक्त फसल का बीमा कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, बड़ी हैरानी की बात है कि जहां इंट–भट्ठे लगे हुये थे उस जमीन में भी यह कह कर बैंक से पैसे काट लिये कि आपने यहां पर फसल बोई हुई थी । इस बात की किसी ने जानकारी हासिल नहीं की कि उसके खेत में कौन सी फसल खड़ी है । अगर कहीं पर गन्ना लगाया हुआ था उसका भी पैसा काट लिया गया, कहीं ईंट भट्ठा था उसका भी काट लिया गया और कहीं पर जमीन खाली पड़ी हुई थी उसका भी पैसा इस फसल बीमा योजना के नाम पर काट लिया गया । उपाध्यक्ष महोदया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जहां पर ओलावृष्टि से फसल खराब हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए था क्योंकि उन फसलों की बीमा राशि ऐजेन्सीज ने काट ली थी । लेकिन किसी भी ऐजेन्सी ने जा कर किसान की फसल की खराब होने की गिरदावरी नहीं की और न ही किसी ने यह कहा कि आपने फसल बीमा योजना के तहत बीमे के रूप में जो पैसा जमा करवाया था उसके बदले में फसल बीमा पॉलिसी के तहत आपको पैसा मिलेगा । इस प्रकार से इस फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया गया है ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे हैं वह बात ठीक नहीं है और ये भ्रमित कर रहे हैं । जिस समय किसान क्रॉप लोन लेता है तो बैंक वाले उससे गिरदावरी मांगते हैं कि आपने कौन सी फसल बोई हुई है । अगर उस समय उसने गन्ने की गिरदावरी दे दी और दो साल बाद उसमें जीरी लगा ली और गेहूं उगा लिया । फसल बीमा

योजना के तहत गन्ने का तो बीमा नहीं होता है हमारे यहां जीरी और गेहूं का बीमा होता है । जब उसका पैसा कटा तो उसने शिकायत की कि मैंने तो गन्ना बोया हुआ है और गन्ने का बीमा नहीं होता है । तब हमारी सरकार ने कुछ समय निश्चित किया था और बैंक वालों को यह कहा था कि इनसे इन्फोर्मेशन ले लो, चाहे किसान दे दे या बैंक ले ले और उसी हिसाब से बैंक पैसे वापिस करेगा । जिसने यह सूचना दे दी या बैंक ने ले ली उनको उनका पैसा वापिस हो गया है और इस फसल बीमा योजना से किसानों को नुकसान नहीं फायदा हुआ है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, श्री श्याम सिंह राणा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी पता नहीं उनको इस बात की जानकारी क्यों नहीं है कि हर 6 महीने में फसलों की गिरदावरी होती है । जब भी कोई नई फसल बोई जाती है तो पटवारी खेत में जा कर गिरदावरी करके लाता है कि इस बार किसान ने कौन सी फसल बोई है । इसी प्रकार से कृषि के बारे में भी आज किसान की अनदेखी की जा रही है, कृषि के नाम पर पहले सरकार जहां समर्थन मूल्य की बात करती थी, सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करती थी आज कुछ नहीं कर रही है । कृषि मंत्री जी ने चुनाव के दौरान यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे । मैंने इनका एक ऐसा भाषण भी सुना था जिसमें इन्होंने यह भी कहा था कि किसान के गेहूं का जो आज समर्थन मूल 1400 रुपये है उसको बढ़ा कर हम 2100 रुपये कर देंगे । यह 700 रुपये प्रति क्विंटल मोदी जी के खजाने से आ कर किसानों को मिलेगा । मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग भी है अगर कृषि मंत्री जी कहेंगे तो मैं इनको दे दूंगा और ये सुन लेंगे कि इन्होंने ये बातें कही या नहीं कही थी। ये सभी बातें केवल और केवल कहने के लिए थी उन पर अमल नहीं किया गया । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये।)** अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं ग्रामीण विकास पर भी अपने विचार रखना चाहता हूं । सरकार की तरफ से 3000 से 10000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांवों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय से, हरियाणा के महान नेता रहबरे आज़म स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर "दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना" के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है । इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रख–रखाव के लिए हरियाणा के महान नेता पूर्व उप–मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना "मंगल नगर विकास

योजना" शुरू की गई है । अगर सरकार ग्रामीण विकास करना चाहती है तो जो पिछला बजट था उस बजट के अन्दर आपने ग्रामीण विकास के लिये जो पैसा रखा था अगर उसको देखें और अबकी बार बजट में इसके लिये आपने जो पैसा निर्धारित किया है उसको देखें तो आपने उस बजट में भी कटौती कर दी है । वर्ष 2016–17 में जो बजट था वह 4.85 प्रतिशत था और अबकी बार आपने उसको 2. 94 प्रतिशत कर दिया । अबकी बार आपने बजट को फिर कम कर दिया है। इसका मतलब सीधा–सीधा है कि आप जो केवल ग्रामीण उत्थान की बात करते हैं । ग्रामीण विकास की बात करतें हैं लेकिन जब विकास में खर्च करने की बात आती है तो कहीं न कहीं ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने के प्रयास किये जाते हैं जिससे कोई भी आपके उस भाषण को सुनने वाला सौ फीसदी यह सोचता होगा कि सरकार ने तो अब की बार बजट का सारा पैसा ग्रामीण विकास की तरफ, कृषि की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, सड़कों की तरफ खर्च करने का काम किया है । लेकिन हकीकत यह है कि आपने इसमें भी पैसा कम कर दिया है । आज की हालत ऐसी है कि जिला परिषद के लोग, ब्लॉक समिति के लोग, गांव के सरपंच इस बात को लेकर के दु:खी हैं कि उनकी अपनी पंचायत का जो पैसा था उस पैसे के लिये भी कहीं न कहीं एक्सियन पर दबाव डालकर के, बी.डी.ओ. पर दबाव डलवा कर के, पंचायत के सरपंचों और पंचों को बुलाकर के रैजोल्यूशन पास करवा लिये गये कि सारा पैसा एक्सीयन के माध्यम से खर्च किया जाएगा । आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद के पास कोई पैसा नहीं है । जिस तरह से कहा गया था कि हम इनको पैसा देकर के कहेंगे कि आप अपने अलग बजट का प्रावधान करें । आज उनके पास खर्च करने के लिये एक पाई भी नहीं है । उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वह शराब के ठेकों से आता है । केवल वही पैसा उनके पास आता था और वही पैसा उनके पास है । जिससे वह अपने–अपने वार्ड में जाकर छोटा–मोटा काम करा सकते हैं । इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसको लेकर के आज यह कहा गया है कि हम ट्रांसपोर्ट विभाग में नई बसें खरीदने जा रहे हैं । हम उसमें सुधार करने जा रहे हैं । सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट विभाग के लिये भी कहा गया है कि लोगों को असुविधा न हो इसलिए हम महिलाओं और बेटियों के लिये अलग से बसें चलाने का काम करेंगे । इसके अलावा इसको लेकर के बहुत से प्रश्न भी यहां पर हुए हैं लेकिन जो बजट में दर्शाया है उससे नहीं लगता कि सरकार कहीं भी ट्रांसपोर्ट विभाग को आगे ले

जाने का काम करेगी । जिस तरह से बजट में दिखाया गया था कि पिछली बार वर्ष 2016–17 में आपने 6.28 प्रतिशत बजट दिया था और अबकी बार आपने अपने बजट में 6.23 प्रतिशत दर्शाया है । मतलब पिछले बजट के मुकाबले इसमें भी अबकी बार कम बजट रखा गया है। इसी तरीके से सहकारिता विभाग है जिससे किसान पूरी तरह से जुड़ा हुआ है । जिसमें बजट के बढ़ाने की बात हर वक्त की जाती है ताकि किसी न किसी तरीके से सहकारिता के माध्यम से किसान को लाभ मिल सके । उसके लिये देश के अन्दर रोजाना नई–नई योजनाएं बनती हैं । सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार भी कहीं न कहीं इसके बारे में चिन्तित नजर आती है कि इसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो उसका गरीब आदमी को सीधा–सीधा लाभ मिलेगा । चाहे कोई भैंस पालने वाला है, चाहे कोई गाय पालने वाला है, चाहे गांव में और कोई छोटा–मोटा कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा । लेकिन उसमें भी आपने जो पिछली बार 880 करोड़ रूपये का बजट रखा था उसको भी आपने घटाकर के 624 करोड़ रूपये कर दिया है । यह भी पिछले बजट की मुकाबले कम रखा गया है । एक तरफ तो बात की गई थी कि एक लाख करोड़ रूपये का बजट होगा । बजट में तो यह दिखाया गया है कि हमारा बहुत बड़ा बजट है । लेकिन जहां पर तरक्की के रास्ते हैं और जहां से कहीं न कहीं सरकार के सामने यह बात आती है कि सरकार कहीं सीरियस हो कर के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है । वहां आपने सभी जगह पर कटौती करने का काम किया है । वह पैसा कहां खर्च होगा । इसके बारे में कहीं कोई बात सामने नहीं रखी गई है । जहां तक बिजली की बात है । हमारे यहां तो बिजली का उत्पादन बन्द ही कर दिया गया है । यहां जितनी भी बिजली है वह प्राईवेट एजेंसियों से खरीदी जाती है और प्राईवेट एजेंसियों से बिजली खरीद कर के आज भी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है तो वह हरियाणा प्रदेश में दी जा रही है । प्रदेश के लोगों को बिजली सस्ती मिले उस पर कदम उठाने की बजाए जहां बिजली को बढ़ावा देने के लिये कि बिजली 24 घण्टे मिले जिसमें सरकार का वायदा था कि हम प्रदेश में 24 घण्टे बिजली देंगे । लेकिन आज हालत ऐसी है कि 24 घण्टे की बजाए आज तो कभी दो घण्टे बिजली आती और फिर चली जाती है । फिर कोई दो घण्टे आती है । इस बात का कोई पक्का समय नहीं है कि किस समय से किस समय तक

लगातार आपको 10 या 12 घण्टे बिजली मिलेगी । आज प्रदेश में बिजली की बहुत बुरी हालत है। उसके सुधारीकरण के लिए जहां ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए था उसकी जगह पॉवर सैक्टर के लिए कम पैसे का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में बिजली के क्षेत्र में 16283 करोड़ 98 लाख रूपये की राशि खर्च करने की बात कही गई थी लेकिन अबकी बार इस राशि को 12685 करोड़ 81 लाख रूपये करके, कम करने का काम किया गया है। सीधा सा मतलब है कि यदि राउंड फिगर में देखें तो 4000 करोड़ रूपये के लगभग बिजली के क्षेत्र में कम राशि का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से इस वित्त वर्ष में लगभग साढ़े तीन–पोने चार हजार करोड़ रूपये पावर डिपार्टमैंट में कम बजट जायेगा जबकि यहां पर बजट की ज्यादा जरूरत थी लेकिन बावजूद इसके पावर डिपार्टमैंट का बजट कम कर दिया गया है। अगर प्रदेश में बिजली का संकट हो गया तो फिर मानकर चलो कि सरकार ने जो प्रदेश में निवेश के लिए हैप्पनिंग हरियाणा तथा प्रवासी हरियाणा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया था, उनका औचित्य समाप्त होकर रह जायेगा और इस प्रकार प्रदेश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा और प्रदेश में कोई इंवेस्ट नहीं करेगा। अगर बिजली के भाव दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा होंगे तो मानकर चलो कोई नई इंडस्ट्री प्रदेश में निवेश के लिए नहीं आयेगी और तमाम तरह की विकास संबंधी बातें केवल कागजों तक ही सीमित रह जायेंगी। सरकार द्वारा कहा जाता है कि हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में 5.84 करोड़ का इंवेस्टमैंट आने वाला है, इस तरह की चीजों से इन कार्यक्रमों का औचित्य समाप्त हो जायेगा। इस तरह से आज प्रदेश का कोई ऐसा डिपार्टमैंट नहीं बचा है जिसकी हालत खराब न हुई हो, जबकि प्रदेश सरकार को इन्हें ज्यादा बजट का प्रावधान करते हुए बढ़ावा देना चाहिए था और इनकी प्रोग्रैस करनी चाहिए थी लेकिन 100 फीसदी इनके बजट में कटौती की गई है और बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए की गई बजट कटौती का खामियाजा प्रदेश के लोगों को आने वाले समय में कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। अब मैं कानून एवं व्यवस्था के बारे बात रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पिछले अढ़ाई साल के कार्यकाल में कहीं न कहीं लोग यह उम्मीद करते थे कि कानून और व्यवस्था में सुधार आयेगा? मैं इसके लिए आपके सामने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं रखूंगा और महज एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिससे स्वयं अंदाजा हो जायेगा कि आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की क्या हालत हैं? आज प्रदेश में बलात्कार, हत्या, चौरी और डकैती की घटनायें नित रोज बढ़ती ही

जा रही हैं और कईं जगह सरकार की इंटरफेरेंस की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको एक गुहला चीका का वाक्या बताता हूँ। यहां पर एक एफ.आई.आर. लॉज होती है जिसमें धारा 323, 376 और 498–ए लगाई गई और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो पांच दोषी थे उनके नाम हैं श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद, श्री संदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद, श्रीमती ऋषि देवी पत्नी श्री प्रेम चंद, श्री प्रेम चंद पुत्र मांगा राम और दो दोषी और थे। इनके खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज हो गई और जांच का जिम्मा एक डी.एस.पी जिसका नाम श्री सुल्तान सिंह था को दी गई। उसने इन छह लोगों को दोषी ठहराने संबंधी अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी लेकिन उस जांच से आपकी सरकार संतुष्ट नहीं हुई और दोबारा से इस केस की जांच का जिम्मा श्री तरूण सैनी नाम के एक डी.एस. पी. जोकि कैथल हैडक्वॉर्टर में पोस्टिड थे, को सौंप दिया गया और उसने अपनी जांच में इन छह लोगों को फिर से मुजरिम मान लिया। दो बार जांच होने के बाद भी जो मुजरिम थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार द्वारा दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया इसी प्रयास के मद्देनज़र इस केस की जांच का जिम्मा एक अन्य डी.एस.पी. श्री सतीश गौतम जो कि कैथल में ही पोस्टिड था, को सौंप दिया गया और इसकी जांच में भी इन छह लोगों को फिर से दोषी मान लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस केस में 3 अधिकारियों से जांच करवाई गई और तीनों अधिकारियों ने 100 का 100 फीसदी अपनी जांच में इन छह लोगों को दोषी माना ओर दोष सिद्ध होने के पश्चात भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार का यह प्रयास रहा कि कैसे और कैसे दोषी लोगों को बचाया जाये। उसके बाद चौथे डी.एस.पी. को जांच दी गई । जिस डी.एस.पी. को यह जांच दी गई उसका नाम जागेन्द्र सिंह था । जब उसको जांच दे दी गई तो उसने जो शिकायतकर्ता था उसको न तो नोटिस दिया और न ही शिकायतकर्ता को बुलाकर पूछा कि क्या मामला है । सीधे–सीधे जो दोषी थे उनमें से 2–3 लोगों को बुलाकर रिपोर्ट कर दी कि ये लोग दोषी हैं । इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है ? जहां सरकार के लगाए हुए अपने डी.एस.पी. ने सरकार के द्वारा बारी–बारी से इन्कवायरी करवाने पर जो लोग दोषी थे उनको दोषी माना तो फिर उनको बचाने के प्रयास क्यों किये गए ? आज वहां पर इस बात को लेकर आम चर्चा है कि केवल और केवल वहां का जो लोकल विधायक है वह दोषियों की मदद कर रहा है और उनको बचाने के लिए बारी–बारी से जांच

बदलवाने का प्रयास कर रहा है । आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह हालत है। अगर मैं सारी बातों की चर्चा करूंगा तो इसमें बहुत लम्बा समय लग जाएगा । (विघ्न) फिर आप मुझे कन्कलूड करने की बात कहोगे । इसी तरीके से स्पीकर महोदय, जो अहम चीज बजट में मानी जाती है वह राजकोषीय घाटा है । यह सबसे जरूरी चीज है । विकास का सरकार का जो पैमाना है वह दो चीजों पर निर्भर करता है उत्पादन पर और पूंजीगत खर्च पर । पूंजीगत खर्चा बढ़ने से आधारभूत ढांचा मजबूत होता है । अगर पूंजीगत खर्च घट रहा हो तो विकास की कल्पना भी कम हो सकती है । पिछले वर्ष 2015–16 में घरेलू उत्पादन 1.39 प्रतिशत था बजट में दर्शाया गया है कि अब वह 1.25 प्रतिशत हो गया है । अब की बार सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं । सरकार के अनुमान से यह 1.80 प्रतिशत तक चला जाएगा लेकिन जिस तरह से पिछले 3–4 सालों से जो बजट दर्शाया गया है उससे नहीं लगता कि इस साल भी उस पर बढ़ोतरी हो जाएगी । इस साल भी वह फिर उसी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाएगा । इसके साथ–साथ जहां तक नहरी पानी का सवाल है एस.वाई.एल. कैनाल के लिए भी सौ करोड़ रूपये दिखाये गए हैं कि सौ करोड़ रूपये एस.वाई. एल नहर के निर्माण के लिए इस साल बजट में रखा है । अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया तो किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार हमें यह भी कह सकती है कि इसके लिए आप किसी एजेंसी को अथॉराइज करो कि उस नहर के निर्माण का काम शुरू करें लेकिन उस पर जो पैसा खर्च होगा वह प्रदेश सरकार की तरफ से खर्च होना है । उसमें केवल सौ करोड़ रूपया दिखाया गया है कि इसमें सौ करोड़ रूपये खर्च कर पाएंगे । अध्यक्ष जी, अगर बजट में एस.वाई.एल. नहर के लिए सौ करोड़ रूपये रखा गया है तो एस.वाई.एल. नहर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया तो आप मानकर चलिए कि जो इतने रूपये रखने की बात कही है तो फिर एस.वाई.एल. नहर बनने में तो दस वर्ष लग जाएंगे । (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष की बात को बीच में टोकना नहीं चाहता था लेकिन शायद बजट पढ़ने में या समझने में थोड़ा–सा फर्क रह गया है । हमने एस.वाई. एल. नहर के लिए वार्षिक सौ करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान नहीं किया है । अगर एस.वाईएल. नहर इस साल बनेगी तो आज के दिन सरकार के पास कोई

एस्टीमेट नहीं है कि उसको बनाने और रिपेयर करने में कितना खर्च आएगा ? हमने सौ करोड़ रूपये का प्रावधान कर दिया है लेकिन यह कमिटमैंट बजट की स्पीच में है कि हमने एक ब्लाइंड एस्टीमेट को भी अप्रूव किया है । हमने इसे इस महान सदन के सामने रखा है । सबकी सहमति से और सबको साथ लेकर हजार करोड़ रूपये की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे और हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे और इसी वर्ष करेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही है अगर वही बात अपने बजट भाषण के दौरान कह देते तो अच्छा था।

कैप्टन अभिमन्युः अभय जी, मैंने बजट भाषण के दौरान कही थी लेकिन बजट भाषण के दौरान आप सदन में मौजूद नहीं थे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जी यह कह देते कि एस.वाई.एल. कैनाल के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि क्या 1000–2000 करोड़ की राशि भी लगे तो सरकार लगाने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह तो हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है। अध्यक्ष महोदय, इस नहर के निर्माण के लिए कितना भी पैसा खर्च हो उसमें सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि सौ के सौ फीसदी लोग इस नहर पर टक–टकी लगाए बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो हरियाणा के हक में आया है वह संदेश केन्द्र सरकार के पास जायेगा और यह नहर बनकर रहेगी। यदि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर होती कि हरियाणा के लोगों को उसके हिस्से का पानी मिले, यह बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाननी चाही थी और अब आपके माध्यम से सदन से भी जानना चाहता हूँ कि राजपुरा के अन्दर पटियाला नदी के नीचे जो साईफन बना हुआ है जिसका दायरा 10 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा है तथा जहां से 4 हजार क्यूसिक पानी भाखड़ा से हरियाणा प्रदेश को मिलता है उसके अन्दर चार पाईप लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन चार पाईपों में से एक पाईप बंद पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, जो पाईप बंद पड़ी है, सरकार अब तक इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि वह पाईप क्यों बंद पड़ी है? आज कल तो ऐसे यंत्र आ गए हैं जिनसे 10 हजार फुट गहरे पानी के नीचे यानी समुद्र के नीचे भी चीजों का पता लगाया जा सकता है तो क्या इस खराब पाईप के कारणा का पता नहीं लगाया जा

सकता? यदि सरकार इस चीज में गंभीर होती कि किसानों को पूरा का पूरा पानी मिले जिससे उनकी फसल अच्छी हो और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तो वह इस चीज का सौ फीसदी जरूर पता लगाती। क्योंकि एक पाइप के बंद होने से हमें 1000 क्यूसिक पानी कम मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक पाइप की वजह से इतना बड़ा पानी का संकट हरियाणा में आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे यहाँ पानी देने के लिए एक रोटेशन हुआ करता था कि 15 दिन पानी देने के बाद एक सप्ताह पानी की सप्लाई बंद रहती थी। लेकिन आज के दिन हमें 32 दिन में केवल एक सप्ताह पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः अभय जी, सिंचाई के बारे में तो आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र कर दिया था।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक बार दोबारा से याद करवाना चाहता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं आया था। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए एक बात और लाना चाहता हूँ कि यदि सरकार सिंचाई के मामले में भी गंभीर होती कि किसान को उसके हक का पूरा पानी मिले तो आज जहाँ दूसरे विभागों में कर्मचारियों की कमी है चाहे वह शिक्षा का विभाग हो चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो सभी विभागों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। किसी भी विभाग में जा कर देखोगे तो कर्मचारियों की कमी का रेशो 48 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग में 51 प्रतिशत जे.ईज., एस.डी.ओज., एक्सीयन के पद खाली हैं। प्रथम श्रेणी के ऑफीसर के 214 पदों में से 73 पद खाली हैं जो 34 प्रतिशत के करीब बनता है। द्वितीय श्रेणी के ऑफिसर के 492 पदो में से 120 पद खाली हैं जो 24 प्रतिशत के करीब बनता है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के 7721 के पदों में 4756 पद खाली हैं जो 62 प्रतिशत के करीब बनता है। चतुर्थ श्रेणी के 9288 पदों में 4098 पद खाली हैं जो 44 प्रतिशत के करीब बनता है। इस तरह सिंचाई विभाग में एवरेज 51 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, अगर सिंचाई विभाग में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और कृषि विज्ञान के अंदर कर्मचारियों की संख्या कम होगी तो यह मानकर चलो कि किसानों का भला नहीं होगा। अगर कृषि विज्ञान केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या कम होगी तो यह मानकर चलें कि किसान पानी के बिना खेती नहीं कर सकता। क्योंकि

अगर पानी नहीं होगा तो उसकी खेती अच्छी नहीं होगी। जब अच्छा बीज मिलेगा अच्छी जानकारी मिलेगा कि कौन सी फसल कब लगानी हैं जिससे किसान का उत्पादन बढ सके। इन सब चीजों के ऊपर प्रदेश की जनता व किसानों को गुमराह किया गया है। इस बजट में यह दिखाया गया है कि हम किसानों के प्रति सीरियस होकर आगे बढ रहे हैं। जिस ढंग से बजट पेश किया गया है इसमें सब चीजों के अन्दर कटौती की गयी है जिससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार ने इस बजट में खासकर किसानों के साथ–साथ दूसरे वर्गों का भी ध्यान नहीं रखा है। इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (सढौरा) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्पीकर सर, हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इस अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए एक बहुत बढिया बजट पेश किया है। जिसमें हर पहलू पर विचार किया गया है। जिस प्रकार से सैंटर में एक बिल में 101 अमैंडमैंट्स के माध्यम से रेल बजट व आम बजट को मर्ज करके, एक साथ पेश करने का काम किया गया है उसकी वजह से वर्तमान वर्ष एक अनूठे वर्ष के रूप में जाना जायेगा तथा इसी प्रकार माननीय वित्त मंत्री जी ने हर मद को ध्यान में रखकर जो वित्त वर्ष 2017–18 के लिए बजट पेश किया है वह भी काबिले–तारीफ है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बढिया बजट पेश करके समस्त हरियाणा प्रदेश व इसके सभी क्षेत्रों व विभागों के लिए रास्ते खोले हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक–एक मद पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो 5.7 प्रतिशत जी.डी.पी. वर्ष 2014–15 में थी, वह वर्ष 2015–16 में 9 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में जो जी.डी.पी 8.7 प्रतिशत थी उसके वर्ष 2017–18 में 9 प्रतिशत रहने की संभावना है। पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जी.डी.पी दर कभी भी 9 प्रतिशत तक नहीं पहुंची। वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 4 प्रतिशत थी और आल इंडिया स्तर पर यह 5.18 प्रतिशत के करीब थी। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी के प्रयत्नों से हरियाणा प्रदेश की पर कैपिटा इनकम वर्ष 2015–16 में 7.5 प्रतिशत पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी शासित केन्द्र सरकार के प्रयत्नों से पर कैपिटा इन्कम 6.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुकी है और वर्ष 2016–17 में इसके 7.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है

जो कि बहुत बढिया बात है। हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में पेश हुए बजट में एग्रीकल्चर, शिक्षा, रोडज, बिजली के क्षेत्र में 102329.35 करोड़ रूपये के आंकड़े को छू दिया है। यह बजट पिछले वित्त वर्ष 2016–17 के बजट की तुलना में 13.18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह पहली बार हुआ है जब कि बजट में हर मद को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में 10,000 से ऊपर तक की आबादी के गांवों को नगरीय सुविधाएं देने का काम किया है। वर्ष 2017–2018 में 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले गांवों की भी उनके विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपया 3 साल के लिए फिक्स किया गया है। इस साल 1200 करोड़ रुपये से लगभग 1500 गांवों का आर्थिक विकास होगा और उनमें वे सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जो पहले कभी शहर में हुआ करती थी। कृषि के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2015–2016 में जो विकास दर 3.2 प्रतिशत थी उसमें वित्त वर्ष 2016–2017 में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017–2018 के बजट में इस क्षेत्र के लिए 3206.1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2016–2017 में 2698.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2017–2018 में इसमें 18.79 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी के साथ–साथ पशुपालन के लिए 1516.1 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 746.88 करोड़ रुपए और वृक्षारोपण के लिए 396 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सरकार का लक्ष्य हर खेत को पानी देने का है और जिस तरह चर्चा के दौरान एस.वाई.एल नहर का पानी टेल तक पहुंचाने की बात आई, उसको ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2016–2017 में 2397 करोड़ रुपए में 13.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए वित्त वर्ष 2017–2018 में 2724.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास योजना के तहत 10 हजार आबादी से ऊपर वाले गांवों को एक नगर का दर्जा व नगरीय सुविधाएं देने के लिए वित्त वर्ष 2017–2018 के बजट में 4963.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल ग्रामीण विकास योजना के लिए 3160.55 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56.69 प्रतिशत अधिक राशि रखी गई है। इसी तरह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के नाम पर जिला हॉस्पिटल खोलने की बात हो या पी.एच.सी को बड़ा करने की बात हो, इसके लिए पूर्व में प्रावधान किए गए 3323.95 करोड़ रुपए के खर्चे में 15.49 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह अपने आप में यह दर्शाती है कि

माननीय वित्त मंत्री जी ने समस्त हरियाणा प्रदेश, यहां पर रहने वाले समाज के सभी वर्गों व हर क्षेत्र के लिए नई पहल की है। वर्तमान बजट में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए 14005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि पिछले साल की तुलना में 18.43 प्रतिशत ज्यादा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्तमान बजट में कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग लेने के लिए 487.39 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जहां तक स्पोर्टस की बात है सरकार ने ऑलम्पिक में स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपए का इनाम, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए का इनाम और कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ रुपए का इनाम नियत किया है, जबकि पहले कभी भी किसी सरकार में इतनी बड़ी अमाउंट विजेता खिलाड़ियों के लिए नहीं रखी गई थी। पहली बार हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा इनाम, कागजों व बजट में ही न रखकर हकीकत में देने का काम किया है। हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया है और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों से जो वायदा किया था वह पूरा किया है । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि युवा सक्षम योजना के तहत पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को काम देने का प्रावधान भी किया गया है और उस काम के बदले उन्हें 6000 रुपये महीना अतिरिक्त दिए जायेंगे । इस तरह से उन्हें 3000 जमा 6000 टोटल 9000 रुपये प्रति महीना दिया जायेगा । एक अप्रैल से युवा सक्षम योजना में ग्रेजुएट लोगों को भी जोड़ने का प्रावधान किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरूक्षेत्र जिलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और इन जिलों को इस तरह से समझा गया जैसे ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं हैं । पिछली सरकार के समय में हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब थी लेकिन अब हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह जी ने पूरे प्रदेश में सड़कों को ठीक करवाया है । आज हमारे क्षेत्र में प्रत्येक सड़क बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है । आज हमारे क्षेत्र में 86 कि.मी. सड़कों का मजतीकरण और चौड़ाई का कार्य करने के लिए माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट में 47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसी तरह से ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने के लिए भी बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के क्षेत्र में सुधार करने की बात आती है तो इसके लिए वर्ष 2017–18 के लिए 3382.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले साल के

मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है । इसी तरह से परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिए वर्ष 2017–18 में 2459.70 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 7.35 प्रतिशत अधिक है । इसी तरह से शहरी विकास के लिए वर्ष 2017–18 के लिए 4973.58 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 45.93 प्रतिशत अधिक है । यही वजह है कि आज चारों तरफ बजट की सराहना हो रही है । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की कुछ बातें रखना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है । हिमाचल सरकार ने कालेअंब के अंदर बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है । हमारे क्षेत्र के 5–6 हजार बच्चे वहां इण्डस्ट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं । मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि कालेअंब की तर्ज पर झण्डकवाला गांव में इण्डस्ट्रीयल हब बनाया जाये ताकि वहां पर हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके । झण्डेवाला गांव के पास 3–4 गांवों की हजारों एकड़ जमीन है जिसको पंचायत देने के लिए भी तैयार है इसलिए वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया अवश्य बनाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरस्वती नगर से रादौर और बिलासपुर 20–20 कि.मी. की दूरी पर हैं । सरस्वती नगर में कोई भी सरकारी कालेज नहीं है । मेरी वित्तमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सरस्वती नगर में सरकारी कालेज बनाया जाये ताकि वहां के बच्चों को हायर शिक्षा लेने के लिए दूर न जाना पड़े । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अंबाला से यमुनानगर हाई–वे पर कोई गैस्ट हाउस नहीं है । वहां पर छप्पर गांव में ब्लोक समिति की 7–8 एकड़ जमीन भी खाली पड़ी है और ब्लोक समिति वह जमीन गैस्ट हाउस के लिए देने को भी तैयार है । इसलिए वहां पर गैस्ट हाउस बनवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व विधायक रामफल चिड़ाना जी सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्पीकर गैलरी में उपस्थित हैं । मैं पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं ।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री घन श्याम दास (यमुनानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट प्रस्तावों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का समय दिया इसके लिए इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2017–18 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। आज तक जितने भी बजट यहां पर प्रस्तुत हुए हैं उन सभी बजट प्रस्तावों में इस बार का जो बजट प्रस्ताव है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है। इस बजट में एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में किया गया है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश को चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के साथ ही साथ सदन में खींच–तान का जो वातावरण यदा–कदा बनता रहता है उसके बारे में भी कुछ शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं और वह यह कि हम सभी इस सदन को महान सदन कहते हैं। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह सदन निसंदेह महान है भी परन्तु इसी के साथ ही साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे विपक्ष के अधिकतर सीनियर माननीय सदस्यों का व्यवहार है क्या उससे सदन की महानता, सदन की गरिमा, सदन की परम्परा, सदन के अनुशासन और सदन की व्यवस्था परिरक्षित होती है या नहीं? यह हम सभी के आत्म–अवलोकन और आत्म–विश्लेषण का विषय है क्योंकि आम तौर यही कहा जाता है और जो कि वास्तव में सत्य भी है कि आप किसी में भी कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं परन्तु यदि आप अपने आप में सुधार कर लेंगे और परिवर्तन कर लेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रदेश, समाज और राष्ट्र के प्रति आपका परम उपकार होगा। मैं आज के बजट प्रस्तावों की चर्चा के समय अपनी सभी माननीय विधायकों से यह प्रार्थना करना चाहूंगा अर्थात यह निवेदन करना चाहूंगा कि समय बहुत अमूल्य होता है इसलिए उसके एक–एक क्षण का प्रयोग प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए और प्रदेश के विकास के लिए होने वाली चर्चा के लिए होना चाहिए ताकि हम अपने प्रदेश व देश की तरक्की करने में अपना सर्वाधिक योगदान देने के साथ ही साथ अपनी सोच का स्तर भी ऊपर उठा सकें परन्तु कई बार यहां यह देखने में आया है कि जो हमारे विपक्ष के सीनियर साथी हैं उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सभी से यह निवेदन है

कि हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें क्योंकि यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों का भी यह परम कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे उस सदन की गरिमा को बढ़ाने में अपना सर्वाधिक योगदान दें जिसको हम अपने शब्दों में महान कहते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं यह बात भी जोर देकर कहना चाहूंगा कि हमें इसे सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए अपितु शब्दों से आगे बढ़कर इस महान सदन को अपने व्यवहार से भी महान बनाने का ईमानदारीपूर्वक प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा बजट के बारे में चल रही है उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बजट बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही गहन चिंतन और मनन के बाद तैयार करके यहां पर पेश किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश ने जो अपनी चहुंमुखी तरक्की की स्पीड बनाई है अर्थात जिस प्रकार से आज हमारा हरियाणा प्रदेश चहुंमुखी तरक्की की ओर तेजी के साथ अग्रसर है उसका लाभ हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग बराबर–बराबर उठा रहा है अर्थात इस लाभ में सभी समान रूप से भागीदार हो रहे हैं। उदाहरणस्वरूप मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां पर हरियाणा प्रदेश के किसानों के बारे में बहुत चिंता व्यक्त की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है जो कि 320/– रूपये प्रति क्विंटल है। मैं यह बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि यह मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक है। इसकी प्रशंसा तो यहां पर किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं की। आलोचना करने वाले माननीय सदस्य आलोचना करते हुए इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि कृषि और किसान की ओर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात भी सच है कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जा रहा है अब तक किसी भी सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। किसानों के हित को ही ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कृषि ही नहीं बल्कि उद्योगों की तरफ भी सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। यमुनानगर के बारे में बड़े गर्व के साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि यमुनानगर जिला विशेष रूप से बोर्ड और प्लाई के व्यवसाय का विश्वस्तरीय केन्द्र है। वहां के इस उद्योग से सम्बंधित उद्योगपति और जनता बड़े लम्बे समय से यह मांग कर रहे थे कि जो बोर्ड–प्लाई उद्योग के

लाईसैंस पिछले अनेक वर्षों से बंद पड़े हैं उनको खोला जाये। जनता और उद्योगपतियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उचित निर्णय लेते हुए इन बोर्ड प्लाई व इससे सम्बंधित दूसरे लाईसैंसों के लिए ऑन–लाईन एप्लीकेशंज इनवाईट की है। इस प्रकार से ये लाईसैंस लोगों को देने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा किया गया है। इससे जो बोर्ड–प्लाई उद्योग में जो पॉप्लर और सफेदा प्रयोग होता है उनके मूल्यों में सुधार होगा। इसके साथ–साथ इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे जो यमुनानगर ने बोर्ड–प्लाई इण्डस्ट्री में जो अपनी विश्वस्तरीय पहचान बनाई है और उसको जो मान्यता मिली हुई है उस मान्यता को मज़बूत करने में मदद मिलेगी। ठीक इसके साथ–साथ ही जब हमारी सरकार आई थी तो पूरे प्रदेश में माइनिंग के लिए बहुत प्रतिबंध लगे हुये थे परन्तु 2 नम्बर में काम चलता था और कुछ माफिया किस्म के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में माफिया तंत्र को समाप्त किया गया तथा अवैध खनन को बंद किया गया और माइनिंग का काम शुरू होने से सारे प्रदेश के लोगों को उचित मूल्य पर रेत, बजरी मिलनी शुरू हुई । आज सारे प्रदेश में निर्माण के काम तीव्र गति से चल रहे हैं। इसी प्रकार से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बना इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, क्या कभी किसी ने सुना था कि बिजली के रेट कम हो सकते हैं शायद नहीं सुना और न ही कभी बिजली के रेट कम हुये परन्तु हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिजली की दरों को कम करने का जो निर्णय लिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। अध्यक्ष महोदय, आज विकास के काम न केवल हो रहे हैं बल्कि तीव्र गति से हो रहे हैं तथा सारे हरियाणा में हो रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने समान रूप से सारे हरियाणा का प्रवास करते हुये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है परन्तु फिर भी अपने–अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनकी चर्चा सदन में होनी अत्यावश्यक होती है । जिस प्रकार से सरकार की कि हर जिले में एक मेडीकल कॉलेज खोलने की योजना थी तो मैं भी आज इस बजट प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यमुनानगर जिला मुख्यालय पर एक मेडीकल कॉलेज खोला जाये । वहां पर मेडीकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है । इसी प्रकार से यमुनानगर में सरकारी कॉलेज खोलने की भी व्यवस्था की जाये । वैसे यमुनानगर में प्राइवेट

कॉलेजिज तो बहुत हैं लेकिन एक सामान्य व्यक्ति वहां पर प्रवेश पाने और वहां की फीस का भुगतान करने में कठिनाई अनुभव करता है इसलिए यमुनानगर में एक सरकारी कॉलेज चाहे वह सिर्फ लड़कियों के लिए हो या सहशिक्षा वाला हो, खोलना अत्यावश्यक है । अध्यक्ष महोदय, जैसे हम सभी सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं उसी तरह से मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं । स्वास्थ्य विभाग हमेशा चर्चा में रहने वाला विभाग है । स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में जो सामान्य नागरिक अस्पताल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में एक 100 बिस्तर का अस्पताल है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस अस्पताल को अपग्रेड करके 200 बिस्तर का किया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें । यमुनानगर जिला पिछले 15 सालों से उपेक्षित रहा है तथा उस समय सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी । हमारे लोक निर्माण मंत्री यहां पर बैठे हैं मैं बताना चाहूंगा कि आज यमुनानगर जिले में बड़ी व्यवस्थित सड़कें बन चुकी हैं परन्तु जो थोड़ा बहुत काम बाकी है अगर वह भी पूरा हो जायेगा तो निशिचित रुप से सरकार जो प्रदेश की जनता को सकारात्मक सन्देश देना चाहती है, वह जायेगा । पिछली बार लोक निर्माण मंत्री की तरफ से सदन में एक प्रोफार्मा दिया गया था कि हर सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र की 5–5 सड़कें लिख कर दे दे ताकि वे बनाई जा सकें । मैं देख रहा हूं कि एक सप्ताह बीत चुका है लेकिन इस बार अभी तक वह प्रोफार्मा नहीं दिया गया है ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वह प्रोफार्मा तैयार है और आज ही दे दिया जायेगा ।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । इसका मतलब यह है कि मैं इसका श्रेय ले सकता हूं कि मेरे कहने पर मंत्री जी ने वह प्रोफार्मा जारी करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी काम हो रहे हैं निश्चित रुप से हरियाणा को भारतवर्ष में एक अग्रणी प्रदेश बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने बिजली सस्ती की है परन्तु बिजली की सप्लाई सुचारू रुप से चल सके इसलिए यमुनानगर में ग्रामीण क्षेत्र में शादीपुर में एक 33 के.वी.ए. का सब–स्टेशन लगाया जाये । अगर यह सब–स्टेशन बन जायेगा तो आंधी–तूफान, वर्षा और बिजली की लाइनें लम्बी होने के कारण

बिजली की सप्लाई में व्यवधान पड़ता है उस व्यवधान को रोकने में सफलता मिल सकती है । यदि सरकार इस काम को करेगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हरियाणा भारत वर्ष के अग्रणी प्रदेशों में से एक है उसी तरह यमुनानगर जिला भी प्रदेश के जिलों में से एक अग्रणी जिला बनने में सफल होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017 दोपहर 2 बजकर 30 मिनट (द्वितीय बैठक) तक के लिये *स्थगित किया जाता है ।

*13:51 बजे

(तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017 दोपहर 2 बजकर 30 मिनट (द्वितीय बैठक)तक के लिये *स्थगित हुई ।)